साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

वर्ष 11 अंक 11 | प्रति सोमवार इंदौर, 24 से 30 अक्टूबर 2016 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2/- रुपए

नौटंकीबाज मोदी, पाकी 40 वर्षों से देश में घुसकर मार रहे

27 सितम्बर के पूर्व व पश्चात का इतिहास देखो, राष्ट्र प्रेम नहीं, पाखंडी नेता

इसरायल की तरह 1 के बदले 10 पाकिस्तान में घुसकर मारो, हर दिन

चीन से डरने की नहीं उसकी घटिया चालों, माल, जासूसी की पूरी दुनिया में बदनामी कर अर्थव्यवस्था चौपट करो

देश के लघु उद्योगों, तकनीकी इकाइयां विकसित कर पूरा चीनी आयात बंद कर दो

भारत की धरती पर मोदी जैसा नौटंकीबाज नेताओं प्रधानमंत्री इतिहास से नहीं पढ़ा। इसी झूठी वादेबाजी के दम पर, देश की जनता के मीडिया के भ्रष्ट जालसाज भुखेरे भेड़ियों ने भ्रमित कर भले ही चुनाव जितना दिया हो, पर आते ही उसने जनता के पैसे की कैसे विश्व भ्रमण में रुपए 50 लाख करोड़ से ज्यादा की धज्जियां बिखेरी समय माया के इस कटु सत्य की सच्चाई को विकीलिक्स ने अमेरिकी प्रशासन की मोटा धन हजम कर सफल बनाई गई रैलियों और सभाओं का सच ईमेल पकड़कर स्पष्ट कर दिया, यही हाल ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, आस्ट्रेलिया चीन में भी हुआ। जहां जनता को रुपए 20-30 का पेट्रोल रुपए 72-75 बैचकर जनता से नोचे धन से अपनी वाहवाही और ताली ठुकवाने में लाखों करोड़ उड़ाये गये, बदले में जनता को राशन के गेहूं में कटौती,स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा गैस, विद्युत मोबाइल काल दरों, रेल किरायों में भारी बढ़ोत्री कर लूटा जा रहा है। कटौती की गई कृषि अनुदान, महिला बाल विकास, ग्रामीण विकास, सड़कों, जल आपूर्ति के बजट में भारी चुनाव पूर्व घोषणाएं की गई थी, महंगाई समाप्त, आतंकवाद समाप्त, भ्रष्टाचार सब 100 दिन में खत्म कर दिया जायेगा, यह तो स्पष्ट था कि भुखेरा जनहित भक्षी सत्ता में आते ही गिद्धों की तरह नोंच-खसोंट में जुट, वास्तविक आवश्यकता और कार्यों को बलाये ताक रख, सत्ता सुख भोगने में जुटी रहेगी, हुआ भी वही,मिडिया की 17 से ज्यादा चैनलों को अंबानी पूंजी राक्षसों ने अपने आधिपत्य में लेकर केवल मोदी की भांडगिरी कर रहे हैं।

जबकि 27 सितम्बर 16 को सर्जिकल स्ट्राइक कर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया जो कार्य ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रोज होना चाहिए वह यदि 40 वर्ष में एक बार कर भी दिया तो क्या वह लकड़बाघे माने, 27 सितम्बर 16 के बाद सौपिया, पंपोर, कठोल आदि में घुसकर नियमित हमले कर रोज 2-4 सैनिकों पुलिसवालों को मार रहे हैं। हमारे देश में घुसे आतंकियों को मार भी डाला तो क्या? बदले में हमारा कितना नुकसान हुआ के साथ शत्रु को शत्रु की भाषा में जवाब देने के लिए हमे इजराइल की तरह उनके घर में घुसकर न केवल पाक अधिकृत काश्मीर छुड़ाने के साथ पूरे पाकिस्तान की 200-250 किमी तक अंदर हर दिन 100-200 टपकायें तो माना जाय कि 56 इंच सीना सच ही दमदार है। बेशक ये सीधा युद्ध होगा इसके विपरीत नौटंकीबाज मोदी इस छोटी सी घटना का जिस प्रकार प्रचार-प्रसार कर अपने आपको महानायक सिद्ध करने पर तुला हुआ था, खलनायक सिद्ध हुआ, बेशक हमारे दूसरे राजनीतिज्ञ यथार्थ का चित्रण करने की अपेक्षा, अपनी नीच, ओछी और घटिया राजनीति पर उतरकर शत्रु की भाषा बोल अपनी राष्ट्रद्रोही मानसिकता का जो परिचय दिग्गी, पप्पु, खेजरीदाल ने दिया बेशक ऐसे ईषालु विपक्ष में ढेरों है। जिसके बारे में लिखना निरर्थक है। (शेष 8 पर)

संकरवर्णीय अमेरिका का मोदी पिछलग्गू बन कर रहा देश बर्बाद

पाक को अंध सहयोग-भारत का चीन के विरूद्ध बाजारू व सामरिक उपयोग

सैन्य अड्डों के उपयोग की सहमति, देश को पड़ेगी भारी, गोपनीय सूचनायें पाक को जायेगी सारी

भा.प्र.मं. मोदी का संकरवर्णी अमेरिका का पिछलागू बनना, उसकी व्यक्तिगत महत्वकांक्षा का हिस्सा है, जिसको मोदी अपना दोस्त समझ रहा है यथार्थ में मोदी स्वयं जानता है कि इसकी भारी कीमत चुका रहा है जिस विश्व व्यापारिक शोषण संगठन के इशारे पर ये मुखेरा हर शासकीय संपत्तियों, उद्योगों, सेवाओं को अपने आकाओं अडानी, अंबानी, टाटा,बिरला के साथ बहुराष्ट्रीय कं. यथा आईटीसी, युनिलीवर व संपत्तियों को लाखों करोड़ का कमीशन हजम कर सौंप रहा है या सौंपने पर चुना है। उनके इशारों पर ही जीएसटी में भी विपक्ष के सांसदों को रुपए 100 से 500 करोड़ में खरीद कर बहुमत से सफल करवाया वही हाल राज्य सभा को उनकी हैसियत के हिसाब से टुकड़ा डालकर खरीद कर पास करवाया और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के इंतजार में है, बिलकुल वैसे ही जैसे वालमार्ट ने 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्चकर, साथ में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ने साथ में विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. यथा आईटीसी, युनिलीवर, मेक्डॉनल्ड, डोमीनोज, आदि रुपए 10,000 करोड़ से रुपए 1 लाख करोड़ खर्च कर और सांसदों को रुपए 500 करोड़ से 5000 करोड़ में पद और हैसियत के हिसाब से खरीदकर भा. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 को बाले ही पास करवा लिया था जिसकी सबसे पहली व्याख्या समय माया ने कर उसे अधिनियम की 5 वर्ष लागू नहीं होने दिया अन्यथा पूरे खाद्य बाजार पर देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. का कब्जा होता और लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार होते और पूरी कृषि भूमि पर अभी तक उनका ही कब्जा होता। जीएसटी के पास होने के बाद अमेरिका संकर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसलिए जीएसटी पास करवाने के लिए मोदी की प्रशंसा में कसीदे पड़े क्योंकि उसकी कमाई में अमेरिकी कं. के जो अरबों डॉलर के जो लाभ होगा वो अमेरिका प्रशासन के करो के रूप में प्राप्त होगा। (शेष 8 पर)

सबसे ज्यादा कालाधन उच्चाधिकारियों के पास

मंत्रियों, नेताओं और उद्योगपतियों पर आयकर क्यों नहीं मारता छापे

आई.ए.एस., आईपीएस, आईएएस सबसे भ्रष्ट, जालसाज देश के सफेद पोश सबसे बड़े सरकारी डकैत, सबसे ज्यादा बेनामी संपत्ति के मालिक, सत्ता के सूत्रधार, सबसे बड़े हवाला कारोबारी

भारत की सत्ता के सबसे बड़े सत्ता के सूत्रधार होते हैं। आईएस अर्थात इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी, जो राष्ट्रपति भवन से लेकर, जिले के प्रशासन की सबसे अंतिम ईकाई जिला पंचायतों में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी और तहसीलों में भी सहा. या उप जिलाधीश और उपजिला दंडाधिकारी के पदों पर विराजमान रहते हैं। सत्ताधीश समझे जाने वाले प्रधानमंत्री के मंत्रियों, राज्यों के मुखमंत्रियों से लेकर सभी मंत्रियों तक जिले के सांसदों, विधायकों से लेकर जिला पंचायत, अध्यक्षों, जनपद से ग्राम पंचायत, नगर निगमों, पालिकाओं, परिषदों, तक सारे जनप्रतिनिधि जो जनता से चुनकर इन संस्थाओं में भेजे जाते है। सबको हांकना, चलाना और बताना समझाना और फिर मनचाही पुस्तिका, आदेशों, ज्ञापन रोकड़ बही आदि दस्तावेजों पर अंगूठें या हस्ताक्षर करवाकर अरबों रुपए का धन का कुछ हिस्सा इन्हें बांटकर हड़प जाना इनके बाये हाथ का खेल है। ये सबसे बड़े कालेधन का हवाला व्यापारी है। ये लाख दो पांच लाख से हजारों करोड़ हजम करके डकार भी नहीं लेते, सबसे ज्यादा इन्हीं का कालाधन बड़ी भू-माफियाओं की बहुमंजिला इमारतों से लेकर, शेयर बाजार, प्रतिभूति, ऋणपत्रों से लेकर बेनामी संपत्ति के प्रदेश में खुले 450 से ज्यादा इंजिनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, कॉलोनियों में, न केवल प्रदेश में, वरन् देश और देश के बाहर युरोप अनेकों देशों यथा इंग्लैंड, अमेरिका से लेकर पनामा, नार्वे, हॉलेंड, फ्रांस, कनाडा आदि देशों से लेकर एशियाई देशों में मॉरीशस, थाईलैंड, खाड़ी देशों में फैला पड़ा है। यही हाल इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस अर्थात आयपीएस, इंडियन फॉरेस्ट इटिंग सर्विसेज अर्थात आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट, इटिंग सर्विसेज अर्थात आईएफएस इंडियन रेवेन्यु चीटिंग सर्विसेज अर्थात आईआरएस जो कस्टम एंड एक्साइज, आयकर अधिकारियों का भी है। (शेष पृष्ठ 8 पर)

रा.स्व.स. सिद्धांतहीन, सत्ता लोलुपों की फौज पूंजीपतियों की कठपुतली

सत्ता के मद में भूल गए हिन्दुत्व, स्वदेशी, बुला रहे गुलामी

100 प्रश सीधा विदेशी निवेश, सौंप देंगे, जर, जमीन, खेत-खलिहान, आकाश, बिजली, पानी, सड़कें विदेशियों को देश की धरती पर देशी लोग करेंगे विदेशियों की गुलामी, मोदी 40 करोड़ को बना देगा भिखारी

मोदी ने प्रसार माध्यमों और इंटरनेट साइटों को जिसमें ट्वीटर, फेसबुक जैसे पर लाखों करोड़ लुटाकर जनता को जो सब्जबाग दिखाकर और जालसाज महानिकम्मी देश को हांकने वाली सरकारी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों की फौज को खरीदकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जालसाजी से सत्ता हथियाई थी। उससे तो यह स्पष्ट हो ही चुका था कि ये नीच दैत्य पूरे देश को अपनी मौज मस्ती और विश्व भ्रमण के शौक में बर्बाद कर देगा, अपनी कमाई और मोटे कमीशन, ताकि उसकी विदेश यात्राओं में धन की कमी आड़े न आने पाए और देश की जनता उसे गाली न बके, उसने राष्ट्र के खाद्य व्यवसाय को भी सीधे 100 प्रश विदेशी डकैतों, बत्तमीज जालसाज कं. जिसमें वालमार्ट, डोमिनो व अन्य कं. सीधे ही किसानों के खेतों खलिहानों को गिरवी रख या पट्टे पर लेकर सीधे ही कृषि उत्पादों की पैदावार को अपने कब्जे में रख मनमानी किमतों पर बेचेंगे, असली खेत मालिक, अपने ही खेत पर साल दो साल मजदूरी करेगा बाद में षड़यंत्रों से उसकी हत्या, कानूनी जालसाजियों से जमीन हथिया ली जाएगी। इस प्रकार देश के 20 करोड़ कृषकों और कृषि मजदूरों को भूखा मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जायेगा क्योंकि वो दो वक्त रोटी खाने लायक भी धन नहीं कमा पायेगा, साथ ही खाद्य पदार्थों से जुड़े व्यवसायियों, उद्योगों से लेकर, 10 करोड़ से ज्यादा सब्जी विक्रेता, ठेले, दुकानदारों को ये विदेशी कं. बेरोजगार कर देगी या खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 में उलझाकर उन्हें रोजगार से वंचित कर देगी, इस प्रकार सन् 2020 तक 40 करोड़ भिखारियों अपराधियों का देश बन जायेगा, तब समझ आयेगी नीच राक्षस मोदी के इस फैंसले का असर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जब तक विपक्ष में रहता था, तभी तक इसकी हिंदुत्व व राष्ट्रभक्ति का दिखावा चलता है।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

भूमाफियाओं के इशारे पर नाच रहा प्र.मं. से जिला प्रशासन तक

स्मार्ट सिटी के नाम केवल लूट और तबाही

शिगूफों और सपनों के सहारे की जा रही जन-धन की बर्बादी, जानकारी मांगने पर जालसाज हरामखोरों की फौज बहाने ढूंढती है

मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मंत्रियों, प्रशासनिक अधिकारियों, से लेकर सांसदों, विधायकों, पार्षदों, पंचों, सरपंचों, महापौरों आदि के जरूर बहुत अच्छे दिन आ गए, अभी तक इन्हें भ्रष्टाचारी, जालसाज, हरामखोर, भूमाफियाओं की श्रेणी में रखा जाता था। अब ये जालसाजी से हथियाई सत्ता के मुखेरे जनहित पार्टी का सपनों का सब्जबाग दिखाकर पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन हजमकर स्वयं लूटने और लुटाने वाला गिरोह बन चुकी है।

मोदी के सत्ता में आने के बाद न केवल भ्रष्टाचार चारों तरफ बढ़ा यहां तक कि ये धूर्त गिद्ध अपना मोटा कमीशन नोंचकर अपने आकाओं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला व अन्य को विक्रयकर, आयकर, कस्टम व एक्साइज में छूट देने के साथ सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के साथ सरकारी बैंकों में जमा धन में से भी इन्होंने पूंजीपतियों के साथ ही किसानों से जमीनें छीनकर, बसी हुई बस्तियों को उजाड़कर जमीने बहुराष्ट्रीय कं., भूमाफियाओं को उपलब्ध करवाने का षड़यंत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से चलकर, मुख्यमंत्रियों, नगरनिगमों, जिलाधीशों के कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों तक फैला हुआ चल रहा है। इस जनता को लूटने के कारोबार में भूमाफियाओं के साथ पटवारियों, नायब तहसीलदारों, सहा. उप जिलाधीशों से लेकर संभागायुक्तों, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री तक सबकी भूमिकायें कानूनों को ताक पर रखकर लूटने खाने की है। स्मार्ट सिटी इसी लूट और भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है। ताकि सब धूर्तों की कमाई होती रहे, इनकी धूर्तता, मक्कारी और लूट का यथार्थ इससे ही स्पष्ट होता है कि इन हरामखोरों निगमायुक्त मनीष सिंग जिलाधीश पी. नरहरि यदि सत्ता संपन्न है, तो जिस काननू के अंतर्गत कानूनों का पालन करने पदों पर बैठे है, तो 50 वर्षों से ज्यादा पुरानी बस्ती के रहवासियों को इतना भी हक नहीं कि ये शूकर कम से कम 6 माह का समय देकर उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करने की सूचना दे दें। आखिर इन धूर्त गिद्धों को नहीं दिखता कि वो भी इंसान है, जंगल के वनैले नहीं जिन्हें कहीं भी, कभी भी कैसे भी खदेड़ दो, उनके वैध आशियाने केवल अपने पद का रौब झाड़ते हुए बिना बताये इसलिए ही तोड़े गये, आखिर उन सड़कों की 200 फुट चौड़ाई बढ़ाकर क्यों वहां बोइंग, या मिलिट्री के युद्धक विमान उतारने है। इसके विपरीत केवल अपनी बहादुरी सत्ता का रौब झाड़ने, उसकी आड़ में अपने मनपसंद ठेकेदारों से बिना टेंडर जारी किए अरबों रुपए की सड़क के ठेके बिना डीपीआर बताये ही 30 से 50 प्रतिशत कमीशन पर कुछ टुकड़े पार्षदों, विधायकों, महापौर को डालकर मात्र स्मार्ट सिटी के नाम प्राप्त अरबों रुपए के आवंटन का उपयोग दिखाकर हजम करने के लिए था, फिर पुरानी बस्तियों की तोड़फोड़ नहीं करेंगे तो इन धूर्त गिद्धों को चंद वर्षों के लिए यहां कलेक्टर, कमिश्नर बनकर पदस्थ हुए है। तो नाम की गरिमा के अनुकूल कैसे अवैध धन का कलेक्शन करेंगे और बड़े-बड़े ठेके देकर कमीशन खायेंगे, जिन हरामखोर जालसाजों के मस्तिष्क में ईमानदारी से सूचना के अधिकार में दी गई अपीलों का निर्णय देने और अपनी जान जोखिम में डाल आवेदक को जानकारी दिलवाने जैसे छोटे काम की क्षमता नहीं, उनसे फिर बड़े-बड़े कामों में तो ईमानदारी तो दूर इस पद पर बैठे शूकरों से तो बेईमानी में भी ये देखना चाहिए, किस हद तक ये बेईमानी के किस उच्चतम शिखर को छू सकता है, अपनी लूट के लिए किस हद तक कितनी तबाही मचाकर कितनी बस्तियों को उजाड़ ये आतंकवादियों से ज्यादा बर्बादीकर सकता है, वैसे भी निगमायुक्त मनीष सिंह वल्द मोतीसिंह ये उसी बाप का बेटा है जिसके बाप मोतीसिंग ने जिस गैस कांड के समय भोपाल में हजारों लाशे बिखरी पड़ी थी, लाखों लोग करहा रहे थे, उस समय मोती सिंह जो भोपाल का एसडीएम था,मोटी सौदेबाजी कर अपनी जीप में एंडरसन को बैठाकर भोपाल हवाई अड्डे ले गया जो वहां से बाद में अमेरिका भाग गया। अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर कैसी स्मार्ट सिटी बनाए गए। बीआरटीएस की तरह भविष्य बताएगा स्मार्ट सिटी केवल धन हड़पने का बहाना है।

जिसकी लाठी भैंस वही दुह ले जायेगा, लोक तंत्र बनाम लूट तंत्र

जब तक सवर्ण, शक्ति का अहसास नहीं करायेंगे, जानवरों से हांके जायेंगे

सहस्त्रों वर्षों की गुलामी से सबक नहीं सीखा- इसलिए करो और झेलों सत्ताधीशों का आतंक, सत्ता के भुखेरे स्वर्ण विधायक 55 प्रश होने के बाद भी रौंद रहे अपनी ही समाज को

भारत विश्व में अनादिकाल से अनादिकाल तक जिस दैविक और दैहिक ज्ञान का केन्द्र रहा है, और अपने पूर्वजों की संचित दैनिक ज्ञान की संपदा का अनादिकाल तक स्वयं और विश्व उपयोग करेगा, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता रहेगा क्योंकि दैनिक अनादि से अनादि तक स्थापित रहेगी बेशक उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। जबकि दैहिक और भौतिक प्रगति अवनित सब क्षणिक रहेगा, क्योंकि भौतिकवाद तात्कालिक, प्रसन्नता और आनंदामृति दे सकता है, पर दीर्घकालिन आत्मीय सुख दैविक ज्ञान और उपासना से ही मिल सकता है। जिसके बारे में हमारे ऋषियों मुनियों ने विराट संपत्ति वेदों, उपनिषदों, पुराणों में संचित है। इसी ज्ञान ने भारत को पूरे विश्व में एक तरफ श्रेष्ठता प्रदान की तो दूसरी तरफ हमारी सहस्त्रों वर्षों की गुलामी का कारण भी रहा और वर्तमान में भी है। इसी पद्धति में जो हमारे देश में वर्णवाद या जाति प्रथा का सामाजिक ताना बाना रहा, उसके चलते स्वाभिमान और न राष्ट्रभक्ति का नामो निशान जागृत नहीं हुआ और सब ऊंच-नीच के अंतर में उलझ आक्रांताओं का स्वागत करते रहे, मात्र एक-दूसरे को नीचा दिखाने में और आक्रांता विदेशी इन्हीं सब का लाभ उठाकर इस श्रेष्ठ ज्ञानी धानियों और ऋषि मुनियों के देश पर राज करते रहे। आज भी हालात जस के तस है। बस वर्तमान में इतना सा अंतर आया है कि इन अंग्रेज जालसाज अंग्रेजों द्वारा जो भारत की सत्ता का 99 वर्ष के पट्टे पर किया गया हस्तांतरण जिन धूर्त महामक्कार वकीलों मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मो. अली जिन्ना को किया गया थ, उसमें से जिन्ना पाकिस्तान लेकर अलग हो गया, स्व. मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्ता में भागीदारी से मना कर दिया, स्व. नेहरू ने कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालकर उसके स्थाई रूप देने के लिए जातिगत आधार पर बांटने के लिए ताकि वो दीर्घकाल तक सत्ता में जमे रहे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत पर फूट डालो और जाते समय भी 99 वर्ष के पट्टे पर अनुबंध करवाकर, सत्ता का हस्तांतरण किया, जैसा कि अंग्रेज जानते थे कि उनका शासन ब्राह्मण, बनिये, राजपूतों जो कि ज्ञानी ध्यानी है, वो अन्य सभी हिन्दुओं के साथ रख अपने को शासन नहीं करने देंगे इसलिए उन्होंने भी मुस्लिमों को कभी शह देकर तो कभी मात देकर बहुसंख्यक हिन्दुओं से लड़वाकर, दूसरी तरफ छल, बल धन और दल से हिन्दुओं को धर्म परिवर्तन करवा कर ईसाई बनाकर अपने समर्थकों, जिसमें धर्म, भाषा को भी बदल दिया गया ताकि दीर्घकाल तक उनके समर्थक उनका गुणगान करते हुए उनके अस्तित्व का बखान करते रहे। वो अपनी हर चाल में सफल रहे, उन्हीं के पदचिन्हों पर चल कांग्रेस ने भी जो श्रेष्ठ समझते थे उनसे छीनकर कानून के नाम पर निम्न वर्ग बताकर, उन्हें अपने अधीन बनाये रखने और सत्ता को स्थापित किये रखने हेतु भिक्षुक बना कर रखा ताकि वे मुफ्त की सेवाओं के लाभ पाने की खातिर उन्हें अपना मतदान आंख भींचकर करते रहें। दूसरी ओर वनों में निवास करने वाली स्वाभिमानी आदिवासियों को बांटकर सुविधा भोगी रसास्वादन करवा दिया। ताकि वे दोनों ही कभी स्वाभिमानी न बने और श्रेष्ठतम प्राप्त कर सके। इसलिए उन्हें सत्ता की खातिर दिए गए आरक्षण के आधार पर सत्ता बनी रहे। इसलिए 10 वर्ष के लिए दिया गये आरक्षण को हर दस वर्ष समाप्त होने के पूर्व ही अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते-बढ़ाते 60 वर्ष गुजर गए, इसलिए आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा रहा। जबकि आदिवासी और अनु. जाति में जो लाभ ले चुके अब उनकी ही पीढ़िया उस आरक्षण का लाभ लेकर उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगी, पर यथार्थ में उस 14 प्रश के भी 5 प्रश को जो लाभ मिल चुका है वे ही व उनकी पीढ़ियां ही उस लाभ का भरपूर आनंद ले रही है। बाकी अनु. जाति व जनजाति के अन्य व्यक्ति जहां था, जैसा है, 60 प्रश 70 वर्षों में उन पर खर्च किया पैसा, वहां के अधिकारियों की जेब में सीधा ही प्राप्ति हो गई, यथार्थ में सामान्य जन से लूटे गए धन से अनुदानों, छात्रवृत्तियों और विकास के नाम से जो धन लूटा व लुटवाया जा रहा है। उसका मात्र उद्देश्य भिक्षादान कर केवल अपने वोट बैंक मजबूत करने के लिए उन्हें संघर्ष और स्वाभिमान से जीने योग्य नहीं बनने देना है। दूसरी ओर विभिन्न विभागों में शीर्ष पर जानबूझकर आरक्षण की आड़ में ऐसे लोगों को स्थापित करना है,जो इनके इशारों पर नाचकर कानूनों को बलाये ताक रखकर खूब भ्रष्टाचार करें ताकि इन्हें मनचाही कमाई होती रहे, संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए समानता के आधार और योग्यता के कारण सामान्य वर्ग को पदोन्नत कर शीर्ष पर बैठा दिया गया तो सामान्य वर्ग एक सीमा के बाद कानून के भय ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की जालसाजियों से सत्ता में बैठे मु.मं. मंत्री को भी कम धन ही दे पायेगा, इन हरामखोर जालसाज नेताओं, मंत्रियों, इंडियन एव्यूसिंग सेवाओं के अधिकारियों को ऐसे लोग अधिकारी, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, बिल्कुल नहीं सुहाते जो गलत को गलत कहे और इच्छानुसार इन्हें उनकी पेटपूजा न चढ़ाये, सामान्य वर्ग का सामान्य बुद्धिजीवी भी हर गलत कार्य में तो इनकी हां में हां नहीं करेगा, इसलिए उनको ये हरामखोर उनके सामान्य पदोन्नति के अधिकारों से भी वंचित कर यथार्थ में घोर मानसिक सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना दे रहे हैं। जबकि ये भारतीय प्रशासनिक बनाम प्रताड़ना सेवायें भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा को हर तीन वर्ष में पदोन्नतियां, सुविधायें भी अधिकतम, लूट, डकैती, भ्रष्टाचार भी भरपूर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि सामान्य वर्ग के वैश्य, ब्राह्मणों और क्षत्रिय वर्ग की जातियों में हर स्तर पर बिखराव मात्र झूठे दंभ में जीने और अपने आप को घोर ज्ञानी ध्यानी होने को भ्रम में जीने के आदी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते और एक तरफ उनके लिए सब गधे, घोड़े, भेड़, बकरियां है। इस भ्रम में 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बाहर आकर इकट्ठे और एकजुट होने को तैयार नहीं है। जबकि इनका यही अहंकार रूपी इनका घोर भ्रम, हमारी सैकड़ों पीड़ियों की गुलामी और अरबों का मौत का कारण भी बना। इस बात को ये धूर्तों ने, जिसमें करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि थे ने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने शूद्रों के नाम पर अनुसूचित जातियां और आदिवासियों को सामान्य वर्ग से लूटे गए धन से को उनकी बेहतरी के नाम पर लूटना और लुटाना शुरू किया। जैसे इन हरामखोरों की बाप की जागीर हो। पर इसका मूल कारण था हमारा श्रेष्ठता का अहंकार बिखराव ही था, जिसका लाभ यवनों से लेकर मुगलों, फ्रांसीसी और अंगेजों से लेकर अब हमारे जालसाजी से चुने हुये हमारे अपने होने का ढोंग करने वाले भी भरपूर ले रहे है। जिसके पीछे वैश्य को धन का, ब्राह्मण को ज्ञान का क्षत्रियों को अपनी बहादुरी का घोर अहंकार है। अभी भी हिन्दुओं का आबादी का 78 प्रश होने के बाद भी, ये घोर स्वार्थी, दंभी अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे है। जिससे बात करो सारे हरामखोर दंभी कोई न कोई बहाना बनायेंगे, कभी उच्च न्यायालय में प्रकरण है, तो कभी सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण है। अभी ये त्यौहार है। इसको निकल जाने दो, अब नो त्यौहार है, इसको निकल जाने दो, फिर देखते हैं। इन सबकी जिंदगी इन बहानों में ही गुजर गई, न ये भुखेरे श्वानों की फौज अपना सोच पाई न अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहती है। ये सब जानते हैं, अनादि से अनादि तक जिसके हाथ में लाठी होती है। बल होता है, सत्ता की भैंस वही चराता, लूटता और लुटाता है। इन डरपोक भेड़ियों से गप्पे हंकवा लो, व्यर्थ की दलीलें दिलवा लो, जैसे ही एकजुट होकर आंदोलन की बात करो तो तिल-तिल मरने के लिए तैयार हैं। परंतु आंदोलन की बात सुनते ही कभी घर का रोना रोयेंगे तो कभी स्वास्थ्य का रोना रोयेंगे, तो कभी काम का, इनके इसी गुण का रसास्वदन आक्रांताओं से आतंकवादी तक और सत्ताधीश तक सभी भरपूर लेकर इन दंभी मूर्खों की जानवरों की तरह घोर शोषण करवाकर भी भेड़ों की तरह मिमियाकर जिंदगी गुजारने को भी अपनो भाग्य समझा जीवन यापन करने में ही अपने को महान समझ रहे है।

सामान्य वर्ग का शोषण शासकीय कार्यालयों में केवल पदोन्नतियों भर्तीयों और शिक्षा में ही नहीं कर रहे है। सत्ताधीश वरन सामान्य वर्ग का शोषण उसी के धन और मेहनत से हर कदम-कदम केवल वोटों की खातिर कर रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की वसूली हो, सड़के हो, बिजली, पानी अन्य सुविधायें सबसे ज्यादा भुगतान सामान्य वर्ग को ही करना होता है। पर ये सामान्य वर्ग अपनी महानता दंभ में अंधें गूंगे और बहरों की जमात बनकर जानवरों से बदत्तर हो गई, फिर ये शोषण करवाने को अपना भाग्य मानती है। पर जो आगे बढ़कर इनकी लड़ाई लड़ने और तन, मन, धन से सहयोग मांगते तो ये मट्ठों और ढीठों की फौज, वहां भी बहानों की फेरिस्त पेशकर दायें बायें होती है। जबकि वहीं आरक्षण के मुफ्त लाभ लेने वालों मात्र 20-22 प्रश जो 50 से 70 प्रश तक आरक्षण का लाभ ले रहे है। खूब जमकर जन-धन से चलाई जा रही योजनाओं में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार से लूटा गया धन भी आंदोलनों और संगठन में खर्च करने के साथ ही उच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों में भी साम, दाम, दंड, भेद के दम पर फैसले लटकाने, आगे बढ़ाने में भी सफल हो रहे है। फिर सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायाधीश कोई देवपुरूष तो नहीं आम आदमियों की तरह भय, भूख, काम, क्रोध, लालच, मद, मोह, माया में जकड़े हुए इंसान है। 8 आदमियों के हत्यारे सलमान को अरबों का धन हड़प जमानत स्वीकार कर सकता है। अपने दो फैसलों को पलट सकता है। उसे मालूम है कि सामान्य वर्ग यथार्थ में सामान्य वर्ग से भी गया बीता भ्रमितों का टोला हैं। कुछ नहीं करेगा।

सूचना अधिकार में जानकारी न देने भ्रष्टाचार बचाने, वा.कर में हर जानकारी तृतीय पक्ष की

वा.कर में अधिकारी घोर भ्रष्ट, कामचोर, मक्कार और बहानेबाज

सू.अ. में अपनी जालसाजियों और भ्रष्टाचार के दस्तावेज न देने, तृतीय पक्ष का बहाना लेकर, बचाती है, बेशक भ्रष्ट सभी हैं, जीएसटी का समयमाया द्वारा लिखा जा रहा था 8 वर्ष का सच सामने आया तो पूरे देश के विक्रय कर अधिकारी हड़ताल कर रहे है

मप्र वाणिज्यकर में भ्रष्टाचार के कारण विभाग के राजस्व की हानि करीब 70 प्रश होती है, क्योंकि अधिकांश अधिकारी 2-5प्रश लाभ के लिए शासन को 90-95 प्रश हानि को नहीं देखते, स्वाभाविक है कानूनों की आड़ में कानून का मजाक बना दोनों हाथ वसूली करते हैं।

वा.क. में नियम है कि सारे एंटी इवेजन ब्यूरो के छापों के समय वीडियोग्राफी करना है, परंतु आज तक वाणिज्य कर के भ्रष्ट आयुक्तों से लेकर, उपायुक्तों सहा. आयुक्त, वा.कर अधिकारी किसी ने भी कार्यालयीन स्तर पर इसका प्रयास नहीं किया, क्योंकि 96 प्रश छापों में 10 करोड़ की कर चोरी पकड़ी जाने पर 1 करोड़ दिखाई जाकर, दो करोड़ हजम कर रुपए 7 करोड़ बचवा दिए जाते हैं। यही हाल ट्रकों को पकड़ने शास्ति जमा करवाने में चलता है। यह इस विभाग की छोटी सी बानगी है, बेशक इस भ्रष्टाचार और जालसाजियों में हिस्सा आयुक्त, सचिव, प्र.स. मनोज श्रीवास्तव, मंत्री मलैया से चलकर यथा योग्य भेंट पूजा न केवल मु.मं. लोकायुक्त तक पहुंचाई जाती है। इसी कारण इस ब्यूरो को 4 वर्ष बाद सन् 2009 में सरकारी गजट में प्रकाशन कर सूचना अधिकार में जानकार देने से बाकायदा प्रतिबंधित करवाकर लूटपाट का खुला तांडव चलता रहता है।

इस विभाग में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने न देनेया अनुचित राशि मांगने, उल्टे सीधे जवाब देने पर वरिष्ठ अधिकारी को अपील की जाती है। अपील में एक तो सुनवाई के लिए बुलाने में ही जालसाजियां की जाती है, फिर भी समय से पत्र मिल गया और आवेदक समय पर पहुंच गया तो वहां 90 प्रश प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी चूंकि स्वयं ही महीना वसूल रहा होता है। साथ ही अपने अधीनस्थों के साथ जालसाजियों में संलग्न होता है, तो कैसे न्यायाधीश की भूमिका निभाये वह अपने अधीनस्थों का वकील बन वह जलसाज पैरवी करने लगता है।

साथ ही न तो अनावेदक की अपील का जवाब अग्रिम में आवेदक को देता है न उन्हें बुलाता है और हरामखोर स्वयं एक तरफा फैसला जिसका उससे संबंध हो न हो, फैसला देता है। इस संबंध में जबलपुर उपायुक्त 2 की अपील वहां की अपर आयुक्त सुमित्रा वर्मा को की गई थी कि उसने पत्र का जवाब ही नहीं दिया इसलिए धारा 7 (6) के अंतगर्त सारी जानकारी निःशुल्क दी जाये, उसने अपील के निर्णय में अपने अधिकारों के बाहर जाकर लिखा कि जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित थी इसलिए नहीं दी जा सकती, भोपाल सं.क. 2 के उपायुक्त का जग़ह वहां बैठी सहायक आयुक्त ने जानकारी देने की अपेक्षा भ्रष्ट जालसाज से भी मांगी गई जानकारी को तृतीय पक्ष बताकर तीन पेज की निरर्थक दलीलें पेश की, यही हाल इंदौर की पूर्णिमा चौरसिया सहा. आयुक्त व सहा. आयुक्त विनीता जैस ने भी किया, इन जालसाजों का हाल ये है कि कभी भी 11.30 से पहले आती नहीं और 4.30 बजे के बाद रूकती नहीं, दूसरी ओर जिनमें लूट, कमाई और कमाई की व्यवस्था है तो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भी काम करेगी, अन्यथा अपने हिस्से के काम कर निर्धारण आदि जिसकी एक-एक पदोन्नति लेने के बाद भी सही जानकारी नहीं, बाबुओं और अपने आतहतों पर टाल देती है। ये भ्रष्ट और जालसाजों को अपने मातहतों की कमाई जिसमें निरीक्षकों, सहा. वा.क. अधिकारी से वा.कर. अधिकारी की, बाबुओं की कमाई हड़पने में भी नहीं चूकती, वकीलों, व्यापारियों से झूठ बोल कर कि मैं कर दूंगी, उनकी भी मुझे दे दो, हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई कि आईटीआर और अधिक कर के भुगतानों में बिना मोटे कमीशन के भुगतान नहीं किए जा रहे है। जानकारी मांगने पर अधिकांश महिला अधिकारियों के जवाब में जैसा आवेदन दिया गया था, वैसे बिंदुवार और समयावधिबार फोटोकॉपी शुल्क का जवाब देने की अपेक्षा बिना पन्नों की गिनती किए एक दो न जवाब दिए अन्यथा भोपाल, जबलपुर में तृतीय पक्ष का कहकर जवाब देने से साफ इंकार कर दिया गया, यही हाल उस जालसाज व हरामखोर अपर आयुक्त शिवहरे ने भी किया कि उसके पास जो आयुक्त थे, उन्हें न तो अपील में बुलाया और स्वयं उनके वकीलों की तरह तरफदारी करके हर जानकारी को तृतीय पक्ष कहकर नस्तीबद्ध करवा दी गई अपीलें। जबकि ये इतने सीधे नहीं कि इन्होंने आवेदक को भले ही अपीलों के निर्णयों को कानून को बलाये ताक में रखकर अपने मातहतों की जानकारी न देकर बचा लिया हो परंतु स्वयं ने उन मातहतों से मोटी, वसूली की है और बदले में उल्टे-सीधे तरीके से कानून की व्याख्या कर टरका दिया।

आखिर कैसे दे दे, अपनी और अपने अधीनस्थों की जालसाजियों और भ्रष्टाचार का ये बारूद, जिसमें ये नामुराद आवेदक हाथ में आते ही, इसकी सच्चाई को न्यायालय में पेश करेंगे लोकायुक्त को शिकायत करेंगे या समाचार पत्र में छापकर इनकी इज्जत के चमाके जनता में ही जाकर करेंगे कोई भरोसा, फिर व्यवसायी भले ही जनता से कितना भी कर वसूले और जेब में रख ले व इन कर्मचारियों अधिकारियों को महीना बांटकर 10 प्रश भी कर शासन को दे न दे, पर इन्हें तो इनका व्यक्तिगत कर दे रहा है। इसी कारण सभी भ्रष्टों और जालसाजों की जानकारी देने में भारी डर लगता है कि उससे बचने के लिए ये शूकरों की फौज बचने के लिए बहानों का सहारा लेती है, यहां तक कि वसूली के लिए तो ये कानून की व्याख्या बड़ी बारीकी से करते है। पर सूचना के अधिकार में धारा 6 (3) में उपायुक्त अब्दुल मजीद जिसकी आधी से ज्यादा सेवा भ्रष्टाचार और लूट, वसूली के दम इंदौर में ही निकल गई अभी भी 5 वर्षों से ज्यादा समय में संभाग 3 में ही कुंडली मारे बैठा है, हरामखोर एक तरफ सीधे की गई अपीले निरस्त कर देता है तो दूसरी उपरोक्त धारा में अपने अधीनस्थों को आवेदन पत्र की जानकारी देने के लिए आंतरित भी नहीं करता, वैसे भी स्टाफ की कमी के कारण अधिकारियों को उचट के लगी हुई है, क्योंकि जितना कम स्टाफ होगा उतनी वसूली में हिस्से कम होंगे। दूसरी ओर दूसरों का हिस्सा भी हजम करने का पूरा मौका मिलेगा, फिर जबसे महाभ्रष्ट, जालसाज, अय्याश मनोज श्रीवास्तव, प्र.स. के पद पर बैठा है, उसे हर काम की मोटी कमाई चाहिए जैसे एंटी इवेजन ब्यूरो की इंदौर में सहा. आयुक्त व वा.कर. अधिकारी के महीनों से पद रिक्त इसलिए है कि वहां कोई मोटी 40-50 लाख से लेकर 70 लाख तक की मोटी रकम देने को तैयार नहीं है। साथ ही 31.3.17 को एंटी इवेजन ब्यूरो समाप्त हो जायेंगे, तो कोई भी धन खर्च करके फंसना नहीं चाहता।

हालात ये है कि भ्रष्टों की अपनी कमाई के लिए अभी तक 20-30 प्रश व्यापारियों ने पंजीयन भले ही नहीं करवाये हो, पर ये चुरकट अधिकारी अपना महीना जरूर डकार लेते है इंदौर में ही एमटीएच कंपाउंड के सामने बने हुए राम मोहन राय शापिंग काम्पलेक्स अधिकांश दुकानदारों के टिन नंबर तक नहीं है। लक्की ट्रेडर्स वाला खुले में नये चाइना टीवी बेच रहा है। परंतु सुधारने का काम बताता है। वही हाल नावेल्टी मार्केट की अंदर की दुकानदारों व्यापारियों ने पंजीयन नहीं करवाये हैं और अरबों रुपए के माल की बिक्री की जाकर खुलकर चोरी की जाती है। साथ ही जिन के पंजीयन है वो भी 50 से 80 प्रश माल कच्चे चिट्ठों पर बेच खरीद लेते है। इसमें भी निरीक्षकों से लेकर सहा.वा.कर अधि. जो अधिकांश बाजारों में रहते हैं। चुपचाप वसूली करते रहते है। यही कारण है कि मोटे वेतन के बाद भी ये हरामखोर जालसाजों की फौज,सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा बचने के लिए तृतीय पक्ष का बहाना ढूंढ निकालते है।

जबकि तृतीय पक्ष की कानूनी व्याख्या धारा 2 न के अनुसार तृतीय पक्ष से तात्पर्य जो नागरिक नहीं है जिसमें लोक प्राधिकारी भी है। अर्थात वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है। सूचना प्राप्त करने का व कोई भी लोक प्राधिकारी भी अपने ही विभाग से जानकारी नहीं मांग सकता, पर ये अपने विभाग को धड़ल्लों से जानकारियां देते हैं। इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि जो जानकारी संसद और विधानसभाओं को देने के लिए बाध्य है। वह जानकारी कोई भी भारतीय नागरिक प्राप्त करने का अधिकार रखता है। फिर अपील सुनने वाले 99 प्रश अधिकारियों ने 11 वर्ष बाद भी न तो पूरा कानून पड़ा, न समझा फिर जरूरत भी क्या है। लूट सके तो लूट लूट की है पूरी छूट। वैसे जीएसटी लगाने पर लूट के लिए छूट का पूरा खेल खत्म होने की संभावना के चलते सारे वा. विक्रय कर अधिकारी 28 राज्यों के दिल्ली पहुंच प्रदर्शन किया, इसके विरोध में, जो सच समय माया 8 वर्ष से लिख रहा था, अब समझ आ रहा है। मोटी कमाई के लिए भाजपा ने हर सांसद को रुपए 10 से 50 करोड़ उसकी हैसियत के हिसाब से बांटकर आखिर जीएसटी पास करवा लिया, अब वा.कर के अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर सरकार तक को समझ आ रही है कि अब इनके हाथ से सबकुछ छिनकर केन्द्र के पास चला जायेगा, तो सरकार को आगे हर माह वेतन बांटने के धन के लिए भी केन्द्र सरकार के पास हाथ फैलाकर 20-30 तारीख तक केन्द्र से भीख मांगना पड़ेगी मिली तो वेतन बटेगा अन्यथा मौज करो।

पूरे प्रदेश की रा.रा. की दशा बिगाड़ दी, भा.रा.रा. प्रा. ने

भा.रा.रा.प्रा. पूर्णतः असफल, लो नि.वि. रा.रा. से करवाई जाये पूरी

मप्र सड़क डकैती विकास निगम, स्तरहीन सड़कें, बीओटी ठेकेदार जनता से, वहां के डकैत ठेकेदारों पर कानून की आड़ में डकैती डाल कर रहे वसूली, सत्ता जाये भाड़ में

पूरे मप्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4602 किमी थी सन् 2008 तक फर 2009 में जब से इन सड़कों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया तब से एक दो सड़कों को छोड़ राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत और भी गंभीर हो गई, जिसके मूल में कारण थे अधिकांश सड़के दक्षिण भारत की उन जालसाज कंपनियों द्वारा हथियाई गई जो पूर्व से ही अपनी जालसाजियों के लिए न केवल कुख्यात थी वरन् जिनके हरामखोर जालसाज संचालक स्वयं ही कुख्यात विधायक और सांसद भी थे, वर्तमान हालात और भी बुरे हो गये, क्योंकि महाराष्ट्र का पूर्व का भ्रष्ट मंत्री लो.नि.वि. वर्तमान का केन्द्र का सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जिसके पास अनेकों बीओटी सड़के होने के साथ ही ताप विद्युत पर व अन्य उद्योगों का मालिक न केवल घोर जालसाज कर चोर भी है, चूंकि अरबपति होने के दम पर आसानी से रा. स्वशोषक संघ के माध्यम से भुखेरा जन पार्टी में और वहां से धन के दम पर मंत्री पद प्राप्त करने में सफल रहा।

जब कांग्रेस का शासन था तो महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में बीओटी की सड़कों के विरूद्ध भारी प्रदर्शन हुए, जिसमें भाजपा और उसके पितृ संगठन ने जनता के साथ मिलकर भारी आंदोलन किए। सत्ता में आते ही अब क्यों महाराष्ट्र में प्रदर्शन नहीं किए जा रहे है। क्योंकि अब तो उनको ही संघी भूतल परिवहन मंत्री है। अब सब भूल गये, क्या सड़कों पर चाहे वो राष्ट्रीय या राज्यों के राजमार्गों पर अकेले केन्द्रीय मंत्रालय 32 प्रश कस्टम और 2 प्रश सड़क विकास, 2 प्रश शिक्षा, 2 प्रश स्वास्थ्य, 2 प्रश अन्य उपकरों के रूप में 40 प्रश तक व मप्र शासन 32 प्रश पेट्रोल-डीजल पर सामने से कर वसूल रहा है। जबकि 25 रुपए के पेट्रोल और 20 प्रति लीटर के डीजल को रुपए 62 और पेट्रोल को रुपए 75 लीटर बैचकर भी 200 प्रश लाभ कमाने के बाद भी सड़कों पर वाहन चलाने के रूपए 1 प्रति किमी से रुपए 50 प्रति किमी तक टोल की डकैती भी डाल रहा है। जबकि वाहनों के निर्माण से लेकर बिक्री तक 60 से 125 प्रश तक का कस्टम, बिक्री कर आदि थोपा जाता है फिर 7 प्रश का मार्ग शुल्क बिक्री पर रोड टैक्स वसूला जाता हैं। इतनी वसूली के बाद भी इस लोकतंत्र तो वास्तविकता में लूटतंत्र की डकैतियां हर किमी चलने पर भी देनी होती है। इसके बाद भी रा.रा.वि.प्रा. की 8 प्रश सड़के चलने लायक नहीं है। चाहे मप्र का रा.रा. क्र. 3,5,9,7, 59 अ, जयपुर, जबलपुर आदि सभी की हालत दयनीय है। बेहतर होगा कि इन सारे राजमार्गों को रा.रा.प्रा. से लेकर प्रदेश की लो.नि.वि. के रा.रा. से ही कम से कम उन्नयन, चौड़ीकरण हो न हो गड्ढे भरवाकर चलने योग्य तो बनवाया जा सकता है। देवास की राऊ के मार्ग को बनते हुए और बिना पूरा बने टोल वसूली करते हुए 7 वर्ष हो गये परंतु हर क्रॉसिंग गड्ढो और धूल से भरी हुई है। इन 7 वर्षों में हजारों दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग जान गवां चुके है। परंतु उन हरामखोर रेडुभ बंधुओं के साथ रा.रा. प्रा. जिसमें आयातित सिविल कार्य के लिए यांत्रिकीय से उत्तीर्ण इंजीनियर्स परि. संचालक बनकर चुपचाप बैठा है।

इंदौर पिटोल मार्ग भी खराब है पूरी तरह से, ठेकेदार ने बैंक ऋण से अपना मोटा कमीशन हजम कर बिना पूरी किये हैं। छोड़कर ही भाग गया, इंदौर-खंडवा इच्छापुर, मुसावल मार्ग भी रा.रा. घोषित होने के बाद भी मप्र रोड डकैत निगम के पास है। इसकी अशोका बिल्डकॉन की ठेकेदारी भी समाप्त होने वाली है। इसे भी 6 लेन हो जाना चाहिए। वर्तमान मार्ग को पहाड़ों में गुफायें और पुल बनाकर लंबाई कम की जा सकती है। इसके भी रा.रा. को ही सौंपकर कार्य करवाया जाना चाहिए, अन्यथा जिन सड़कों के दम पर सरकार आई थी, उन्हीं सड़कों के दम पर ही जायेगी भी, सार्वजनिक सड़कों को अपनी कमाई के लिए सत्ताधीशों चाहे वो कांग्रेसी हो या मुखेरा जनहित भक्षी पार्टी के सबने अपने मोटे कमीशन जो रुपए 1 करोड़ प्रति किमी 5 करोड़ प्रति किमी तक होता है। ठेकेदारों को सौंप, बैंकों से ऋण की गारंटी देकर बनवाकर जनता को लूटने के लिए इन जीवन दायिनी सड़कों को हवाले कर दिया जाता है। और जनता से प्राप्त करों के धन से प्र.म. से लेकर मंत्री अधिकारी विश्व भ्रमण कर लाखों करोड़ बर्बाद करते हैं। मोदी ने विश्व भ्रमण पर जो रुपए 50 लाख करोड़ बर्बाद किए उसके 10वें हिस्से से ही 50000 किमी सड़कों को 6 लेन किया जा सकता था, यदि रुपए 10 करोड़ प्रति किमी भी खर्च होता तो जबकि रुपए एक करोड़ प्रति किमी में ही काम किया जा सकता है।

साप्ताहिक समय माया

जिस बिजली व सड़कों से सरकार आई थी उसी की लूट व डकैती से जायेगी

मप्र सड़क डकैती निगम-सड़कों पर भी ठेकेदारों की लूट

भ्रष्ट मु.मं.,प्र.स., प्र.संचा., सचिव से लेकर सं.प्र. प्रबंधक, ठेकेदारों से महीना वसूलकर चुप

समय माया सन्2003-04 से सड़क डकैती निगम की लूट और वाहनों से लूट की प्रशंसा में सतत समाचार प्रकाशित कर रहा है, परंतु भ्रष्ट मुख्यमंत्री चौहान, पूर्व के और वर्तमान के प्रधान सचिवों, सचिव से लेकर इस डकैती निगम में बैठे प्रबंध संचालकों सुलेमान, विवेक अग्रवाल से लेकर वर्तमान मनीष रस्तोगी, वहां बैठे सारे मुख्य अभियंता जो संचालक के पदों पर उनके अ.यं. के पदों पर महाप्रबंधक संभागीय प्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों के पदों पर बैठे सहायक यंत्री और उपयंत्री पदस्थ सब केवल आंख मींचकर कर शासकीय वेतन से ज्यादा ठेकेदारों के टुकड़खोर श्वानों की फौज है, वैसे भी इस निगम का मूल उद्देश्य ही था कि प्रदेश की सार्वजनिक सड़कों का निर्माण जन-धन से किया गया था, उनको निजी सेक्टर में सौंप कर,वाहन खरीदी पर 7 प्रश सड़क कर 15.0 प्रश विक्रय कर, 75 प्रश कस्टम एंड एक्साइज के साथ फिर रुपए 18 प्रति लीटर के पेट्रोल को मोदी अपने आका रिलायंस से रुपए 40 प्रति लीटर खरीदकर 32 प्रश कस्टम एक्साइज, 2 प्रश शिक्षा, 2 प्रश सड़क कर, 2प्रश स्वास्थ्य, 2 प्रश सेवा कर का सेस और फिर 32 प्रश राज्य सरकार का विक्रय कर बनाम वेट मिलाकर रुपए 75 प्रति लीटर की डकैती डालकर भी सत्ताधीश दानवों का पेट नहीं भरा तो उन्होंने रुपए 1 से लेकर रुपए 25 प्रति किमी का टोल टैक्स थोपकर जनता को लूटा, अच्छे दिन कीतरह अच्छी गुणवत्ता पूर्ण सड़कों के नाम। जबकि बीओटी की 90 प्रश सड़के गड्ढों की, ऊंची-नीची होने के साथ असुरक्षित यहां तक कि 10-10 वर्ष बाद भी मार्ग संकेतकों और किमी तक के पत्थरों का भी पता नहीं साथ ही जगह गति अवरोधक की भरमार 2 लेन और 50 प्रश सड़कें तो एक लेन होने पर भी टोल वसूला जा रहा है। जबकि केन्द्र सरकार की भूतल परिवहन मंत्रालय की स्पष्ट नीति है कि 4 लेन से कम पर टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। दूसरी तरफ किसी भी टोल ठेकेदार ने अपना पैसा नहीं बैंकों से कर्ज लेकर जो कि जन-धन ही है। साथ ही हर सड़क की दोगुनी से 6 गुनी तक ज्यादा कीमतों की डीपीआर बनवाकर वह भी भाड़े के सलाहकारों से 1 प्रश कीमत पर साथ ही कार्य की देखरेख के लिए इस निगम ने अपने कमीशन के साथ 2 प्रश कुल कीमत की डीपीआर भुगतान कर सलाहकार संस्थाओं जिसमें पूर्व के लो.नि.वि. के सेवानिवृत्त धूर्तों की फौज जिसमें से.नि.मु.अ. पू.च. अग्रवाल जैसे गिद्धों की फौज भरी थी जो ठेकेदारों के कार्यों पर अंगूठा लगवाकर वसूली कर चुप बैठी रहती थी, स्वाभाविक था, निगम में जो संभागीय प्रबंधक थे वो भी अपना टुकड़ा खाकर चुपचाप देखते थे, वैसे भी लो.नि.वि. के महामूर्ख ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर जो वहां नकारा और निकम्मे सिद्ध हो रहे थे चुन-चुन कर पदस्थ किया गया था। बाद में एडीबी, मंडी निधि, केन्द्रीय सड़क निधि का कार्य भी इसी लिए दिया गया था ताकि ये आराम से लूटपाट कर सके। सबसे ज्यादा ऐसे बीओटी के आजमगड़िया धूर्त सुलेमान और उसके बाद हरियाणवी डकैत विवेक अग्रवाल के समय 2 से 4 गुनी लागत पर हस्ताक्षरित हुए जिसमें इन हरामखोरों ने रुपए 25 लाख से रुपए एक करोड़ प्रति किमी 40 से ज्यादा बीओटी ठेकों में हजम किया। अधिकांश ठेकों में निर्माण ठेकेदारों ने सारा कमीशन बांटकर, 10 प्रश अपना हिस्सा मिलाकर, जानबूझकर कार्य की दुगुनी तिगुनी कीमत लागत बताकर बैंकों से ऋण लेकर भी 30 से 50 प्रश हिस्सा डकारकर सड़कों को रखरखाव करने वाली फर्मों को संपत्तियों और देयतायें, स्थानांतरित कर खिसक लिये, जहां पर दैनिक टोल आय कम थी, हालात ये है कि ठेकेदार सड़कों का रखरखाव तो दूर रखे गये कर्मचारियों को भी नाम मात्र न्यूनतम वेतन देकर, इस डकैती निगम के श्वानों को टुकड़े डालकर और मोटा मार्जिन रखकर घाटे दिखाकर ठेकेदार बैंकों की किश्तें जानबूझकर जमा नहीं कर रहे है पर वसूली तो कर रहे हैं। चूंकि सारे डकैती निगम के डकैतों को मोटा महीना मिल रहा है तो अकेले इंदौर में संभागीय प्रबंधक के पद पर बैठाये बौरासी जो कि सं.2 का सं.प्र.था, इस मूढ़ जिसने सेतु संभाग में भारी बर्बादी की थी, यहां तक सेतु के खंभों के नीचे डाली जाने वाली लोहे की प्लेट, पुल की वहन क्षमता के अनुपात में 1 से 4 इंच मोटी लोहे की प्लेट तक डालना दिखाकर लाखों रुपए हर पुल में हजम किया, जांचे लंबित है। के साथ सं.क्रं-1 और इंदौर-उज्जैन जिसमें 5000 किमी से ज्यादा बीओटी, एडीबी व अन्य सड़के हैं का ही महाप्रबंधक भी बनाकर पिछले 5 से ज्यादा वर्षों से केवल मोटी कमाई रखने के लिए ही बैठाये रखा है। मंत्री रा.पा. सिंह ने भी पहली ही चर्चा मेंकहा था कि अच्छा 5 वर्षों से आप यहां पर है और 15 जिले देख रहे हैं। यथार्थ यह है कि ये हरामखोर बीओटी सड़कों पर डकैती डाल रहे ठेकेदारों से वसूली कर सब सड़कों की अच्छी स्थिति बता देता है। उस वसूली के कुछ टुकड़े प्र. संचालक के साथ, मु.मं. कार्यालय का, श्वान विवेक अग्रवाल को डालकर अपनी इंदौर की तीन पदस्थापनाओं को बचाये हुये है। मु.मं. कार्यालय में बैठी चांडाल चौकड़ी के ऐतिहासिक रूप में जमे चांडाल इकबाल सिंह बैस को इसी ने बाहर का रास्ता दिखवाकर चारों तरफ की वसूली पर एक छत्र राज कर रहा है। इसी हरियाणवी न केवल लो.नि.वि. व इसके सभी विभागों के साथ अन्य सभी विभागों की स्थानांतरण सूचियों को अरबों की वसूली के लिए रोक रखी है। इससे न केवल रुपए 500 करोड़ की वसूली के आधार पर बनाये गये सारे नये व पुराने मंत्रियों के साथ ही सभी अन्य विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, संचालक, आयुक्त, प्रमुख अभियंता भी सैकड़ों करोड़ की कमाई हाथ से जाते देख नाराज है। इस चांडाल विवेक अग्रवाल को सचिव व प्र.सं. सड़क डकैती विकास निगम को छोड़े वर्षों अवश्य हो गये, परंतु मु.मं. कार्यालय में बैठकर न केवल पूरी लो.नि. वि. गतिविधियों, स्थानांतरण, पदस्थापना, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति से लेकर हर बड़े ठेके में कमीशन आदि के साथ ही पूरे रोड डकैत कारण के सारे बड़े ठेकों में डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति से लेकर बैंक ऋण और उसकी गारंटी की स्वीकृति, 3 गुने से लेकर 4 गुनी डीपीआर अपना और मु.मं. का प्रति किमी 50 लाख से रुपए एक करोड़ का कमीशन हजम कर ही स्वीकृति देता है, बोरासी को इंदौर में केलकर को 2 संभागों में उज्जैन, 15-20 सहा. यं. को संभागों के प्रभार के बदले में मोटा कमीशन के इस खेल में भी रोल अदा कर रहा है। भोपाल के सत्ता के इर्द-गिर्द सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विवेक अग्रवाल न केवल लो.नि.वि. वरन हर विभाग की सूची को मु.मं. कार्यालय में बुलवाने के बाद संबंधितों से लेन-देन का खेल कर रहा है। प्र.सं. इकबाल सिंग बैस का जो वसूली विनियोजन सौदेबाजी का पिछले दो दशक से जो मु.मं. कार्यालय पर एकाधिकार था, उस परा अब उसे बाहर का रास्ता दिखाकर न केवल कब्जा कर लिया, वरन अपनी प्रजाति के अग्रवालों को, जिसमें प्रमोद, पंकज, चंद्रप्रकाश, डी.डी., राकेश अग्रवालों को अच्छे क्रीमी विभाग देकर लूटने खाने के लिए छोड़ दिया है। जिसके चलते लो.नि.वि. में कार्यों का कम लूट खंसोट और भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है। इसलिए पूरे मप्र में बीओटी की सड़कों पर एक, दो, चार, लेन की सड़कों की बदहाली से दूर्घटनाओं में भारी बढ़ोत्री होने के साथ कहीं न कहीं न केवल बसें कारे, ट्रक व अन्य सभी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर जान माल की भारी हानि के बाद भी किसी भी गिद्ध का कोई चिंता नहीं है, मु.मं. शिवराज कभी सास के ईलाज के लिए कभी बेटे से मिलने, कभी अपना काला धन विनियोजित करने विनियोजकों को लुभाने जाने की आड़ में 8-8, 10-10 दिन के लिए विदेश यात्राओं में मस्त रहता है। उसे मालूम है कि उसके अब दिन पूरे हो गये हैं कभी भी मु.मं. के पद से हटाया जा सकता है। इसलिए मु.मं. रहने जितना सुविधाओं शक्ति का दुरुपयोग कर सारे लाभ लिये जा सकते है। भरपूर लेते हुए दोनों हाथों से वसूली कर लो क्योंकि केन्द्र नहीं ने हटाया तो भी जिस बिजली सड़कों के दम पर सत्ता में आये थे उसकी बिजली और सड़कों पर जनता के वोटों से कम वरन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की और सत्ता के असली सूत्रधार इंडियन एब्यूसिंग सर्विस के महाधूर्तों की जालसाजी से ज्यादा जीत-हार होती है।

मप्र खनिज विभाग 1 प्रश राजस्व भी नहीं, मु.मं. से लेकर पटवारी, खनिज निरीक्षक तक लूट रहे

मंत्री, संत्री, कलेक्टर, खनन अधि, निरीक्षक सब लगे हैं, खनन से धन खनकाने

सभी नेता, खनन माफिया, मंत्री राजेन्द्र शुक्ला अरबों की संपत्ति अवैध खनन की, मु.मं. से लेकर छूटभय्यै, तक महीना बांटकर करते है, खनन से बने तालाबों में हर वर्ष सैकड़ों मौते

पूरे मप्र में रेत, पत्थर, मुरम से लेकर कीमती धातुयें, तांबा, लोहा, अभ्रक से लेकर हीरे तक के होने वाले प्रतिदिन कुल खनन का 1 प्रश भी राजस्व शासन के खाते में नहीं आता, जबकि पूरे प्रदेश रेत, मिट्टी, पत्थर, मुर्रम की रुपए 1000 करोड़ से ज्यादा की बिक्री होती है। जिसकी रायल्टी 1 प्रश भी खाते में नहीं आती, जबकि केवल सरकारी विभाग ही जिसमें लो.नि.वि. की भवन व पथ, सेतु, परि. ई.सा.रा.रा, जैसी शाखाओं में एक अरब की निर्माण कार्यों में रेत, पत्थर, मुर्रम का उपयोग हो जाता है, फिर जल संसाधन, लो.स्वा. या. ग्रामीण यांत्रिकीय, न.घा.,वि.प्रा., नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों में निर्माण मरम्मत आदि कार्यों में पूरे प्रदेश में इतना खर्च होता है जिसके मूलतत्वों में रेती, गिट्टी, पत्थर, मुरम ही होते है। बेशक कुछ विभाग जिसमें सड़क डकैती निगम प्रदेश के सारे नगर निगमों, पालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, रा.राजमार्ग प्राधिकरण और सभी टर्न की प्रोजेक्टस जो सभी विभागों में चल रहे है। 90 प्रश चोरी की रेत, गिट्टी, पत्थर, मुरम के उपयोग से ही कार्य संपन्न होता है। यह हाल प्राथमिक या निम्न श्रेणी के खनन का है। परंतु उस उच्च श्रेणी के खनन जिसमें साधारण धातुओं यथा लोहा, तांबा, जिंक, बाक्साइड आदि के खनिजों में 0.5 प्रश से 0.1 प्रश तक भी नहीं मिलता, जबकि हीरे जैसे रत्नों में छतरपुर पन्ना से लेकर रीवा तक फैले बेल्ट में 0.1 प्रश कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि अधिकतर खदानों पर खनन माफिया नेताओं का कब्जा है, जो खनिज अधिकारी से लेकर जिले के कलेक्टरों संभाग के कमिश्नरों, प्रस सचिव मंत्री और मुख्यमंत्री को करोड़ों रुपए देकर पहले ही औने-पौने में वैधानिक तरीके से भूमिका पट्टा हथियाते हैं। अंदाज लगाया जा सकता है कि रुपए 250 करोड़ की रिश्वत लेते औश्र वही खदान रुपए 5000 करोड़ में नीलामी में गई राजस्थान में,फिर मप्र में तो हीरे की खदान तक है। निम्न श्रेणी से लेकर उच्च श्रेणी कोयला है, जिसका कोलगेट कांड अभी भी गाहे बगाहे सुर्खियों में आ जाता है। फिर झाबुआ की मेगनीज, बालाघाट की तांबा खनिज की खदानों क्या मप्र में नीलामी की गई, सारे खनिज अधिकारी निरीक्षकों से लेकर कलेक्टर तक हर दिन अवैध खनन में से हिस्सा प्राप्त करते है। रेती, पत्थर मुरम से लेकर अन्य खनिजों में ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां के कलेक्टर रहते हुए भितरवार की एक पत्थर खदान रुपए 50 करोड़ लेकर एक खनिज माफिया को साधारण पत्थर बताकर सौंप आये। इंदौर के पी. नरहरि इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जि.ख. अ. प्रदीप खन्ना जो हर महीने लगभग रुपए एक करोड़ से ज्यादा हजम करता है। जिसमें प्रतिदिन औसतन 1000 ट्रक रेती, जो बड़वाह नेमावर मार्ग आगरा-बाम्बे मार्ग, धार आदि से आती है। यही हाल गिट्टी और कोयले व अन्य का है। जिसमें निरीक्षक भिंद्रे आलोक अग्रवाल व अन्य निरीक्षक भी रुपए 1-3 लाख की औसतन कमाई करते है। जानकारी कैसे और मरने के लिए क्यों दे? अपील लगाने पर जिले का सरकारी कानूनी डकैत बिना देखे अपील खारिज कर देता है। क्योंकि उस डकैती में उसका भी हिस्सा है। यही हाल देवास के जि.स्व.अ. उइके, उसके निरी. मिश्रा, फरहत जहां आदि की प्राप्त दस्तावेजों की जानकारी से स्पष्ट होता है कि कैसे ये अवैध उत्खनन की शिकायतों, पत्थरों, रेती की खदानों, मुरहम आदि में अरबों रुपए की राजस्व चोरी करवाकर न केवल स्वयं वरन करोड़ों की कमाई कर जिलाधीश से लेकर आयुक्त, सचिव, प्र.स. पुराने कुख्यात खनन माफिया रा. शुक्ला और मु.मं. तक हिस्सा पहुंचाया जाता है।उज्जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15-16 में मात्र रुपए 12 करोड़ की आय प्राप्त हुई। मात्र 300 घन मीटर पत्थर का खनन हुआ, जबकि कच्चे अनुमान से ही सिद्ध होता है कि लगभग 1000 धन मीटर पत्थर की गिट्टी बनाकर, निजी सार्वजनिक व शासकीय कार्य विभागों के निर्माण मरम्मत पूरे उज्जैन जिले में खर्च हो जाती है। यहां बैठे जि.ख.अ.एम.एस. खतेडिया ने चर्चा की तो बताया, निरीक्षकों की भारी कमी, पदोन्नतियों आदि में शासन के दोगले चरित्र के कारण मुश्किल से खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने की पहल की जाती है,परंतु साधनों के अभाव में जैसे जैसे कार्य चलाया जाता है।

मप्र लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

भ्रष्टाचार छुपाने चक्कर कटवाते है, आवेदकों को, जालसाज इंजिनियर्स

प्र.स.प्र. अग्रवाल, मु.अ.अ. अग्रवाल दोनों हाथों बटोर, बचा रहे जालसाजों को

मप्र लो.नि.वि. को दिग्गी ने सन् 2002 में बंद करने की घोषणा कर दी थी, जिसमें प्रदेश की सड़कें सारी मप्र डकैती निगम को, सारे भवन संबंधित विभागों को सौंपने की तैयारी थी, उस समय भी लो.नि.वि. के कर्मचारियों ने श्री अजमेरा को घेरा और कहा कि ये विभाग बंद नहीं होना चाहिये, तो उन्होंने पलट कर कहा कि भाइयों मुझसे कहने से क्या होगा, मैं कौन हूं, कितनी बखत है मेरी, मात्र एक छोटे से समाचार पत्र जो धन के अभाव में कभी समय से नहीं छप पाता, मैं क्या कर पाऊंगा, तो भी उन्होंने कहा, आप तो लिखो आपका जादू कलम का खाली नहीं जायेगा, तब भी दिस 2002 के प्रकाशन में दिग्गी की लूटने खाने और बर्बाद करने व लो.नि.वि. के आधिपत्य की जमीनों को भूमाफिया को बैंच मोटा धन कमाने की लालसा को प्रकट कर इस विभाग को बचाने में समय माया ने भूमिका निभाई थी। पदोन्नतियों वरिष्ठों द्वारा परेशान किए जाने की अवस्था में भी समय माया अपने औचित्य और इनके संघर्ष में यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग करता रहा, परंतु सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, जालसाजियां करने और सू.अ. के कानून की धज्जियां उड़ाने और जानकारी न देने के लिए ये सारे दुष्कृत करने से नहीं चूकता। मु.अ. कार्यालय इंदौर, उज्जैन में सूचना के अधिकार में पत्र दिए गए, इंदौर के मु.अ. कार्यालयों में बैठी हरामखोर और जालसाज मु.अ.व. संबंधित कर्मचारी इस पत्र को धारा 6 (3) में कभी भी अपने अधीनस्थ यंत्रियों और अधीक्षण यंत्री इंदौर कभी भी अपने अधीनस्थों को पत्र अंतरित नहीं करते हैं। साथ ही जिस तरह से आवेदन दिया जाता है ये निकम्मों की फौज लिखने के बाद भी आवेदन का जवाब बिंदुवार और समयावधि के अनुसार नहीं देती, न ही वहां बैठा लो.सू.अ.व. स्वयं मु.अ. इसके बारे में कभी अधीनस्थों से पूछताछ करता, कहने को भ्रष्ट बिंदुल जालसाज, मु.अ. बना दिए गए जब कि एक साधारण से आवेदन का जवाब ढंग से नहीं दे सकते तो पाठक अंदाज लगा सकते है कि अंदर बैठे भ्रष्टों, जालसाजों की फौज क्या और कैसे कर रही होगी। **(शेष पृष्ठ 5 पर)**

न पदोन्नतियां न स्थाई भर्तियां- सरकार भी विभागों में ताले लगाने की तैयारी में

घोर शोषण कर रहे कर्मचारियों का सरकारी विभागों में

शास. विभागों में भी कर्मियों की ठेके में भर्तियां, ठेकेदार 20 से 50प्रश वेतन हजम कर जाते है। उच्च अधिकारी ठेकेदार से भी मोटा धन हजम करते हैं। तब उनको ठेका कर्मी जमकर लूटपाट, भ्रष्टाचार करते हैं। उसमें भी हिस्सा डकारते हैं। उच्चाधिकारी व नेता

मप्र सरकार में बैठी भाजपा अच्छी तरह जानती है कि वह तीसरी बार भी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से ही सत्ता सुख भोग रही है। इसलिए एक तरफ 2006 में 6ठवां वेतन मान और 2006 में 7वां वेतनमान उन स्थाई कर्मचारियों को देने की घोषणा कर दी, दूसरी पिछले 26 वर्षों से स्थाई कर्मचारियों और अधिकारियों की जिसमें सभी कार्य विभागों यथा लो.नि.वि., जल संसाधन, लो.स्वा.या. ग्रामीण यांत्रिकीय के वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक तरफ भर्ती न होने, दूसरी सेवानिवृत्तियां और मृत्यु के कारण वास्तविक कार्य करने बाल कर्मियों की संख्या आधी से कम हो गई तो दूसरी तरफ कम्प्यूटराइजेशन और कार्य की मात्रा तीन गुनी तक बढ़ गई, 90प्रश विभागों में हालात ये हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुभवी कर्मचारियों, यहां तक कि सहा. आयुक्त स्तर के अधिकारियों जैसों को वाणिज्य कर मुख्यालय तक में, वर्तमान में सेवानिवृत्त सहा. आयुक्त माहेश्वरी इंदौर, मुख्यालय में कार्यरत है। यही हाल वाणिज्यकर, आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी कार्य विभागों में खनिज, खाद्य, आदिम जाति कल्याण, जिलाधीश कार्यालयों पंचायत, कृषि, उद्यानिकी, ग्रामीण, यांत्रिकीय, महिला बाल विकास, श्रम,औद्योगिक, स्वा.व सुरक्षा विद्युत कं. सभी मंडलों निगमों आदि सभी में जनसंख्या कानूनी आवश्यकताओं समय परिवर्तन के हिसाब से कार्य तिगुना हो गया और स्टाफ कहीं 20 प्रश कहीं 30 प्रश कहीं 40प्रश ही रह गया, बेशक यह स्थिति केंद्रीय सरकार के विभागों में भी है। कुछ विभागों में जिससे लो.नि.वि. जिसकी चार शाखाओं में विभाजन हो जाने के बाद यथा लो.नि.वि.,सेतु, सड़क विकास, निगम वीरा इकाई, स्टाफ मात्र भवन और पथ व सें से यांत्रिकीय का ही था, जबकि रा.रा. के अधिकांश संभाग और उपसंभाग बंद कर दिये गये, वि.व.यां. में इसके सभी विभाग 17-18 तक 80 प्रश बंद होने के कगार पर पहुंच जायेंगे। अभी विद्युत यांत्रिकीय के स्वा. व. सुरक्षा, बायलर, उद्योग, नर्मदा घाटी, ग्रामीण यांत्रिकीय, लो.स्वा. यां, जल संसाधन वन विभाग जिला तहसील स्तर के कई कार्यालयों ें 25 से 50 प्रश कार्यालयीन समय में भी ताले लटके रहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पंचायत, आदि में ग्रामीण स्तर पर भवनों का निर्माण तो किया जा रहा है परंतु डॉक्टरों, शिक्षकों, अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती का कोई ठोस हल निकालने की पहल नहीं की जा रही है। इसके विपरीत सरकार से स्थाई जिम्मेदारी न होने के कारण हर कार्य की गुणवत्ता बिगड़ने पैसे की घोर बर्बादी, भ्रष्टाचार भी चारों तरफ बढ़ा, फिर स्थायित्व के अभाव में, संविदा और ठेके पर लगाये कर्मचारियों को वेतन भत्तों, छुट्टियों,स्वास्थ्य, लो.नि. वि., पंचायत, विद्युत मंडल, कृषि, आदि में देखा जा सकता है। शिक्षा में घोर बर्बादी हुई, जिसमें 10-12वी के विद्यार्थियों को ढंग से हिन्दी इंग्लिश लिख-पढ़ नहीं सकते, लोक निर्माण विभाग के परि.कि.ई. में ठेके पर गए कर्मियों को विभाग देता है, रुपए 12,500- और ठेकेदार भुगतान करता है रुपए 8 से 8500 स्वाभाविक है ठेके पर भर्ती इंजिनियर जिसे नाप पुस्तिका भरने से लेकर बिल बनाने तक के कार्य करवाये जा रहे है। कम्प्यूटर ऑपरेटर्स दक्ष श्रमिक की श्रेणी में आता है। इसकी भर्ती में घोटाले कृषि, लो.नि.वि.लो. स्वा. यां. कोष व लेखा वाणिज्यकर ग्रामीण यांत्रिकीय पंचायतों, स्वास्थ्य विभाग सभी में हुए, कई विभागों में तो उन्हें दैनिक वेतनभोगी से कम वेतन दिया जा रहा है। फिर विभाग के संचालक प्रमुख अभियंता आयुक्त और उनसे जुड़े लोगों ने ठेकेदारों को अपने कमीशन के हिसाब से रखा और संविदा पर कार्य करवाये, इन बेरोजगारों से मनचाहे तरीके से फर्जी काम करवा लो, क्योंकि संविदा पर है। कोई जालसाजी पकड़ में आने से पहले इनका स्थानांतरण करवा दो या इन पर ढोल दो और अपने आपको सुरक्षित कर लो, उसे हजारों टन गेहूं चोरी में, चौकीदारों को दोषी ठहराकर हटा दिया गया। लो.नि.वि.परि. क्रिया इकाई में कम निर्माण अनावश्यक लीड की अधिक राशि को भुगतान कर राशि हजम की गई। अनावश्यक कई कार्यों में उज्जैन, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर में करोड़ों का अधिक भुगतान से परि. यंत्री ने पैसा हजम कर हड़पा और जब मामले सामने आये तो वो इन संविदा यंत्रियों पर ढोला गया, पंचायतों में भी अरबों रुपए का पूरे प्रदेश में भुगतान हो रहा है। पकड़े जाने पर संविदा कर्मियों पर डालकर भगा दिया जाता है। आखिर बड़े अधिकारियों की धड़ल्ले से स्थाई भर्तीयां छोटे कर्मचारियों को ठेके पर रखने का उद्देश्य यही है कि उनसे भ्रष्टाचार जालसाजियों के कार्य मामले सामने आने से पहले बाहर कर दो, ताकि सभी अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को माल हजम करने का रास्ता बना रहे, फिर सरकार में मंत्री अधिकारियों के बाप की जागीर तो नहीं। स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति हो तो जिम्मेदारी ठहराई जा सके। वोटों की राजनीति के दुष्परिणाम सामने है। 2017 में सभी शास. विभागों अनु. जाति जाति, जनजाति ही बचेंगे सारे सामान्य का सफाया हो जायेगा, फिर देखिए बर्बादी।

भ्रष्टाचार छुपाने चक्कर कटवाते है..

पृष्ठ 4 का शेष

भारतीय सड़क कांग्रेस के 17 से 22 दिसम्बर 15 के अधिवेशन में क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष पद पर मु.अ. प्रभात श्रीवास्तव सचिव बंसी जैसवाल, को अधिकारी का.य. निर्मल श्रीवास्तव, लेखाकर मनीष त्रिवेदी था, शासन के मिले धन,सदस्यों से बटोरे व प्रदेश के ठेकेदारों से नगद व चेक से मिला कुलधन रुपए 20 करोड़ से ज्यादा था, चारों के साथ अलग-अलग समितियां भी थी, जो होटल बुकिंग कार्यक्रम, भोजन, यातायात, प्रिंटिंग आदि कार्य देख रही थी। जिसमें अलग अधिकारी थे सूचना अधिकार में दिये पत्र जो 01.04.2016 को दिया गया था, जिसकी अपील 07.05.16 को की गई, 02.07.16 को सुनवाई की गई और उसमें कहा गया कि आपको सारी जानकारी निःशुल्क दी जायेगी। 3 माह गुजर जाने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई, सचिव व अ.यं. बीएल सेवानिवृत्ति पाकर मुक्त हो गया, ये तीनों धूर्तों ने फाइल इसके पास है, उसके पास है, में तीन माह बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं किया, न ही शूकरों की फौज जानकारी दे रही है। बेशक पैसा प्र.स. व मु.अ. अखिलेश अग्रवाल को भी बांटा गया, जिसकी शिकायत आने अब लोकायुक्त को भी जा रही है। किस तरह ये तीनों जालसाज जानकारी न तो देने से मना कर रहे है न ही देने को तैयार है। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, कहकर ये तीनों धूर्त टालमटोल कर रहे है।

सं.क्र. 1 के का.य. निर्मल श्रीवास्तव ने मेगा चिकित्सालय में व अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार किया है। पुरानी भी कई जांचे इस पर लंबित है। यही कारण है कि प्र.स. प्रमोद अग्रवाल की अर्धांगिनी हर माह इंदौर आकर भारी खरीदी करती है। जिसके बिलों का भुगतान इसके सहा. य. स्तर के अधिकारी करते हैं। प्र.स. प्रमोद अग्रवाल के भ्रष्टाचार और लूट में इंदौर से लेकर पूरे मप्र के कार्यपालन यंत्री भुगतान कर रहे हैं। इसलिए सारे भ्रष्टों को खुलकर पाला जा रहा है। जैसे उज्जैन में का.यं. केलकर के भ्रष्टाचार की अनेकों जांचों के बाद भी सेतु, संभाग का प्रभार दे दिया गया है। इंदौर सेतु सं. में घोर भ्रष्ट जालसाज का.यं. रा.ना. मिश्रा को 5 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। 20 से ज्यादा संभागों में प्रभारी का.यं. बैठाकर महीना वसूली का खेल चरम पर है।

खाद्य एवं औषधि कानूनों की आड़ में हो रहा लूट का तांडव

सांची एवं अमूल दूध के नहीं लिए वर्षों से नमूने

एक ही स्थान पर महीना चुकाकर बैठे है 5-8 वर्षों से ज्यादा समय से, खाद्य एवं औषधि विक्रेताओं, निर्माताओं से मोटा महीना वसूली कर पहुंचाते हैं, मु.चि. अधिकारी उपजिलाधीशों और आयुक्त तक, इसलिए सब है चुप, दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कं. के इशारों पर न केवल केन्द्र सरकार वरन उच्च व सर्वोच्च न्यायालय भी नाच रहे है। खाद्य एवं सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लगाने और अब एलोपैथिक औषधियों के यौगिकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में भी अपनी संदिग्ध भूमिका निभाई है, जो गरीबी बीमारों को सीधा मौत के मुंह में धकेलेगी

मप्र की सरकार में बैठे चुन कर आये मंत्रियों को तो 5 वर्ष काम के बहाने सीधी दोनों हाथों से लूटपाट कर धन बटोरना ही उद्देश्य है, चाहे वो जालसाज मु.मं. हो या अन्य तो स्वाभाविक है कि सत्ता में परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर बैठे, आई.ए.एस. बनाम इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों से लेकर खाद्य व सुरक्षा व मानक अधिनियम 06 के निरीक्षक सह खाद्य सुरक्षा अधिकारी और औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत नियुक्त औषधि निरीक्षकों से लेकर बाबुओं तक जो 5 से 25 वर्षों से एक ही स्थान पर बैठे कानूनों की आड़ में लूट-पाटकर अपने आकाओं यथा उप संचालक सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहा., उप व जिलाधिकारी से लेकर खाद्य एवं औषधि नियंत्रक कम सह प्रशासक को उनके मुंह के आकार का टुकड़ा डालकर सबका मुंह बंद रखने के लिए बाध्य है।

आखिर क्यों 3 वर्ष से ज्यादा एक ही स्थान पर इस विभाग में खाद्य व औषधि निरीक्षक सारे प्रदेश के जिलों में पदस्थ रहते हैं। फिर इंदौर में तो औषधि निरीक्षक गोयल व ठाकुर खाद्य निरीक्षक मनीष स्वामी, सुभाष खेड़कर, श्रीमती वैशाली, सबको 8 वर्षों से ज्यादा हो चुके है। स्वाभाविक है रुपए 40-50 लाख रुपए महीने की कमाई कर रुपए 5 लाख प्रति माह नियंत्रक रुपए 2 लाख प्रति माह मु.चि.अ. सह. उप संचालक, संयुक्त संचालक, सबको बांटा जा रहा है, रुपए 10 हजार प्रति माह प्रति अनुज्ञप्ति पर अपने-अपने क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों को देना पड़ता है। इसलिए छोटे-छोटे दुकानदार खाद्य वस्तुओं के या तो अनुज्ञप्ति ही नहीं बनवाते और यदि खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करना मजबूरी बन ही गया है, तो रुपए 10 से लेकर 50 हजार तक चुकायेंगे तो स्वाभाविक है वो खुले में मिलावट भी करेंगे, स्तरहीन खाद्य बैचेंगे और कानून तो खाद्य निरीक्षक को साधने के लिए महीना दे ही रहे हैं, तो फिर डर किस बात का। फिर कानून बनाया ही गया बहुराष्ट्रीय कं. की मिलावटी स्तरहीन खाद्य सामग्री जो कि पैकेट में होती है, मनमानी कीमत पर बेची जाकर जनता को लूटा जा रहा है। इस खेल में मुख्यालय स्तर पर बैठा हर नियंत्रक करोड़ों रुपए खाकर ही किसी प्रदेश में किसी भी परिष्कृत खाद्य या खाद्य वस्तु की बिक्री हो सकती है के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। कं. बड़ी नामी कंपनियां भी उपसंचालकों और खाद्य एवं औषधि निरीक्षकों को धन बांटती है। इसी अवैध वसूली को ही लुटाकर 8-10 वर्षों तक एक ही स्थानपर डंटे रहते हैं। सिर नियम कानून इनकी और शासन के धूर्त मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव नियंत्रक सरेआम अपनी वसूली के लिए धज्जियां उड़ाते और जनता को बर्बाद करवाते हैं। जनता को लूटने और बर्बाद करने के लिए इन बहुराष्ट्रीय कं. जो खाद्य पदार्थों व औषधियां उत्पादन, पैकिंग, परिष्कृत करने का कार्य करती है। देशों की सरकारों को कानून बनवाने, संशोधन करवाने आदि को विवश करती है। धन के दम पर जैसा कि वालमार्ट, युनिलीवर आईटीसी मेक्डोनाल्ड आदि के साथ, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला अदि ने धन के दम पर कानून तो बनवाये ही साथ में उन्हें लागू करवाने, अपनी मनमर्जी के फैसले भी सर्वोच्च, उच्च व सत्र न्यायाधीशों तक को खरीद करवाने के भी बड़े खिलाड़ी है। चाहे जनता बीमारियों से मरे न मरे परंतु धनाभाव के कारण मानसिक संत्रास में अवश्य घुट-घुटकर जीने के लिए विवश है। इस संबंध में अधिकांश तथ्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 के ही प्रकाशित हुए है, जबकि बहुराष्ट्रीय दवाक कं. अपने माल की बिक्री के लिए अनाप-शनाप हजारों गुना लाभ कमाने के लिए कैसे-कैसे प्रपंच रच रही है। इसके बारे में यथार्थ में 0.01 प्रश भी भारतीय दृष्य, श्रव्य व मुद्रित प्रसार माध्यमों में नहीं छपा, जबकि कोई भी नीतिगत निर्णय लेने के अब हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत मंत्रालयों से लेकर न्यायालयों तक में डकारी जाती है।

15-16 वर्ष पहले इस देश के छोटे औषधि निर्माताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों का पालन करने के नाम पर अकेले इंदौर में 300 से ज्यादा छोटी दवाई ईकाइयां बंद कर दी गई क्योंकि ये छोटे संसाधनों से औषधियां उत्पादित कर बड़ी बहुराष्ट्रीय कं. जो युरोप और अमेरिका की थी, भारत में बिकने वाले सस्ती औषधियां के कारण माल नहीं बेच पा रहे है जबकि पूरे देश में इस प्रकार छोटी औषधियां उत्पादक कं. की संख्या लाख से ज्यादा थी, अभी हाल ही में भारतीय औषधि उत्पादकों जिनकी पूंजी 5 से 25 करोड़ थी को नष्ट करने, पुनः एक नया निर्णय मुंबई उच्च न्यायालय से पारित करवा लिया कि अब भारत में किसी भी दवा में संयुक्त यौगिकों को मिलाकर नहीं बेचा जायेगा। औषधि अलग-अलग जैसे कि बदन दर्द, सर्दी जुकाम व बुखार में भी पेरासिटामोल के साथ डिक्लोफेनाक अलग-अलग बिकेगी इससे गरीब आदमी की जेब पर दोहरा असर पड़ेगा, जो कि सीधा बहुराष्ट्रीय कं. की लाखों करोड़ दवाइयां अकेले भारत में ही बिक जायेगी, भारतीय बड़े खिलाड़ी सिपला, रेनबैक्सी, इप्का, आईजीपीएल जैसे अनेकों कं. की संयुक्त यौगिक औषधियां जिसमें दवायें, गोलियां, इंजेक्शन आदि शामिल हैं से अरबों रुपए का निर्मित औषधियों के भंडारण अगले 3-4 माह में समाप्त करना होगा, अन्यथा उसको नष्ट करना होगा। अब इसके दुष्प्रभाव देखिए। एक डॉक्टर जिसे कम्पाउंटेंड अर्थात मिश्रित यौगिकों की दवायें लिखने की पिछले 50 वर्षों से आदत पड़ी हुई थी, उनके नाम रटे हुए थे, किसी भी रोग या उससे पैदा हुई अन्य तकलीफों के लिए वह एक दवा या दो दवा लिखकर चलता कर देता था, अब पुनः भेषज विज्ञान का अपवयन कर देखेगा कि किस बीमारी में किस आयु व वजन के किस बीमार को कौन सा तत्व की वर्तमान में बाजार में उपलब्ध औषधियां कितनी-कितनी अलग-अलग किस समय दिये जाने से रोगी स्वस्थ होगा।

इन सबसे न्यायालयों को कोई मतलब नहीं उन पर तो धन और दम के प्रभाव में निर्णय दे दिया जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय को लागू करना होगा, इसके दूसरी ओर यह कांड व निर्णय औषधि निरीक्षकों से लेकर नियंत्रक व स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को करोड़पति से अरबपति बना देगा, इन भ्रष्ट निरीक्षकों को हर नई दवा और उसके तत्वों को गोली, इंजेक्शन, लेप बनाने और इसके नामकरण की आज्ञा लेने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे या निरीक्षकों को देना पड़ेंगे। स्वाभाविक है इससे लघु इकाइयां ये आज्ञायें और अनापत्ति लाखों रुपए खर्च करके लेने में असमर्थ रहेगी तो बंद करना पड़ेगी, स्वाभाविक है बड़ी व बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए आसानी से बड़ा एकाधिकारी बाजार जहां 130 करोड़ आबादी है उपलब्ध हो जायेगा। जहां उनको कोई चुनौती नहीं दे सकेगा। सरकारी शूकरों को अरबों रुपए की दवाइयां खरीदने में 25 से 50 प्रतिशत कमीशन मिलेगा। इस उठापटक में 10-20 हजार गरीब रोगी आसानी से कहां कैसे मर जायेंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा और इसकी आड़ में निजी औषधि सरकारी चिकित्सालयों चिकित्सक औषधियां परीक्षण का धंधा भी चमकाकर करोड़ों रुपए पूरे देश में कमा जायेंगे, क्योंकि आम आदमी व उसके रोगीयों को कुछ समझ ही नहीं आयेगा, जनता मरेगी, तभी तो इन गिद्धों की कमाई होगी, इनके लिए जनता कीड़े-मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं।

पूरे राष्ट्र में ये सिद्ध होने के साथ प्रकाशित भी होता रहा है, जैसा कि समयमाया 17 वर्षों से लिख रहा है कि देश में 70 प्रतिशत दूया व उससे बनी सामग्री विशुद्ध अन्य रासायनिक पदार्थों से बन रही है। यहां तक कि सांची मप्र की और अमूल गुजरात की दुग्ध व उससे बने पदार्थों की जो आपूर्ति कर रही है वह कुछ शासकीय आवासीय क्षेत्र में भरे स्तरीय दूध आपूर्ति करती हैं। बाकी आम आदमी को रुपए. 48 प्रति लीटर में भी न केवल छपे अनुसार मानक स्तर की नहीं होती। इसके विपरीत उसके नमूने नहीं लिये जाते यह बात स्वयं विभाग अपने विधानसभा में लगे प्रश्नों के उत्तर में भी लिख चुका है। निजी प्रयोगशालायें सांची और अमूल के उत्पादों के सामने से नमूने लेकर जांच करना नहीं चाहतें, क्योंकि सच बताने पर वर्षों तक न्यायालयों में चक्कर काटकर जवाब सवालों में उलझना नहीं चाहते, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धूर्त खाद्य निरीक्षक शासकीय और निगमों के महीना वसूली करते हैं तो मिल रहा है। जब तक कोई मरे नहीं तब तक चुपचाप महीना खाओ।

साप्ताहिक समय माया

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण

न जल, न विद्युत, अरबों हड़पने, उदवहन परियो

कठोरा, पुनासा, खरगोन, क्षिप्रा, उद्वहन परियोजनाओं का इतिहास और वर्तमान ही काफी था, जनधन के सैकड़ों करोड़ की बर्बादी, अपनी लूट के लिए नर्मदा गंभीर छः गांव माखन की नई योजनायें, दूध देने वाली गाय का दूध, मक्खन नहीं रक्त पी रहे जनता का

मप्र की मुखेरा जन पार्टी की सरकार जनधन को हड़पने के लिए जन हितों के नाम हजारों करोड़ रुपए अकेले नर्मदा घाटी विकास बनाम भ्रष्टाचार प्राधिकरण के नाम से अपनी मोटी कमाई के लिए बर्बाद करने पर तुली है, जिसका यथार्थ समय माया पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहा है, जैसे-जैसे सूचनायें और जानकारियां हाथ लग रही हैं। पर इस घोटालों को प्राधिकरण का पैसा चूंकि सीध मुख्यमंत्री तक स्व. अर्जुन सिंह से लेकर मामा शिवराज तक पहुंचता है, इसलिए किसी के कानों पर जिसमें राज्य प्रशासन से केन्द्रीय प्रशासन तक जूं तक नहीं रेंगती। जबकि केन्द्र शासन का नर्मदा नियंत्रण प्राधिकारी पीछे ही बैठा है। उसके अधिकारियों से लेकर केन्द्र के जल संसाधन विभाग, सचिवों से लेकर मंत्री तक को पैसा बांटा जाता है। तो वो जमीनी आंकलन, बांध और नहरों का निर्माण लागत उसकी डीपीआर, विस्थापितों का मुआवजा व निर्माण की गुणवत्ता स्तर उससे होने वाले वास्तविक लाभ-हानि का यथार्थ आंकलन कुछ भी नहीं करता, इसलिए राज्य में बैठे प्रधान सचिव, सचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो कि केवल भ्रष्टाचार से धन नोंचने के आदी हैं। आईएएस बनाम इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के ये अधिकारी जो न तो किसी विषय के विशेषज्ञ है, न इंजिनियर है, न डॉक्टर है, न समाज शास्त्री न अर्थशास्त्री इसके विपरीत चाहे वो तकनीकी विभागों यथा नर्मदा घाटी, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, सभी विद्युत कं., चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा, महिला बाल विकास, वित्त आदि सभी विभागों के सचिवों और प्रधान सचिवों पर इन्हीं धूर्त गिद्धों का बोलबाला है। जिसमें इनका काम मात्र अपने स्वार्थों के साथ ही सैकड़ों करोड़ से हजारों करोड़ रुपए का धन नोंचना है। जो इनके अधीनस्थों ने नियम-कानूनों की आड़ लेकर अपने लाभ की पढ़ा दी, इन शूकरों ने आंख भींचकर हस्ताक्षर कर देता है। फिर ये सत्ता के गलियारों के सुपर डॉबर मेन मोटा टुकड़ा हजमकर कुछ झूठन मु.मं. मंत्री को डालकर स्वयं मोटा हिस्सा डकार जाते हैं। फिर भाजपा उर्फ मुखेरा जनता पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज की दो विशेषतायें जनधन की बर्बादी के लिए कि बजट के साथ भी वित्तीय मांगों के अनुपूरक बजट और दूसरी अधिकांश विधानसभा सत्रों का उद्देश्य सदन में भी अनुपूरक बजट मांगों को उचित सिद्ध कर भी धन हड़पना ही होता है। जैसे ही अनुपूरक मांगे पूरी हुई येन-केन प्रकरेण नूरा कुश्ती के जरिये सत्र को अनिश्चितकाल के लिए समाप्त कर दिया जाता है, ताकि अपने भ्रष्टाचारों के जवाब जो कि अधिकांश 50 से 90 प्रश झूठे आंकड़ों की बाजीगरी के होते है।

इसमें फिर नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के भी अधिकांश वित्तीय फैसलों का मूल उद्देश्य काम की अपेक्षा काम की आड़ में केवल लूट होता है। इस यथार्थ को समय माया पिछले 15 वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहा है। झूठा, मक्कार, हरामखोर, जालसाज, सत्ताधीशों की भ्रष्टाचार के अंधों को कुछ नहीं दिख रहा।

बरगी बांध, उसकी दायी-बायीं नहरों, इंदिरा सागर की इंदिरा नहर ओंकारेश्वर की उसकी दायीं बायी नहरों में बहने वाले पानी को उसकी पूंछ तक अर्थात अंतिम छोर तक बनाई गई नहरों के हिसाब से ही पूर्व में ही सरंचना तैयार कर दी गई थी, तो फिर उदवहन सिंचाई परियोजनायें जो हजारों करोड़ की बताई जा रही है, उनके लिए पानी और फिर जल को 120 समुंद्र तल की ऊंचाई से उठाकर 250, 300, 450, 470 समुद्र तल से ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बिजली और उसके बिल का भुगतान की समस्या कैसे पूरी होगी। पूर्व में बनी कठोरा, पुनासा, क्षिप्रा लिंक परियोजनाओं के हाल ही देख लेते जिसमें कठोरा खरगोन में सन् 2000 के आसपास यह योजना मात्र रुपए 150 करोड़ की थी, बनते रुपए 300 करोड़ पपिंग, नहरों आदि में खर्च कर खरगोन जिले की 7000 है भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य था, मात्र 4000 है. क्षेत्र में ही सिंचाई हो पा रही है। जबकि इंदिरा सागर की नहर से पूर्ण लक्ष्य 1,23,000 है. में कृषि को सिंचित करना था। 1 है. भूमि को सिंचित करने के लिए 2 व्यूमेक पानी की आवश्यकता होती है। पुनासा उदवहन परियोजना जिसमें 35000 है. में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया रु. 660 करोड़ की लागत की ये परियोजना बनते-बनते रुपए 800 करोड़ से ज्यादा की हो गई, खरगोन परियोजना जिसका लक्ष्य 25000 है. में सिंचाई करना था, रुपए 550 करोड़ की पूर्ण होते-होते 700 करोड़ की अर्थात 67000 है। 1,34,000 क्यूमेक पानी निकाल लिया गया, अर्थात 1,23,000 है. में से 67000 है. सिंचाई हेतु पानी को नहर में से उदवहन किया गया, इसके बाद में छेगांव माखन रुपए 897 करोड़ की 20000 है. और सडमा की रुपए 300 करोड़ की दो नई परियोजनायें और बना दी गई, सड़मा का भी लक्ष्य 6000 है का है। 90000 है. में सिंचाई के नाम पर जो अतिरिक्त परियोजनायें लादी गई, तो ठीक है कि बिजली तो आप खरीद लोगे, जबकि 1.23 लाख है. में सिंचाई तक होगी जबकि समुद्र तल से 262.19 मी. तक इंदिरा सागर बांध भरा जायेगा और उसकी 7.90 एमएएफ अधिकतम क्षमता होगी, जबकि अभी मात्र 245.17 मीटर तक ही भरा गया है और उसके चारों 250 में.वा. के चारों टर्बाइन चलाकर विद्युत उत्पादन करेंगे। बांध की नियोजित ऊंचाई कुल 92 मी. तक से जो 170.19 मी. है,जब अभी 17 मी. कम भराव पर है। स्वाभाविक है कि लगभग 20 प्रश कम पानी भरे जाने के कारण 1.23 लाख है. से घटकर 96000 है. में ही कृषि सिंचाई की जा सकती है उस पर भी 90000 है. की सिंचाई का जल, उदवहन कर खींच लिया जायेगा तो क्या इंदिरा सागर नहर जो खंडवा, खरगोन, धार से बड़वानी जिले तक 190 किमी तक लंबी बनाई जाने के उपरांत भी मात्र 600 है. में ही सिंचाई कर पायेगी, तो फिर इन धन के क्यों हजारों करोड़ बर्बाद कर 190 किमी लंबी नहर बिछाई जब आपको खंडवा और खरगोन जिलों में ही 90000 है. सिंचाई करना थी।

लोकसभा और विधानसभा में बैठे पैसों के भूखेरे धूर्त सांसदों और विधायकों को ये सत्ताधीशों की लूट नहीं दिख रही, हजारों करोड़ की बर्बादी पर ये विपक्षी सत्ताधीशों से क्यों नहीं पूछते कि जब पानी ही नहीं तो हजारों करोड़ जन-धन के बर्बाद किये जा रहे है। यही हाल बरगी की दायीं-बायीं नहरों में भी हुआ जहां नहरों की लाइनिंग के लिए रुपए 668 करोड़ 1997 में स्वीकृत हुये और समाप्त भी हो गये और नहरों में अभी भी सीमेंट कांक्रीट का लाइनिंग नहीं हुआ, जबकि दायीं नहर जबलपुर से निकलकर सतना मंडला तक जाती है और बायी तट नहर गोटे गांव तक जाती है। कई ठेकेदार करोड़पति बन गये है, इंजिनियरों के साथ-साथ।

अब ओंकारेश्वर की दायी-बायी नहरों भ्रष्टाचार को समय माया 2006 से लगातार प्रकाशित कर रहा है। परंतु 17वें समय विस्तार के साथ काम पूरा नहीं हुआ, जबकि टर्न की ठेके थे, जिसमें न समय वृद्धि मिलनी थी न महंगाई का भुगतान, इसके विपरीत बहानों की आड़ लेकर न केवल समय वृद्धि दी, महंगाई का भुगतान भी किया, गुणवत्ता पूर्ण कार्य न होने के कारण कार्य पूरा होने से पहले ही न केवल तल पर आजू-बाजू की दीवारें भी चटक गई जबकि डीपीआर में 10 सेमी मोटी क्रांकीट लोहे की जाली के साथ डाली थी, गारंटी पिरियड तो पूर्ण होने के पूर्व ही समाप्त हो चुका था, ढाई साल का काम प्रथम चरण का 10 वर्ष में पूरा न होना, विस्तार पर विस्तार देकर महंगाई का भुगतान कर सबका हिस्सा डकारना। घाटी के भ्रष्टाचार के शिखर दर्शन करवाने के साथ प्रदेश के जन-धन की बर्बादी भी करता है।

ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत गृह 4.5 मेगावाट (2×1.75 बराबर 3.5 के साथ 28.8 प्रश सतह के केप्टिव पॉवर प्लांट की पुनरावृत्ति स्वीकृति रुपए 439 करोड़ की स्वीकृति, नर्मदा नियंत्रण की 38वीं बैठक 15.02.2014 में दी गई, कुल 20 प्रश हजम करन का मार्जिन इसी बैठक में ओंकारेश्वर नहर परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रुपए 2921.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई। वास्तविक कार्य रुपए 1000 करोड़ लगभग रुपए 1921.54 करोड़ सीधे हजम करने के लिए, जिसका उदाहरण ओंकारेश्वर की दायीं और बायीं तट नहरों के निर्माण से देखा जा सकता है। मान परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासन स्वीकृति रुपए 246-03 करोड़ और जोबट की रुपए 230.61 करोड़ स्वीकृति की गई, पुनरीक्षित का 50 से 70 प्रश केवल हजमकर 43वीं बैठक में नर्मदा क्षिप्रा लिंक के लिए 12.10.12 के रुपए 432 करोड़ स्वीकृत किये। कार्य रुपए 396.34 करोड़ की मेघा इंजिनियर्स हैदराबाद को दिया।

46वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक योजना की प्र.स्वी. रुपए 2153.46 करोड़ की 47वीं बैठक में 17.06.14 को डाबरी उदवहन सिंचाई परियोजना की लागत राशि रुपए 56-50 करोड़ की 47वीं बैठक दिनांक 17.06.14 को ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत स्वतंत्र जल निकासी के अति उच्च। उच्च प्राथमिकता के जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार कार्य हेतु रुपए 15549.54 करोड़ स्वीकृत प्रदान कर 90 प्रश पैसा हजम कर लिया जायेगा क्योंकि 9 महीने उपचार कागजों पर दिखाकर 3 माह की बरसात में सब बाढ़ में बहना और साफ हो जाना बताया जायेगा।

50 वीं बैठक 16.02.2015 को 38वीं बैठक में ओंकारेश्वर परियोजना की ईकाइ 2 में 38वीं बैठक में स्वीकृत रुपए 2925.54 करोड़ की लागत बढ़ाकर रुपए 4116.22 करोड़ की स्वीकृति अर्थात मात्र 4 वर्ष में 42 प्रश लागत बढ़ा दी गई, ये है, भाव वृद्धि की आड़ में लूट का तांडव 51 वीं बैठक 09.07.2015 में नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना नदी में प्रवाह मार्ग जो कि सोनवाय में पाइप लाइन से फिर खुली कहीं 10 चौड़ी तो कहीं चौड़े तल और ऊपर की कहीं 10', कहीं 15', 18' चौड़ी नहर में दो पुलियां दिखती है, जिनकी लागत मात्र अधिकतम रुपए 15 से 20 लाख नहीं हो सकती के लिए रुपए 2.3450 करोड़ की स्वीकृति दी गई जिसमें से 80 प्रश पैसा हजम, जबकि सोनवाय में जहां तक 1.80 डायमीटर की वह पाइप लाइन वहां आते तक लगभग 1.2 मीटर ही रह गई साथ ही वहां से भी क्षिप्रा के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अब जहां वर्षों से खेती हो रही है की वास्तविकता जानने, पुनः प्राकृतिक बहाव को पुनः जीवित करने का कलम कागज विवाद न.घा.वि.प्रा. और इंदौर के जिलाधीश से लेकर पटवारी तक दो वर्ष से जारी है। 51वीं बैठक दिनांक 29.07.15 में सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत नर्मदा कावेरी लिंक चैनल निर्माण कार्य हेतु रुपए 54.07 लाख स्वीकृत हुये, जबकि कार्य मात्र रुपए 10 से 15 लाख का ही था। इसी बैठक में ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर दायें बायें तरफ 4 घाटों के निर्माण में रुपए 9.23 करोड़ स्वीकृत हुए, जबकि वहां मप्र जल संसाधन मंडल के खरगोन संभाग और मप्र लोक निर्माण संभाग खरगोन ने भी घाट निर्माण किये, जबकि वहां दायें बायें दोनों तरफ पुल से 400 मीटत तक पहले से भी घाट बने हुये थे, जबकि कीमत नये बनाने पर भी दो करोड़ इसी बैठक में अलीराजपुर उदवहन सिंचाई परियोजना की लागत रुपए 582.8 करोड़ स्वीकृत की गई, स्वाभाविक है रुपए 100 से 150 हजम किया ही जायेगा, जोबट विस्तार सूक्ष्म सिंचाई लागत रुपए 156.58 लाख स्वीकृत कार्य मात्र रुपए 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा।52वीं बैठक 18.01.2016 में बलबाड़ा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु रुपए 52-78 करोड़ स्वीकृत कार्य मात्र रुपए 10 से 15 करोड़ का, भैरव पहाड़ी के कटाव रोकने दायीं और दीवार का निर्माण हेतु रुपए 12.96 करोड़, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परि. 5000 है. सिंचाई के लिये रुपए 2167.21 करोड़ स्वीकृत।

समय विस्तार और भाव वृद्धि भुगतान का खेल और आंदोलनों की ठेकेदारों के साथ भूमिका

निचली नर्मदा परियोजनाओं व इंदिरा सागर नहरों, ऊपरी नर्मदा परियोजना व रा.अ. चई सागर या बरगी दाई-बाई नहरों में भी समय वृद्धि और भाव वृद्धि से विभागीय इंजिनियरों से लेकर ये खेल मुख्यमंत्री कार्यालय तक फैला हुआ है, जिसमें एक तरफ जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जो पेट्रोल डीजल में गैस में पूरे देश में सबसे ज्यादा 32 प्रश तक लूट कर इन ठेकेदारों को लुटाकर स्वयं भी लूटी जा रही है, तो वही दूसरी और निश्चित समय में कार्य न होने से अरबों रुपए मुआवजे में लुटाने के बाद भी न तो समय पर सिंचाई हुई, जिससे अरबों रुपए का कृषि फसलों के उत्पादन का नुकसान हुआ तो अरबों रुपए की बिजली अरबों रुपए की बिजली का भी उत्पादन नहीं हो

सूचना के अधिकार में देने में घोर जालस

किसी भी विभाग की कार्यशैली नापने का सबसे बड़ा पैमाना बन चुक नर्मदा घाटी के भोपाल मुख्यालय में बैठे धूर्तों और भ्रष्टों जिसमें उपाध्यक्ष परियोजना नहरें और इंदिरा सागर नहरों के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण सतना, कटनी, गोटेगांव, मंडला, भोपाल का 23 नंबर संभाग, मंडलेश्व ठीकरी, बड़वानी, धरमपुरी, मनावर, पुनासा 25 व 27 आदि के कार्यपा जालसाज, जानकारी देने के नाम पर, ये शूकरों की फौज हर कदम-कदम करती है। समय पर पत्र दे दिया तो पैसे जमा नहीं करेंगे, आवेदक ने पै कटवायेंगे, जानकारी दे भी दी तो आधी-अधूरी, यहां तक कि मुख्य अभि जमा किये दो माह से ज्यादा गुजर गये, हरामखोर जानकारी देने को तैया जबकि यहां भी करन सिंग और बियानी जैसे ठेकेदारों की समय वृद्धि और भ बाद भी वृहतः लघुव वितरणी नहरों का कार्य अधूरा है। जिसमें सनावद का ठीकरी में तो धन हड़पने के लिए नहरों के केन्द्रीय जल आयोग की मूल रू अधूरा और स्तरहीन निर्माण कार्य करवा डाले।

यथार्थ में नर्मदा, घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण लूट और भ्रष्टाचार की मु.मं. शिवराज मंत्रियों उपाध्यक्ष वैश्य से लेकर नीचे उपयंत्रियों और वन विभ भ्रष्टाचार का अरबों रुपए का दूध दोहन के साथ शासकीय पदों पर बैठकर लूटे गए धन पर। जालसाजी की जादूगरी के बड़े-बड़े अजूबे नमूने भी उ दिल्ली के नर्मदा भवन विश्राम में भोपाल के 23 नंबर संभाग में पदस्थ है भोजन और रखरखाव के झूठे बिलों से हजम पिछले 15 वर्षों से ज्यादा स धामनोद में सहा. यंत्री भी बनाकर मात्र कमाई, मोटे कमीशन के लिए उच बैठाया गया । वह शूकर यहां आकर बिलों पर व अन्य कागजातों पर अपन फुर्र हो जाता है दिल्ली।

ोजनायें

सका जैसा कि मंडलेश्वर बांध के मामले में 18 वर्ष से हो रहा है, इन सबके विपरीत लागत में बढ़ोत्तरी से, जनता से लूट भी बढ़ी, परंतु मु.मं. चौहान से लेकर मंत्री, उपाध्यक्ष व प्रधान सचिव रजनीश वैश्य जैसे भ्रष्ट धूर्तों से लेकर जो छः वर्षों से ज्यादा समय से एक ही पद पर कुंडली मारे जमा हुआ है के साथ सदस्य अभियांत्रिकीय, मुख्य अभियंता अजनारे जिसके अंतर्गत 32 नंबर संभाग में सबसे ज्यादा समय वृद्धि प्रकरण जिसमें दायीं तट नहर द्वितीय चरण में सोम दत्त बिल्डर्स के करण सिंग जैसे धूर्त मक्कार को 17 और 10 समय वृद्धि की आड़ में लागत वृद्धि में मोटा कमीशन करोड़ों का डकारा गया, इस समय वृद्धि के लिए आंदोलनों की आमग में धन के घी ये ठेकेदार ही झोंककर अपनी मोटी कमाई करते हैं, जबकि दूसरे समय वृद्धि के बाद से ही ये मक्कार और भ्रष्ट कार्यपालन यंत्री 8,3220 व अन्य सभी चाहते तो ठेका निरस्ती कर लागत और जोखिम पर नई निविदायें लगाकर अन्य ठेकेदारों से कार्य संपन्न करवा सकते थे, परंतु न केवल कार्य पालन यंत्री तो फिर भी समझदार थे पर अधीक्षण यंत्री तो ढूंढ-ढूंढ कर ऐसे मूढ़ बैठाये गये जो, संलग्न सहा. यंत्रियों के इशारे पर अंगूठा लगाते थे वही हाल मुख्य अभियंता अजनाने का भी था, जो कि 8 वर्षों से इंदौर में जमा रह पूर्व में तो अधीक्षण यंत्री का भी प्रभार संभाले था, इसके पीछे एक ही खेल था अरबों रुपए का भ्रष्टाचार का धन डकारने के लिए इन मूढ़ों की पद की वैधानिकता का उपयोग करना, अ.स. शिवहरे व अ.य. तोमर को 3 बार संविदा युक्तियां दी गई।

जानकारी
ाजियां

ा है सूचना का अधिकार कानून-05, रजनीश वैश्य से लेकर ऊपरी नर्मदा ा यंत्रियों से लेकर जबलपुर, नागोद, र, सनावद का 21 नंबर, खरगोन, लन यंत्रियों से जानकारी मांगने पर ये पर आवेदक को हर तरह से परेशान सा जमा कर दिया तो पचासों चक्कर यंता रोहित रमेश इं.सा. नहरों में पैसा र भी नहीं और फोन भी नहीं उठाता। ाव वृद्धियां दे-देकर हजम कर जाने के 21, पुनासा का 25 व 27, खरगोन, पांकन व बदलकर ही नहरों का आधा-

ी दूधारू गिर गायें बन चुकी है, जिसमें ाग जो क्षतिपूर्ति वन विकास में लगे हैं। सत्ता सुख भोगने में मस्त है। जनता से पलब्ध है। एक उपयंत्री कटारिया जो । लाखों रुपए महीने के फर्जी धुलाई, मय से कर रहा था। उसे नहर संभाग च्चाधिकारी की औलाद होने के कारण ना अंगूठा लगाता है, हिस्सा लेता और

किसान आत्महत्या कर रहे, कृषि विभाग भ्रष्टाचार का तांडव

मु.मं., प्र.सं. से लेकर कृषि मंत्री, संचालक तक सब करने लगे है, वसूली में। निलंबन, बहाली फिर पदोन्नतियां भी मोटी कमाई का खेल है, राजोरा का। फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी और पदौन्नति प्राप्त उ.स.मीणा सूचना के अधिकार में जानकारी देने की अपेक्षा 5 पेज की उल्टें ही स्वयं शिकायतें करते, हाथ पैर तोड़ने की धमकी देकर क्षमा मांगते है, रुपए 40000 करोड़ से ज्यादा केन्द्र और राज्यों के बजट से आधा हजम कर जाते है। प्र.स. से लेकर ग्रा.कृ.वि. अधिकारी तक, मु.मं. से नीचे तक सबकी हिस्सेदारी, सबचुप।

मप्र में अकेले मुखेरा जन पार्टी के 13 वर्षों के शासन काल में ही कृषि विभाग के भ्रष्टाचार और जालसाजियों के चलते पूरे प्रदेश में 10 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, पर हर जिले के आत्महत्या के बाद हर मामले को दबाने और लीपापोती की गई, जबकि देशभर में यह आंकड़ा दस लाख से ज्यादा है। दूसरी और सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की,सरकार में बैठे धूर्त मक्कार आईएएस से लेकर नीचे तक बैठे हर अधिकारी और कर्मचारी को भ्रष्टाचार से लूटने और कार्य करने की शैली में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टे ही वह यह जानता है कि हर नई सरकार में बैठने वाला हर मंत्री खर्च करके मंत्री बना है,तो उसे भ्रष्टाचार से कमाये गये धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए तो स्वयं भ्रष्टों को पाल पोसकर ज्यादा वसूली करेगा, इसलिए भ्रष्ट और ज्यादा प्रसन्न नजर आते हैं, यहां तक कि जो भ्रष्ट अधिकारी फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी पाकर, पदोन्नति लेकर उपसंचालक बन बैठे हैं। वो हरामखोर अपने जाति प्रमाण और मूल निवासी प्रमाण पत्र न देने के लिए लाखों रुपए हर साल खर्च करके अपने इस जालसाजी पूर्ण कृत्य को दबाने के लिए अपने मुख्यालय से लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग में भी खर्च करते चले आ रहे हैं। तो आखिर क्यों अगर ईमानदार हैं तो जाति प्रमाण की प्रतियां आवेदक को तत्काल जानकारी मांगने पर पिछले 10 वर्षों से क्यों हर कार्यालय में टाला जा रहा है। फिर जानकारी मांगने पर न देकर 4-6 पेजों की दलीलें देना, स्वयं सिद्ध करता है कि अपन कितने भ्रष्ट, जालसाज और नियम कानूनों की धज्जियां बिखेरने में न केवल स्वयं अपनी वरन जन धन से चलने वाली सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने में माहिर हरामखोर हैं। उपसंचालक मीना पहले अपने गिरेबां में झांककर अपना आत्मावलोकन कर लिया होता। बेशक ये खूबियां केवल आप में ही नहीं, पूरी भाजपा की सरकार से लेकर हर मंत्रालयों में पाई जाती है। जिस प्रधान सचिव राजेश राजौरा पर लोकायुक्त की आय से अधिक संपत्ति मामले लंबित हो फिर संचालक मोहन लाल मीणा जिन्हें अपने अधिकार और दायित्वों का बोध न हो जो संयुक्त संचालकों की अपील सुनने और निर्णय देने की पात्रता ही न जानता हो उससे क्या उम्मीद की जाये, उसको दो अपीलें इंदौर/उज्जैन के संयुक्त संचालकों के विरूद्ध भेजी गई, महीने भर अपील की सुनवाई की अपेक्षा निकम्में और हरामखोर जवाब देता है कि सुनने की पात्रता ही नहीं रखता है, परंतु जालसाजी करते हुए अपने भ्रष्टाचारों को दबाने दोनों अनावेदकों से पैसा हजम कर उन्हें बचाने कि लिए न तो अपील ही लौटाता है और न ही पत्रोत्तर में ये बताता है कि अपील सुनने का पात्र कौन है। आखिर ये हरामखोर, मक्कारों, भ्रष्ट शूकरों की फौज सूचना के अधिकार पर से क्यों इतना भयभीत है, बेशक भयभीत तो सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री कार्यालय भी है, प्रयास भी किये गये है कि किसी प्रकार इस कानून को रद्द कर दिया जाये, तो 56 इंच सीना भी दमा पीड़ित है हांपने लगता है। इस कानून का सबसे ज्यादा बलात्कार भ्रष्टों को बचाने जालसाजियों को छुपाने में इस राष्ट्र के परम विश्वास की बागडोर संभालने वाले आम से खास हुए न्यायाधीशों ने ही किया है।

मोदी के सत्ता संभालने के बाद चारों तरफ बर्बादी का तांडव हो रहा है चाहे वो सरकारी विभाग हो जालसाज निजी क्षेत्र की खाद, बीज कीटनाशक फफूंदनाशक कं. के उत्पाद हो, सबके भ्रष्टाचारों ने किसानों को सबसे ज्यादा बर्बादी का कारण बने ऊपर से इस पाखंडी नौटंकी बाज मोदी की खोटी नियत का, प्राकृतिक कहर का परिणाम भी किसानों ने ही भुगता या तो पानी नहीं गिरा, तो फसलों की बुआई विलंब से हुई, इस बार बुआई के समय पानी गिर भी गया तो पौधे और फूलों के आने बाद सूखा पड़ा तो भी फसले सूखी किसानों ने येन-केन प्रकरेण सिंचाई भी करके फसलों को पका भी लिया तो पकी पकाई फसलों के कटने से पहले पानी गिर जाने से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, इससे स्वाभाविक था किसान ही नुकसान में रहा, कहां गया मोदी का फसल बीमा

मप्र के कृषि विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार के तांडव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केन्द्र व राज्य सरकार के धन से कृषि फसलों के आबंटित धन जिसमें खाद, बीज, कीटनाशकों फव्वारा सिंचाई के लिए फव्वारों पाइप लाइन, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, तालाब बनवाने व अन्य कार्यों के लिए आवंटित धन, सामग्री, अनुदान, खरीदी, अनुज्ञप्ति जारी करने आदि में हुए भ्रष्टाचारों के कारण इसी प्र.स. राजेश राजौरा ने वसूली बढ़ाने और धमकाने के लिए 8-10 उपसंचालकों को निलंबित कर दिया था, फिर मोटी वसूली के बाद न केवल उन सबको बहालकर पदोन्नति भी दे दी गई और उन्हें संयुक्त संचालक बनाकर मैदानी पदस्थापनायें दे दी गई, इसके साथ ही अपने खास चहेते को चूंकि इंदौर में रहने साढ़े तीन वर्ष से ज्यादा हो जाने के इंदौर के पास देवास में पदस्थ कर दिया जो इसके लिए इंदौर में कंपनी के मुख्यालय प्रादेशिक बनाकर पूरे मप्र में स्तरहीन खाद, बीज कीटनाशकों आदि का व्यापार कर रही है। से मोटी वसूली कर ऊपर पहुंचाता था इसके पूर्व शाजापुर में भी भारी कांड किए। शाजापुर, इंदौर में किए कांडों के बारें में समयमाया पूर्व में भी छाप चुका था, इसलिए सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के नाम पर जानकारी देने की अपेक्षा उल्टे ही वो जानकारी मांगने की शिकायत कलेक्टर कमिश्नर को करने का पत्र भेजा अर्थात अपने कुकर्मों की लंबी सूची को छुपाने आखिर जवाब देकर पैसे मांगने की अपेक्षा 5 पन्ने की व्यर्थ और औचित्यहीन दलीले देकर भ्रष्ट, जालसाज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, जैसे सारा विभाग इन हरामखोरों के बाप की जागीर हो, कानून इन शूकरों की रखैल, फिर क्यों अनु. जाति, जनजाति आयोग की जांच दबाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। क्यों नहीं पिछले साढ़े तीन साल से जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं दे रहा, यदि ईमानदार है तो मांगने पर दे देना चाहिये। 60 प्रश से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर भर्ती किए और पदोन्नति भी ले रहे है। दूसरी तरफ शासन ने जनता के धन से वेतन बांटकर कृषकों के कल्याण और कृषि विकास के लिए बैठाया था उसके बदले जन-धन से वेतन के अतिरिक्त स्वकल्याण और विकास में लगा है। न केवल ये सब कृषि अधिकारी वरन मु.मं., कृषि मंत्री बिसेन व अन्य सभी। भारतीय अर्थशास्त्र में कृषकों के बारे में जो शिक्षा ग्रहण करते समय पढ़ा था, कि भारतीय कृषक कर्ज में जन्मता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही इन भ्रष्ट जालसाजों के कारण मर जाता है।

आयोडीन नमक है घातक बीमारियों का कारण

भारत में पूंजीपतियों के पोषण और आमजन के शोषण के लिए इंदिरा गांधीजी ने आयोडीन नमक कानून 1972 में टाटा से मोटी रिश्वत खाकर ही टाटा केमिकल लि. को लाभ पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था, जिसके दुष्परिणाम 1975-76 के बाद से ही आने शुरू हो गए थे, जब मधुमेह, ह्दयघात,गुर्दे, यकृत के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि होना शुरू हो गई थी, जब भाजपा विपक्ष में थी तो विरोध करती थी आयोडीन नमक का और अब सत्ता में आने के बाद से रुपए 1000 से 5000 करोड़ की राशि मिलने के बाद से चुप है, जबकि उसके बदले में सरकार केन्द्र व राज्य मिलकर रुपए 25 से 30 लाख करोड़ खर्च कर रही है, हर वर्ष पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारत में घेंघा रोग छत्तीसगढ़ और हिमालय की तराई के कुल मिलाकर 25 से 30 लाख लोग पीड़ित थे उनको आयोडिन खिलाने के नाम वर्तमान में भी 130 करोड़ की आबादी की मोटी कमाई के लिए अनावश्यक रूप से 50 पैसे किलो के नमक को रुपए 25 प्रति किलो खिलाकर, जबकि आवश्यक आयोडीन हरी पत्तेदार सब्जियों आदि में मिल जाता है। क्योंकि आयोडिन का आधिक्य रक्त शिराओं और रक्त वाहनियों को तो कमजोर कर आंतरिक क्षरण पैदा करता है, साथ ही अंतः स्त्रावी ग्रंथियों जिसमें पिटयुटरी ग्रंथि की कार्यप्रणाली कमजोर, बाधित व क्षतिग्रस्त करने से शरीर के मुख्य अंग यथा मस्तिष्क ह्दय, यकृत, प्लीहा, गुर्दे, जननागों की बाधित कार्यप्रणाली इन सारे अंगों को कार्यक्षमता घटाने के साथ मूल रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर करती है। जिससे ये अंग युवावस्था से ही कमजोर होने लगते हैं। पूंजीपतियों के टुकड़खोर राजनीतिज्ञ स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मु.मं. प्रधान सचिव, सचिव स्वास्थ्य, आयुक्त आदि को ये आयोडिन नमक तत्काल बंद करवा देना चाहिए, इसके परिणाम भी 5 वर्ष बाद आना शुरू होंगे। जब सभी घातक बीमारियों के मरीजों की संख्या में गिरावटे आयेगी।

विद्युत के लिए नेता और अधिकारी की लूट और परेशान कर रहे उपभोक्ता को

पृष्ठ 12 का शेष

मीटर वाचक सबकी कमाई लाखों रुपए से करोड़ों रुपए में होती है। इसीलिए हरामखोर प्र.सं. आकाश त्रिपाठी जिसने सांसद सुमित्रा महाजन को झूठे ही साढ़े चार लाख वोंटो से फर्जी तरीके से जितवाया जबकि यथार्थ में 25000 वोटो से भी नहीं जीती, बिना सारी मशीनों की एक्सेल शीट बने ही परिणाम घोषित किए। बदले में स्थानांतरण के स्थान पर उसे इंदौर में विद्युत कं. को लूटने और बेटों को लूट की व्यवस्था कर जनता को ठगने का षड़यंत्र चल रहा है। इतनी लूट के बाद भी जनता से करों में लूटे गये धन में से रुपए 40000 करोड़ रुपए केन्द्र व राज्य का लेकर विभिन्न योजनाओं का भी हड़प लिया गया, कभी फीडर संपरेशन कभी दिनदयाल विद्युत योजना के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की गई, जबकि 17500 मेगावाट उत्पादन विद्युत जल व कोयले की इसके बाद सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, की भी लगभग 2000 मेवा विद्युत प्रदेश में आपूर्ति की जाने के बाद सालभर ये हरामखोर की फौज रखरखाव के नाम कभी गांवों की कभी शहरों की विद्युत आपूर्ति बाधिक करते है।

किसी गरीब के झोपड़े या दो कमरे के मकान में हजारों के बिल, तो कहीं 5 मंजिल के भागीरथपुरा के फर्शी वाली गली में एक के मकान में 40 किरायेदारों के भवन में मीटर रीडर्स रुपए 500 से 1000 का ही बिल देकर लाखों रुपए प्रति माह की कमाई करते है। ये ही हाल बड़ी फैक्ट्रियों, भवनों व्यावसायिक संस्थाओं में पूरे प्रदेश में किया जाकर अरबों रुपए की बिजली चोरी करवाकर ऊपर के ऊपर हजम किये जा रहे है। वसूली की भरपाई करने के लिए, और हजारों करोड़ के झूठे और फर्जी बिलों जो कार्यों, खरीद, आउटसोर्सिंग, ठेके के कर्मियों को पर बिना प्रशिक्षित किए उच्च दामों, निम्न दाब विद्युत केन्द्रों पर दैनिक वेतन भत्तों से कम वेतन पर बेरोजगारों का शोषण कर ठेकेदार और अधिकारियों के प्रति कर्मचारी 15 से 40 प्रश वेतन डकार रहे है। 90 प्रश ट्रांसफार्मर लाइनों, खंभों का स्तरहीन सामग्री से रखरखाव कर अरबों रुपए का धन हड़पा जा रहा है। अधिकांश कार्यो में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसलिए अंकेक्षण भी नहीं करवा रही है। ये कंपनियां और सरकार जानबूझकर हजारों गुना वसूली किए जाने के बाद भी हर वर्ष हजारों करोड़ के घाटे और लाइन लॉस दिखाकर, बैलेंस शीट में कर्जा, घाटा दिखाकर हरामखोरों की फौज हर वर्ष दो बार बिजली की कीमतें भी बढ़ा रही हैं।

सेवानिवृत्त यंत्रियों, राज्य प्रशासनिक और केन्द्र प्रताड़ना सेवा के अधिकारियों को बैठाकर जिन्हें न तो व्यावसायिक और न तकनीकी ज्ञान होता है। कंपनियां चलाई जा रही है। जो पूरी विद्युत मंडलों की जमी जमाई व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर निजी हाथों में सौंपना चाहती है। ग्वालियर के फ्लॉप शो से भी गिद्धों को अक्ल नहीं आई। वैसे भारतीय व राज्य की प्रश प्रताड़ना सेवायें केवल प्रताड़ना देकर लूटपाट करना जानती है। न ये शूकरों की फौज व्यवसाय कर सकती है, न प्रशासन चला सकती है। बेहतर जनता प्रदेश और देश के भविष्य के लिए ये कंपनियां तत्काल समाप्त कर पुनः विद्युत मंडल की बहाली की जाये और नऐ स्थाई इंजिनियर, तकनिशियनों अधिकारियों, कर्मचारियों की भर्ती की जाये, जो नये चार्टड बनाम करप्ट अकाउंटेंट्स कार्यरत है। उन्हें इन जालसाजों ने कठपुतली बनाके रखा हुआ है। जैसा ये नचाते है, कहते हैं वो बेचारे करते है। ये घाटा दिखाने और लूट की साजिशों को भी नियमित करते है।

साप्ताहिक समय माया

27 सितम्बर के पूर्व व पश्चात का इतिहास देखो, राष्ट्र प्रेम नहीं, पाखंडी नेता

प्रथम पृष्ठ का शेष

अमेरिकी दादागिरी को चीनी चुरकट न केवल बाजारवाद में वरन् हर क्षेत्र में मात देने के साथ, सामारिक क्षेत्र में भी अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहे। बेशक चीन भारत का चिर शत्रु है उसकी सामरिक आर्थिक, महत्वकांक्षा भारत को हर तरह से क्षति पहुंचाने की ही रही है। इस दृष्टिकोण से शत्रु का शत्रु, शत्रु का मित्र बन ही जाता है। भारत अमेरिका का एक दूसरे के प्रति झुकाव, लगाव, दोस्ती ठीक और आवश्यक थी और है। इसके विपरीत अमेरिका का इतिहास निहायत घिनौना है। अमेरिका पूरी दुनिया के गुंडे बदमाशों, अपराधियों से पैदा हुई वर्तमान फौज जिसके हर काम कदम में विशुद्ध धूर्तता, चालाकी और मक्कारी भरी होती है। वो किसी का सगा नहीं हुआ, यदि सचमुच ही भारत में दोस्ती का ढोंग भी कर रहा है। तो तत्काल उसे पाक को हर तरह की सहायता देनी बंद कर देना चाहिए थी, जो उसने नहीं की, दूसरी ओर पाक में हो रहे सिंध पंजाब बलोचिस्तान में हो रहे, हिंदुओं के कत्लेआम, मानवाधिकारों कें उल्लंघन का मामला भी नहीं उठाया उल्टे ही बलूचिस्तान को पाक का अभिन्न अंग कहकर उसने धूर्तता और दक्षिण एशिया में अपने हथियारों के बाजार को ही गर्म रखने के लिए पाक के पक्ष में ही शिगूफे छोड़े, पाक अधिकृत काश्मीर में भी हो रहे जनशोषण के मामले पर भी चुप्पी साध रखी है। फिर अमेरिका जो भारत 25000 किमी दूर बैठा है, भारत के बाजार के दोहन के अतिरिक्त उसके लिए भारत की क्या उपयोगिता है। भारत के वहां कोई शत्रु भी नहीं, फिर अमेरिकी दोस्ती के नाटक ने रूस जो कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, पाक की सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास किया। स्वाभाविक है कि भविष्य में रूस चीन और पाक मिलकर भारत पर आक्रमण करें, रूस आक्रमण न भी करे तो उसे भारत के हर सैन्य अड्डे की जानकारी पहले से ही है, वह जानकारी वह चीन और पाक से साझा करे और युद्ध के समय अप्रत्यक्ष रूप से नैपथ्य से सहयोग के चलते ईरान को 10 वर्ष तक अप्रत्यक्ष सहयोग किया। अमेरिका और ईराक को युद्ध विराम के लिए बाध्यकार दिया था, यदि भविष्य में युद्ध हुआ तो भारत को नीचा दिखाने अमेरिकी सहयोग मिले न मिले परंतु रूस और चीन पाक को सहयोग कर राष्ट्र के लिए भारी खतरा बन जायेंगे, यह तो पक्का ही है कि पाक से हर हाल में युद्ध करना होगा, सीधे युद्ध में उसके साथ चीन अवश्य होगा, फिर अमेरिका उल्टे ही भारत के सैन्य स्थलों के नक्शे, पाक को अपने पक्ष में लाने के लिए इन सैन्य अड्डों की पूरी जानकारी पाक से साझा करेगा।

पाक को अंध सहयोग- भारत का चीन के विरूद्ध बाजारू व सामरिक उपयोग

प्रथम पृष्ठ का शेष

नौटंकीबाज रक्त पिपासु दानव मोदी ने इस कृत्य को भी खूब भुनाया, तत्काल ही लाखों करोड़ के हथियार खरीद के सौदे रूस, अमेरिका, फ्रांस व अन्य से कर डाले, बेशक यहां कमीशन खोरी अपने आका, अंबानी बंधुओं के माध्यम से हुई और जनता का रक्त चूसने उसने बदले में पेट्रोल कीमतें बढ़ा दी। अभी 51 अमेरिकी डॉलर की कीमत पर तिगुना महंगा बेचा जा रहा है। बदले में श्याना कौवा रूस के पुराने हथियार, पनडुब्बियों, लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, मिसाइलें खरीद रहा है। इस वर्ष भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, जबकि वही रूस और अमेरिका पीछे से पाकिस्तान को तन, मन, धन के साथ हथियारों से भी पूरा सहयोग कर रहे है, ताकि लड़ाई की तैयारी दिखाकर अपने हथियार बेच मोटी कमाई कर अपने देश की अर्थव्यवस्था चला सके।

मंत्रियों, नेताओं और उद्योगपतियों पर आयकर क्यों नहीं मारता छापे

प्रथम पृष्ठ का शेष

राज्य सरकारों में विक्रय कर या वाणिज्यिकर, आबकारी राजस्व में पटवारी से लेकर तहसीलदार, सहा. जिला, उपजिला व जिलाधीकारी अर्थात एडीएम, एसडीएम और डीएम, जनपद जिला पंचायत अधिकारी जिला कृषि, महिला बाल विकास, खनिज आबकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, एसपी, डीएसपी से लेकर ए.एस.पी., टीआई, उपनिरीक्षक, जिला उद्यानिकी, सहा. यंत्री उपयंत्री, कार्यपालन यंत्री अधीक्षक, मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.लो. स्वा. जिलाशिक्षाधिकारी, जिला कोषालय अधि., जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी जिला पंजीयक, मुद्रांक, सहकारिता, जिला परिवहन जिला व केन्द्रीय कारागार, श्रम, निरीक्षकों खाद्य एवं औषधि निरीक्षक, खाद्य एवं नागरिक पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व, श्रम, निरीक्षकों खाद्य व औषधि निरीक्षक, औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा आबकारी, विक्रय कर, राजस्व, उद्योग, खनिज आदि जहां पर निरीक्षक नाम का पद है। निरीक्षण की आड़ में रुपए 5-10 हजार से लेकर जैसा काम वैसा दाम के आधार पर मोटी वसूली की जाती है।

निरीक्षकों की कमाई रुपए 10-20-50 हजार रुपए प्रतिदिन से लेकर रुपए 20-25 लाख प्रतिदिन तक हो सकती है। यही कारण है कि युवा पीढ़ी से लेकर मध्यमवर्गीय तक निरीक्षक बनना पसंद करते है और इसकी तिकड़म में रुपए 25-50 लाख तक खर्च करने को तैयार रहते है। ताकि दोनों हाथों से लूट-पाट कर सके। जब सरकार का नियम है कि रुपए 5000/- से ज्यादा नगद हाथ में नहीं रखना है तो फिर सारे मंत्रियों, नेताओं, आई.ए.एस., आईपीएस, आईएफएस से लेकर संभागायुक्तों, जिलाधीशों, शासकीय चिकित्सकों, इंजिनियरों से लेकर सरकारी पटवारी, तहसीलदार, निरीक्षकों, उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अधिकारियों, निरीक्षकों के घरों पर क्यों अचानक छापे नहीं मारे जाते, जिनके पास आसानी से लाखों-करोड़ों की नगदी पकड़ी जा सकती है। जो अपने रिश्तेदारों, नौकर-चाकरों से लेकर अपने मिलने वालों परिचितों के नाम के साथ ही अपने पाले हुए कुत्ते-बिल्लियों के नाम तक से बैंकों में लाखों-करोंड़ों का लेन-देन करते है। संपत्तियां खरीदते हैं। न केवल प्रदेश में वरन् देश व विदेशों तक में संपत्तियां तरल और ठोस में निवेशित करते है। हालात ये है कि इन्हें अपने कालेधन को सुरक्षित निवेश करने का स्थान तक उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अमेरिका में 2007-08 में करीब 32 से ज्यादा बैंक डुबोने और दिवालिया करने के पीछे का राज भी यही था, ताकि वहां जमा लाखों भारतीयों के जो लाखों-करोड़ डॉलर जमा थे, जो पूर्णतः कालाधान ही था जिसमें अधिकांश उच्च स्तरीय मंत्रियों, अधिकारियों, नेताओं, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का ही अवैध आय का ही धन था, जिसके डूबने के बाद किसी की आवाज तक नहीं निकली। जिससे आसानी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारा गया।

भारत में काले धन का राग अलापने वाले और काले धन के नाम से वोट कबाड़ने वाले मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा ने बताया कि पूरा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लड़ने वालों ने बताया कि उनके पास चुनाव लड़ने रुपए लाखों करोड़ का खर्च कहां से आया, फेसबुक के मालिक जुबरबर्ग जो पूरी दुनिया में लव जिहाद फैलाने आतंकवादी संगठनों, आईएसआईएस, इंडियन मुजाहिद्दीन, सिमी जैसे संगठनों को न केवल भारत में वरन पूरी दुनिया में प्रोत्साहित करने वृहत जनसंहार की चित्रावली प्रसारित करने वाले को लाखों करोड़ का भुगतान करने वाले मोदी और अमित शाह व भाजपा के पास कालाधन किस स्त्रोत से प्राप्त हुआ, किस हवाला गिरोह से इसका भुगतान किया, तब आयकर ने इन स्त्रोतों पर छापा क्यों नहीं मारा जब वह फेसबुक और ट्वीटर जैसी सामाजिक कही जाने वाली साइटों पर मोदी अपनी नायक से महानायक छवि गढ़ने के लिए इनका उपयोग कर दूसरी तरफ आतंकवाद को देश में बढ़ावा दे रहे थे। हाल ही की जीएसटी को राज्यसभा और लोकसभा में पास करवाने के लिए अमित शाह और मोदी ने हर सांसद को न्युनतम रुपए 10से 20 करोड़ बांटकर समर्थन प्राप्त कर बहुराष्ट्रीय कं. के हित में जीएसटी पास करवाया। यह धन किन देशी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मित्तल जैसों के साथ विदेशी कं. आईटीसी, युनीलीवर, वालमार्ट, कैलाग, मेकडावल जैसी बहुराष्ट्रीय कं. के ये लाखों करोड़ के चंदे से उनके हित में, देशी 5 करोड व्यावसायिक छोटे एवं लघु उद्योगों को नष्ट करने के लिए किया गया, आखिर ये कालाधन नहीं था। क्यों नहीं इसकी जांच की गई, इसका परिणाम अब न केवल राज्यों की सरकारें वरन भारत सरकार भी भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को घाटे में करने के लिए ये बहुराष्ट्रीय कं. ही जिम्मेदार होती है जो जनता से लूटकर इन मंत्रियों उच्चाधिकारियों को देकर जनता को नोंचने के लिए कानून तक बनवा लेती है। जैसा की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06, जीएसटी में तत्काल में भारत में किया गया। आखिर मोदी उसकी भाजपा के साथ पूरा विपक्ष उसकी आवाज क्यों नहीं उठाता। क्या कर लेता है आयकर। फिर काले धन पर हल्ला मचाने वाले राजग और संप्रग के राजनैतिक दलों के किस नेता को मंत्री को धन नहीं चाहिए, इसके लिए तो दोनों ही नेताओं ने राष्ट्रद्रोही दाउद की जेट एयरलाइंस, लोटस के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर्स, एक्सिस बैंक जैसे समूहों को इंडियन एयरलाइंस सुरक्षा तक को गिरवी करने से नहीं चूके, आखिर उस कालेधन को तो लूट डकैती से आया था, को आसानी से लगवाकर न केवल देश के हर हवाई अड्डे से लेकर पूरे देश के चप्पे-चप्पे के हवाई नक्शे तक उसके माध्यम से पाकिस्तान और चीन के हवाले कर दिये गए, जबकि जेट के बारे में न केवल देशी गुप्तचर एजेंसियों वरन् अमेरिका ने भी उसे वर्षों तक आतंकवादियों के धन से चलने वाली एयरलाइंस बताकर उसे देश में घुसने की आज्ञा नहीं दी थी।

सत्ता के मद में भूल गए हिन्दुत्व, स्वदेशी, बुला रहे गुलामी

प्रथम पृष्ठ का शेष

इस देश भक्ति के ढोंग से जनता भ्रमित हो गई और उसने इन के इस भारतीय जनता पार्टी को इस रा.स्व. सं. की आड़ में हिन्दुओं क हित साधन के नाम पर सत्ता पाते ही सबसे पहले हिन्दुओं को ही बर्बाद करती है। जिन अगड़े हिन्दुओं के दम पिछले 35 वर्षों से चंदा मांग अपने पैर जमाये और साम, दाम, दंड, भेद की नीति और जालसाजी पूर्ण तरीके से सत्ता हथियाई, सत्ता को संभालते ही केवल मुस्लिम और आरक्षित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जो कि पूर्ण रूप से कांग्रेस का अन्यायन पुजारी है। जन-धन से बेइंतहा लूटे या थोपे गये पेट्रोल, डीजल को दुगुनी कीमत पर बेचकर भी उस पर 32 प्रश एक्साइज, 8 प्रश सेस, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के साथ 0.5 प्रश स्वच्छता के नाम भी लूटा जा रहा है। वह पैसा इस मानवों की विशेष जाति पर खर्च किया जा रहा है, आखिर 10-10 वर्ष करते-करते 65 वर्ष गुजर गये, पर आरक्षण का भूत नहीं मिटा पाये।

दूसरी ओर जब कांग्रेस सत्ता में होती है, तो स्वदेशी चिलाते हैं। अब जब स्वयं की पार्टी सत्ता में है तो सब स्वदेशी भूल जल, जमीन, जंगल, जन, जानवर सब विदेशियों को गिरवी किये जा रहे है। कहां गया राष्ट्रवाद, कहां गया साम्यवाद सब अपने पूंजीपति बाप अडानी, अंबानी, टाटा को गिरवी बेचा या कब्जा करवाया जा रहा है। देश के 40 करोड़ लोगों को भूखा मारने की पूरी तैयारी चल रही है। कहां गया राष्ट्र प्रेम, हालात इस संघ के अंदरूनी दयनीय है। 5,7,10 वर्ष के बच्चों से लेकर 70-80 वर्ष के बूढ़ों तक को राष्ट्रभक्ति, हिन्दू राष्ट्र आदि के नाम पर मानसिक रूप से उन्हें बांध कर घोर शोषण कर शीर्ष पर बैठे जिसमें मोदी, भागवत आदि अपनी शक्ति और संघ का दुरुपयोग कर रहे है। मोदी ने जिस प्रकार प्रसार माध्यमों पर फेसबुक, ट्वीटर, टीवी चैनलों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर बहाकर और संघ के कार्यकर्ताओं का भरपूर उपयोग सत्ता पर कब्जा जमाया, सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद से ही संघ ने हिन्दुत्व को त्याग मुस्लिमों से गलबहियां कर टोपी पहनना और पहनाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के नितिन गडकरी जो न केवल घोर भ्रष्ट जालसाज है, रा.स्व.संघ ने उसे न केवल बल, छल के दम पर सत्ता भी सौंपी, भूतल परिवहन मंत्रालय की, जबकि कांग्रेस के कार्य पर सत्ता में आने के बाद चूंकि नितिन गडकरी के भी कई टोल टैक्स है, महाराष्ट्र में सारा विरोध हवा हो गया, अर्थात अब संघ के लिए राष्ट्रीय संपत्तियों को पूंजीपतियों को सौंपने जिसमें सड़कें, बिजली पानी आदि थे, पूंजीपतियों को सौंप मोटी कमाई से कोई गुरूेज नहीं।

संघ ने जो ठोस हिन्दुत्व की छवि बनाई थी उसी के दम पर वह सत्ता में आई, उसको हिन्दुत्व के लिए हिन्दुओं की घटती जनसंख्या के लिए, हिंदुओं की संस्कृति, परम्पराओं की स्थापना के लिए धर्म परिवर्तन से हिन्दुओं से ईसाई और मुसलमानों की घर वापसी के लिए, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को धार्मिक परम्पराओं को सिखाने, पहाने, मंत्रों, शास्त्रों, वेदों उपनिषदों की महत्ता, दैनिक जीवन में उपयोग, आयुर्वेद की परम्पराओं को ज्ञान और चिकित्सा पद्धति को पुनः जागृत करने, विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए सत्ता का सदुपयोग कर पूरे विश्व में जड़े जमानी चाहिए थी, वो सत्ता के मद में मदहोश हो स्थायित्व के लिए पूंजीपतियों के शरणागत हो, स्वयं धन बटोरने में लग गया, गोविंदाचार्य जैसे शीर्ष विचारक को हांसिये पर डाल दिया, जबकि संघ को अपने हर कार्यकर्ता के लिए जिसमें बच्चों का शिक्षा जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक युवाओं को प्रोत्साहित कर स्थाई रोजगार, नौकरियां, व्यवसाय के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थायें करनी चाहीए थी।

जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया जबकि संघ को चाहिए था कि शिक्षितों को सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए प्रशासनिक, पुलिस, वन, विदेश सेवाओं, राजस्व सेवाओं से लेकर बाबुओं तक की भर्ती करवाना, आखिर वह संपत्ति न केवल चिरस्थाई होती, बल्कि युगों तक रा.स्व. संघ का झंडा लहराता, पर संघ के दकियानूसी सोच के लोगों ने उसको राजनैतिक उपयोग के लिए सत्ता की रखैल बनाकर उसकी आधारभूत सोच, बोल वचन और कर्तव्यों पर ताले मार दिये, संघ को अभी भी वक्त है कि वो अपने मूल उद्देश्यों की गुरूकुल पद्धति जिसमें अंग्रेजों ने राष्ट्र को विरकाल तक गुलाम बनाये रखने के लिए नष्ट किया था,पुनः जागृत कर हिंदुओं को शीघ्र विवाह, असीमित बच्चे पैदा करने और उनके लालन-पालन और शिक्षा का भार उठाने की प्रेरणा दे, साथ ही स्त्रियों को संघ की शाखायें बढ़ाकर हिन्दुत्व के मूल सिद्धांतों की ओर मोड़े, उनमें वेदों, उपनिषदों की शिक्षा, वाद विवाद करवाये ताकि विदेशी टीवी संस्कृति और बहुराष्ट्रीय कं. की बर्बादी और उच्च श्रृंखला से बचाया जा सके, जब सत्ता आपके लोगों की है, तब तो इस कार्य को सत्ता के सहयोग से आसानी से संपन्न किया जा सकता है। संघ की गोपनीयता और शांति से कार्य करने की प्रणाली सबको अच्छी लगती है पर संघ में समुचित विकास, समुचित सबकी समृद्धि के घोर अभाव के साथ ही सत्ता संभालते ही राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी, हिन्दुत्व धर्म, परंपरा, संस्कृति की मूल अवधारणा का लोप हो जाना इस संघ के शीर्ष पर बैठे पदाधिकारियों की घोर लालची दंभी और अब सरकारी प्रवृत्ति का सहज दर्शन करवा देता है। फिर आम हिन्दु जो भले ही न जुड़ा हो उसके हृदय की श्रद्धा को बिखेर देता है यदि नाथुराम गोडसे नहीं मारते तो गांधी इस देश को कैसे बर्बाद करता कि स्पष्ट स्वीकार करने में क्या तकलीफ है।

क्यों नहीं बताते इतिहास की हकीकत कि गांधी नेहरू की अय्याशी की हकीकत उनकी चित्रावली जिसमें गैर स्त्रियों के साथ कैसे गलबहियां करते थे, लगा दीजिए प्रदर्शनी, प्रसार माध्यमों में चलवा दीजिये महीने दो महीने हल्ला मचेगा, फिर ठंडा होने के साथ ही नाथुराम गोडसे जी का सच सामने होने पर लोग हत्यारे की अपेक्षा नायक की भांति याद करेंगे। आखिर संघ की दुलमुल नीति किसे बर्बाद कर रही है। स्वयं संघ को,जागो आने वाली पीढ़ी को ठोस सिद्धांतवादी हिन्दु संगठन का सहारा दो, समाज के हित की बात करो चाहे सत्ता किसी की भी हो, वाक्त है अभी युवाओं को जो 20-30 लाख तक केन्द्र व राज्य की नौकरियां करवा दो स्थाई, आप अपने आप स्थाई हो जाओगे।

न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं, जुऐ के अड्डे

न्याय मिलता नहीं, कबाड़ा जाता है

सत्ताधीशों और पूंजीपतियों की कठपुतली बन चुके हैं, उच्च सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों को भी सत्ता पुलिस और प्रशासन के इशारों पर ही नाचना होता है, आखिर वेतन तो वो ही देते है

भारत में न्याय प्राप्त करना था न्याय की बात करना पूर्णतः बेमानी होता जा रहा है। इस संबंध में भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की एक पंक्ति- जो उन्होंने 25 जून 2001 के अपने जनता के नाम दिये गये संदेश में कही थी- 'न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जुये के अड्डे हैं। जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा'' भारत की न्यायालयीन व्यवस्था में इसी सत्यता को हर कदम-कदम स्थिति स्पष्ट है, जिसे स्वयं न केवल राष्ट्र के प्रथम नागरिक ने भी 15 वर्षों पूर्व न केवल स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया, वरन दों पंक्तियों में ही भ्रष्टाचार के तांडव की स्थिति स्पष्ट कर दी थी, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी खुले मन से न केवल स्वीकार किया वरन् केन्द्र व राज्य शासन के पर्याप्त संख्या में अयवश्यकतानुसार जिला एवं सत्र न्यायालयों में, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोत्तरी न करने को भी जिम्मेदार ठहराया, भारतीय न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वरन् पूरे देश में फैले चारों तरफ हर कदम शासकीय और अशासकीय व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सभी प्रकार की संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार लूट व शोषण के लिए सर्वप्रथम जिम्मेदार है, जबकि भारतीय न्यायालयों का इससे भी खतरनाक एक पहलू यह भी है कि ये न्याय के मंदिर कहे जाने वाले ये न्यायालय अपराधियों, भ्रष्टों, जालसाजों के प्रमुख संरक्षणदाता भी ही है।

हर राजनैतिक पार्टी के बड़े नेता, मंत्री से लेकर इस देश की प्रशासनिक रीढ़ समझे जाने वाले महाभ्रष्ट, जालसाज, जनधन पर सबसे ज्यादा डकैती डालने वाले, काले धन और बेनामी संपत्ति के सबसे बड़े मालिक, नेताओं, मंत्रियों,प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को हांकने और चलाने वाले इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी 90 प्रश आर्थिक और वित्तीय अनियमिताओं को हजारों करोड़ की धन राशि हड़पने, बर्बाद करने वालों पर सैकड़ों जांच प्रकरण लंबित होने के बाद भी आराम 30 से 40 वर्ष की नौकरीयां पूरी कर आराम से निकल लेते हैं और न्यायालयों में मुकदमे चला करते हैं।

भारतीय न्यायालयीन व्यवस्था के पहलूओं में सबसे बड़ा दुखद पहलू यह भी है कि न्याय अत्याधिक धीमा लंबा होने के साथ ही पूरी न्यायिक व्यवस्था पूंजीपतियों और सत्ताधीशों की गुलाम बन चुकी है, जिसके उदाहरण उच्च और सर्वाच्च न्यायालय में होने वाले निर्णयों से स्पष्ट हो जाते है। सलमान के प्रकरण में मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण में दिये गए निर्णयों को पूरे देश के सत्र एवं जिला न्यायालयों से लेकर आमजन में भी रुपए 200 करोड़ और सर्वोच्च न्यायालय में रुपए 500 करोड़ के दान दिये जाने की चर्चा चल रही थी, वही हाल काले हिरण द्वारा सलमान को देखकर उसकी बंदूक से स्वयं कनपटी गोली मारने वाले प्रकरण में भी उच्च न्यायालय जोधपुर ने दान प्राप्त कर किया और साफ वही कर कर दिया, जबकि उसके गाड़ी चालक जो जश्मदीद गवाह था ने स्पष्ट कहा कि गोली सलमान ने हिरण को मारी थी। इसके बाद भी साफ बरी कर देना स्पष्ट करता है कि स्वयं भ्रष्ट न्यायायिक व्यवस्था अपराधियों को मोटे धन के बदले पालती है।

भारत में खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06 जिसे वालमार्ट जैसी कं. ने 550 करोड़ अमेरिकी डॉलर देकर भारत में बनवाया जिससे एक-एक सांसद को रुपए 500 करोड़ तक मिले थे, चुपचाप सबसे अंगूठे लगा दिये जब वह सन् 2011 तक लागू नहीं किया जा सके तो उसके विरूद्ध याचिका में भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मोटा धन हजम कर उसे लागू करवाने का संसद पर दबाव बनवाया था, ताकि बहुराष्ट्रीय कं. को लाभ पहुंचाकर देश की जनता को लूटने का मार्ग प्रशस्त हो सके, 5 अगस्त 2011 से लागू इस काननू का ही ही प्रभाव था कि बहुराष्ट्रीय और देशी कं. ने लाखों टन दाल को भंडारण कर दाल की कीमतें जो रुपए 60 की बिकती थी। 4 गुना महंगी कीमतों में रुपए 250/- प्रति किलो तक बेचकर लोगों के मुंह से दाल-रोटी भी छीन ली, दूसरी तरफ नकली घी, दूध से लेकर मसालों, खाद्य तेलों आदि में जालसाजी पूर्ण कानूनों की आड़ में 25 से 75 प्रश मिलावट की वैधानिकता के आधार पर खुली छूट देकर 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की छूट दे दी गई, कानून की बात भी की पूर्ण बहुराष्ट्रीय कं. को फायदा पहुंचाकर छोटे, लघु व मध्यम श्रेणी के विक्रेताओं, उत्पादकों आदि ने या तो धंधे बंद कर दिये या खाद्य एवं औषधि विभाग के खाद्य. सुरक्षा के डकैत जालसाजों हर कदम लूट की दोनों हाथों पूरी छूट देकर भ्रष्टाचार का तांडव करवा दिया, अभी हाल में बहुराष्ट्रीय दवा कं. और विश्व स्वास्थ्य (बिगाड़ो) संगठन के इशारे पर उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अब औषधियां मूल तत्वों के संयुक्त यौगिकों के रूप में नहीं बिकेगी, अर्थात गरीब को अब बीमारी की दवाओं के हर तल की अलग-अलग दवायें खरीदने के लिए चौगुनी से आठ गुनी कीमत देनी होगी, ताकि बहुराष्ट्रीय कं. के उजड़ते और बिगड़ते व्यापार को रोककर उन्हें 1000-2000 प्रश का लाभ मिल सके, और भारतीय औषधि उत्पादक कं. को अपनी फैक्ट्रीयां बंद करना पड़े और लाखों लोग बेरोजगार हो जाये, इसके साथ ही उनका रु. 50000 से 70000 करोड़ की औषधियों का भंडारण अवैधानिक हो जाये, और विदेशी उत्पादकों का माल इस देश की 130 करोड़ आबादी के लिए विदेशों से खरीदना पड़े, अब प्रश्न यहां यह उठता है कि न्यायाधीश विधि विशेषज्ञ है या भेषज विशेषज्ञ, फिर भारतीय डॉक्टरों को जो सरकारी या निजी क्षे में चिकित्सा सेवायें दे रहे हैं, दूसरी और क्या औषधियों और सौंदर्य प्रसाधन कानून में इसका उल्लेख किया गया है कि औषधियों की संयुक्त यौगिकों की अवस्था में बैचना या बीमारों की चिकित्सा में देना अपराध है। फिर जो डॉक्टर पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से अधिकांश औषधि यौगिकों के नाम से बिकने वाली दवायें लिख और चिकित्सा कर रहे हैं। यदि उन्होंने उसी आधार पर कार्य किया तो कई बीमारों की मौत भी हो सकती है, रोग बिगड़ या बढ़ भी सकता है, तब ऐसा आदेश देने वाला उच्च, न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनायेगा हर दिन ऐसे सैकड़ों फैसले उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों में पूंजीपतियों और सत्ताधीशों के इशारे पर दिये जाते है। न्यायालयों में घोर भ्रष्टाचार है, ये स्वयं न्यायाधीश सार्वजनिक मंचों से स्वीकार कर चुके हैं।

यहां पर भ्रष्टाचार और वसूली का तांडव से सभी परिचित है। यहां पर वास्तविकता में न्याय मिलता नहीं जुगाड़ना पड़ता है, फिर आए दिन पुलिस के भ्रष्टाचार जिसमें अपराधियों को फरियादी और फरियादियों को अपराधी बनाकर निरीहों को सजायें दिलवा दी जाती है। और अपराधियों पर 50-50 प्रकरण दर्ज होने पर एक में भी सजा नहीं मिल पाती या दिलवाई जाती फिर पुलिस के सिपाही से लेकर प्रधान आरक्षक, उप सहायक से नगर निरीक्षक, अधीक्षक से लेकर महानिरीक्षक तक सब यथार्थ में भ्रष्ट होने से ज्यादा बड़े कहानीकार और फर्जी वृतांत लेखक भी है। जिनकी कहानियों के आधार पर सारे जिला न्यायालयों और उनके सरकारी वकीलों को नाचना पड़ता है जिससे सैकड़ों बेगुनाह कारागृहों में मृत्यु की कामना के साथ जीवन का हर पल पूरा करते है तो 90

प्रतिशत अपराधियों के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। इसके विपरीत चूंकि पत्रकार अजमेरा पुलिस के यथार्थ का समाचार प्रकाशित करते है। इसलिए उनके विरूद्ध एक झूठा मुकदमा जिसमें उन्होंने 16 पुलिसवालों को मारा था 2 नवम्बर 2002 को, 14 वर्ष चलाया गया, क्योंकि 2 नवम्बर 2002 गीता भवन चौराहे पर पुलिस धनतेरस के दिन वसूली कर रही थी। 1.45 बजे गीता भवन चौराहे से हरी बत्ती पर जब चौराहा पार कर रहे थे, नगर सैनिक अशोक यादव स्कूटर पर कूदकर पकड़ने के लिए दौड़ा, गाड़ी रोकने के बाद किनारे लगवाकर वसूली के लिए पैसे मांगे, जो उनके पास नहीं थे, गाड़ी की चाबी उनके पास थी, नाम पता पूछने पर पता चला कि ये वही अजमेरा है जो पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध वर्षों से कलम चला रहा है। अधिकारियों ने घेर लिया और पलासिया थाने ले आये, पुलिस सिपाहियों से अजमेरा के विरूद्ध एफआईआर लिखवाने को सबने मना कर दिया, तो अशोक यादव व जिसकी ड्यूटी 12 बजे समाप्त हो गई थी, दिन के 2-3 बजे 11.30 बजे को घटना दर्ज करवाकर गाड़ी जप्त कर ली गई, अजमेरा के वकील मित्रों ने जमानत लेकर छुड़वा लिया। जिसका बार-बार कहने पर भी चालान मई 03 के दिन में 4.30 बजे पेश किया ताकि आसानी से अंदर किया जा सके, परंतु न्यायाधीश ने यह देखते ही बुरी तरह से मुंशी को डांटा व रुपए 5 हजार की नगद रसीद काटने को कहा, व साढ़े पांच बजे जमानत दे दी, इस बीच जितने भी गवाह बुलाये गये सबने साफ कहा कि हमारे सामने कोई घटना नहीं घटी, न हम किसी को जानते हैं।

पुलिस ने बिना पूछताछ किये हमारे नाम गवाहों में लिख दिये, बाकी बयान सब स्वयं पुलिस वालों के ही थे, गाड़ी पकड़ने के बाद जब कुछ अधिकारियों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि अजमेरा को मालूम पड़ना चाहिए कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है, उसके बाद गाड़ी पकड़ने का झूठा केस बनाने 6 महीने भर बाद भी चालान पेश नहीं किये।

पिछले 10 वर्षों में 380 उद्योग बंद 14 खुले- निवेश आयोजन में अरबों फूंके

पृष्ठ 12 का शेष

सन् 2014 में इन भ्रष्टों ने किराया दिया रुपए 40 लाख प्रतिदिन, जबकि रुपए 25 लाख प्रतिदिन के किराये में सन् 2016 में वन विभाग ने बांस वृद्धि हेतु विदेशियों को बुलाकर आयोजन किया। फिर जैसा कि लो.नि.वि. के भारतीय सड़क कांग्रेस में रुपए 650 प्रति प्लेट भोजन और रुपए 250 की प्रति व्यक्ति चाय में रुपए एक करोड़ से ज्यादा डकारा जबकि हर भोजन व्यवस्था का भुगतान बड़ी कं. ने करवाया था, वही हाल यात्री वाहन व्यवस्था में 400 करोड़ टैक्सियों का भुगतान हुआ जबकि मात्र 180 कारें और 50 बसों के स्थान पर 20 बसों का ही उपयोग किया गया। वही हाल कार्यक्रमों के आयोजनों और सजावट में भी रुपए तीन करोड़ के भुगतान में से रुपए 1.50 करोड़ डकारा गया। होटल बुकिंग में भी लगभग रुपए 75 लाख का ज्यादा भुगतान किया गया।

110 होटलों की बुकिंग में से 87 होटलों में आगुंतकों को ठहराया गया, इसमें भी करीब रुपए 8 करोड़ शासन से मिला रुपए दो करोड़ इस सड़क कांग्रेस के सदस्यों से इकट्ठा किया और करीब रुपए 5 से 8 करोड़ पूरे मप्र के छोटे बड़े ठेकेदारों से अधिवेशन और स्मारिका में रुपए 20,0000 से लेकर 5 लाख तक के विज्ञापन छापे गये, रुपए 800 से 1500 की साड़ियों कीमत रुपए 1500 स 5000 दिखाई गई, 400 साड़ियों में से लगभग 110 साड़ियां उनका सचिव व सेवानिवृत्तियां बीएल जैसवाल हजम कर गया, इसमें रुपए 5 से 7 करोड़ हजम किए गए। जिसमें प्र.स. प्रमोद अग्रवाल, प्र.अ. अखिलेश अग्रवाल, मु.अ. पीके श्रीवास्त, अ.यं. जैसवाल, इस आयोजन केरोड़िया एनके श्रीवास्तव और इसके खातों को देखने वाले महाधूर्त भ्रष्ट सं.ले. त्रिवेदी व अन्य ने मिलकर हजम किया यही कारण है कि अप्रेल के सू.अ. के आवेदन, मई की अपील जिसकी सुनवाई 2 जुलाई को हुई अभी तक जानकारी नहीं दी गई, ये एकेवीएन में भी यही कहानी दुहराई जाती है। फिर यहां बजट लगभग रुपए 50 करोड़ से ज्यादा होता है। यहां पर भी भोजन, होटल बुकिंग, विज्ञापन, सजावट, टैक्सियां, बुकिंग़, छपाई के नाम पर ही रुपए 15 से 20 करोड़ उस समय का प्र.सं. मनीष सिंग, उद्योग विभाग प्र.स. सुलेमान, मंत्री वसुंधरा राजे से लेकर यहां बैठे महाप्रबंधक मुजाल्दा अरोरा, गेठेवाला से लेकर बाबु चपरासी तक ने हिस्सेदारी की, मु.मं. को अपना हिस्सा तो वित्त विभाग से स्वीकृति के साथ 5 से 10 प्रश तक फर्जी के बिल लगाकर पहुंचा ही दिया जाता है।

फिर यहां एकेवीएन तो बड़े उद्योगपतियों को जीने नहीं देती, अगर इन औद्योगिक केन्द्रों में बैठे यंत्रियों, प्रबंधकों महाप्रबंधकों को धन नहीं मिलता नियमित रूप से तो ये उद्योगपतियों को कदम-कदम परेशान करते हुए भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। अकेले इंदौर के एकेवीएन, धार, पीथमपुर, सांवेर रोड, खरगोन के निमरानी, लेबड़ आदि क्षेत्रों में पिछले 15 वर्षों में सैकड़ों उद्योग बंद हुए, जबकि देवास, मक्सी, मंत्रियों, मालनपुर व पूरे मप्र में मप्र में पिछले 20 वर्षों में 1200 से ज्यादा उद्योगों में ताले डाले गए जिन पर अरबों रुपए वाणिज्यकर, आयकर, बिजली, पानी, एक्साइज और कस्टम का करोड़ों रुपए डूब गया।

मिट्ठू मियां मु.मं. शिव चौहान ने केवल झूठे आंकड़ों की बाजीगरी से पूरे मप्र को पिछले 12 वर्षों से होलकर कभी यह क्यों नहीं बताया कि कितने उद्योग पूरे मप्र के औद्योगिक क्षेत्रों में बंद हो गए केवल सरकारी नीतियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण, कितने करोड़ रुपए हर वर्ष यहां बैठे गिद्धों जो प्रदेश के और के.वि. निगमों में बैठे हैं। बिजली, पानी, सड़को व अन्य सुविधाओं के नाम पर हजम कर लेती है, क्योंकि जनता से लूटे गए करों में से खर्चों में लुटाये गये धन में उसका भी हिस्सा है। यही कारण है कि इन डकैतों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर ये जालसाजों की फौज कभी पूरा और सही जवाब नहीं देती, समय पर आधे-अधूरे मांगी गई जानकारी फोटोकॉपी शुल्क मांग भी लिया गया, तो भी जानकारी देने के नाम पर हरामखोर चक्कर करवाते हैं। जब आधी-अधूरी जानकारी के विरूद्ध अपील भी की तो जालसाज दो माह तक सुनवाई नहीं करते, बाद में रद्द कर दी जाती है।

सुनवाई में अगर दबाववश निःशुल्क देने का लिख भी दिया तो सू.अ. अरोरा कभी भी पूरी जानकारी नहीं देता, वैसे सुनवाई प्र.स. को करना चाहिए, पर वो डकैतों का महाडकैत मप्र मुजाला के हवाल कर देता है। मनीष सिंग भी तो मोती सिंग की औलाद है, लगभग रुपए 10 करोड़ हजम किया था जिसमें रु. 50 लाख के फटाके ही फोड़ दिये थे। धनतेरस से लेकर दीवाली के दो दिन बाद शाम 7-8 बजे से रात्रि 2 बजे तक हर दिन रुपए 10 लाख के फटाके फोड़े जाते रहे जिससे पूरी रेडियो कॉलोनी गूंजी। ये वही मोती सिंग था जिसने भोपाल का एसडीएम रहते हुए 1984 में एंडरसन को करोड़ों रुपए लेकर अभिरक्षा से जुड़ाकर 8 दिस. 84 को एयरपोर्ट छोड़ा था, अपनी जीप से, अब निगमायुक्त बन जब करोड़ो हजम कर रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर।

साप्ताहिक समय माया

जुलानिया के जाने से भ्रष्ट मुस्करा उठे, जल संसाधन के यंत्री और अभियंता

मप्र जल संसा. में भ्रष्टाचार और जालसाजियों का तांडव

सूचना के अधिकार की अपील में आवेदन का पन्ना ही गायब, उज्जैन की खान डायवर्सन पूर्णतः असफल, का.य. महेन्द्र जैन के भ्रष्टाचार पर स्थानांतरण पर भी स्थगन, अ.य. बागोरा 20 वर्ष से खरगोन में फिर भी स्थानांतरण नहीं

मप्र जल संसाधन विभाग से 6 वर्ष बाद प्र.स. जुलानिया की बिदाई हो गई, पूरे जल संसाधन विभाग में ही खुशी की लहर छा गई हो, परंतु पूरे देश में इस जैसे भ्रष्ट निहायत ढीले, मक्कार और जालसाज विभाग की छवि बदलने, सिंचाई का रकबा बढ़ाने में जो योगदान जुलानिया के प्रशासन ने दिया, पूरे देश के आजाद भारत का इतिहास बन गया, देवास के दतनी बांध का जो काम उसके समय में निश्चित समय सीमा में हुआ और 20-25प्रश नहरों में पानी छोड़ा गया, वह शायद दूसरे प्र.स. के रहते कभी संभव नहीं होता।उज्जैन में भी अति अल्प समय में 18 किमी के खान नदी के गंदे पानी को क्षिप्रा के समानांतर पाइप लाइन बिछाने का सिंहस्थ के पूर्व वहां के का.य. मुकुल जैन, जो ऐतिहासिक भ्रष्ट हैं, जिसने रुपए 3 करोड़ का 1980 का चोरल बांध बनाते-बनाते, 2002 तक उसकी लागत 103 करोड़ कर दी थी से रुपए 80 करोड़ का कार्य करवा लिया। वह बात दूसरी है कि वह पाइप लाइन बार-बार फूटती रही और सिंहस्थ की समाप्ति और बरसात में वह पूर्णतः औचित्यहीन हो क्षिप्रा का पानी गंदा करती रही, स्वाभाविक था हरामखोर ने परियोजना में रुपए 10 करोड़ से ज्यादा पर मिल बांटकर हाथ साफ किया तो सूचना के अधिकार में आवेदन का जवाब भी कैसे दे, अपील करने पर अ.यं.ह.न. गुप्ता ने जो कि पुराने भ्रष्ट है। जिसने धार, देवास में मोटा माल हजम किया, अपील में कई बार चक्कर लगवाने के बाद सुनवाई की और लिख दिया कि आपका जवाब नोटिस बोर्ड पर टांगा था, आपने पैसे जमा नहीं किये, जैसे जवाब को डाक द्वारा भेजने पर इन जालसाजों के बाप की जेब का पैसा लग रहा था, अब चूंकि ये अ.य.ह.न. गुप्ता जो धार के बाद देवास के का.यं. रहते हुए दतुनी बांध के कार्य को संपन्न करवा चुके हैं। जहां भराई में पीली के स्थान पर काली मिट्टी डाल, बिना स्तरीय दोनों तरफ के दबाव और स्तरीय कांक्रीट निर्माण जिसमें 55 ग्रेड की सीमेंट के स्थान पर 44 की सीमेंट डलवाकर इस रुपए 175 करोड़ के बांध में भूमि अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक में 8 से 10 प्रश तो कार्यालयीन दर है, हजम करने के कारण, जानकारी देने में देवास स. के मक्कारों ने जवाब देने की अपेक्षा हर बार जानकारी नोटिस बोर्ड पर टांगी, जो हर सप्ताह देवास सं. के इस विभाग में पिछले तीन वर्ष से चक्कर लगाने के बाद कभी नहीं दिखी, यहां बैठे हर का.यं. उसके मक्कार भुखेरे की फौज को डर था कि जानकारी देने पर मुश्किलें बढ़ सकती है। फिर इंदौर मंडल में उस समय का अ.य. गांधी जो अपनी जाति छुपाकर गांधी लिखता था और वर्तमान का अ.य. अरविन्द खरे और वहां बैठा मक्कार और कामचोर स्टाफ पिछले 3-4 वर्ष में लगाई गई अपीलों का निराकरण अपने स्तर पर पैसे लेकर, बिना अपील में बुलाये इंदौर, देवास, शाजापुर की स्वयं ही नस्तीबद्ध कर देता था, जब शाजापुर संभाग से मात्र कुछ रजिस्टरों की फोटो कॉपी मांगी गई थी, उसके अधिकतम रुपए 100, 200 का शुल्क लगना था वहां बैठा महाभ्रष्ट रुपए 7-8 हजार शुल्क मांगने पर जब अपील की गई तो दो महीने बाद पैसा न जमा करने और अपील निरस्त करने का पत्र भेजा गया तो पूछा कि आप बिना बुलाये और सुनवाई किए अपील निरस्त कैसे कर सकते है।

तो फाइल बुलाई गई तो मालूम पड़ा कि हरामखोरों जालसाजों ने आवेदन का पत्र ही गायब कर दिया है, ये वही मंडल कार्यालय है और ये वही सब पदोन्नत अधिकारी है जिनकी लड़ाई समय माया ने की थी। सन् 1999 में सभी मंडल कार्यालयों को बंद कर दिया गया था, वहां बैठे जल संसाधन, लो.नि.वि., लो स्वा. या, कृषि, महिला कार्यालयों के अधिकारियों के कहने पर सन् 2004-05 में इनके लिए लिखा गया जब इन्हें 2006 से पुनः अधिकार मिले, क्योंकि जिलों के बाद सीधे मुख्यालय से निराकरण व अन्य कार्यों के लिए जाना व संपर्क करना पड़ता था, फिर जल संसाधन में सामान्य वर्ग के 692 से ज्यादा सहा. यंत्रियों को एक ही पद पर बैठे 30-32 वर्ष हो गये थे, वहां के सहा. यंत्रियों के रोने गाने और कार्य के बदले रुपए 10 हजार देने की बात पर लड़ाई लड़ी गई और छापा गया, मार्च 2009 में छापने के बाद जुलाई 16 में पदोन्नतियां शासन ने की। जब शुल्क चुकाने की बाद उठी तो वे ही सहा. यंत्री जो रोते थे, बत्तमीजी दिखाते हुए बोले कि आपके करने से थोड़े ही कुछ हुआ है। इसके जवाब में जब श्री अजमेरा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो 432 बचे हैं उनकी पदोन्नतियां करवा लेना। उसके बाद सन् 2012 तक कोई पदोन्नतियां नहीं हुई। का.यं. महेन्द्र जैन शाजापुर संभाग जब इतनी छोटी सी जानकारी न देने के लिए, ये जालसाज रुपए 200, 500 के स्थान पर 10 से 20 गुना राशि मांगकर जानकारी न देने के लिए ये जालसाजी कर सकता है तो स्वाभाविक है शासन के धन को कितना और कैसे पिछले 25-30 वर्षों में हड़पा होगा, चूंकि इसका इतिहास मालूम नहीं किया जा सका, शायद इसी कारण इसका शाजापुर से स्थानांतरण किया गया, तो बंदा तत्काल उच्च न्यायालय से स्थगन ले आया कहां ये इंदौर से जाने को तैयार नहीं था, ज्यादा होशियारी दिखाने पर, मुख्य अभि. कार्यालय इंदौर से इसे शाजापुर भेजा गया था, चूंकि वहां बड़ी परियोजना आने और मोटा करोड़ों रुपए में धन हड़पने और भ्रष्टाचार से मोटी कमाई के आसार दिखे तो अब जाने को तैयार नहीं, जबकि मु.अभि. कार्यालय इंदौर में संलग्न करने का कारण भी भ्रष्टाचार था, प्र.स. जुलानिया 6 वर्ष जल संसाधन विभाग में रहे, कार्य में कसावट लाये, परंतु कई भ्रष्ट जालसाजों को टस से मस नहीं कर पाये, जिसमें एक है खरगोन सं. का पूर्व का.यं. भगोरा और वर्तमान में भी वही का.अ.य. है। 1992 में सहा.य. के पद पर पदस्थ किए जाने के बाद से 24 वर्ष गुजर जाने के बाद भी खरगोन में ही है, अपने सहा.यं. के कार्यकाल में भी कोई भी कार्य स्तर से पूरा करवाने की तो दूर का.यं. खरगोन रहते हुए भी करोड़ों के ठेके दिए गए। ठेकेदार के साथ मिलकर आधे अधूरे कार्यों के भी दुगुने भुगतान करवाकर कार्य बंद करवाकर नई निविदायें बुलवाकर फिर कार्य शुरू करवाने का ये सिद्धहस्त रहा है। म.प्र. अंकेक्षण महानिदेशक की रिपोर्ट में इन तथ्यों को उठाया गया उस पर रिपोर्ट को मोटा धन खर्च कर दबा दिया गया। जुलानिया ने जानने के बाद भी तो इसे हिला नहीं पाया, ऐसे 4-5 कार्यों में इस अ.य. भगोरा ने एक ही कार्यों के 4-5 बार नये सिरे से टेंडर लगाकर धन हजम किया। इंदौर नर्मदा ताप्ती कछार के मु.अ. कार्यालय में पुनः संविदा पर पदस्थ एसके पंवार को न हिन्दी लिखते बनती है, न ढंग से इंग्लिश कानूनी सलाहकार के पद पर अवैध नियुक्ति दी जाकर उसे रुपए 10 हजार प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है, जबकि ऐसे भुगतान करते समय जो पेंशन मिलती है उसमें से रुपए 10 हजार का कटोत्रा होना चाहिए,जो कि अभी तक डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं हुआ है। नये प्र.स. पंकज अग्रवाल को इसमें जांच करवानी चाहिए। प्र.सं. पंकज अग्रवाल को शीघ्र ही कर संभाग में लागत के विपरीत नये जल स्त्रोतों को विकसित कर वर्षा का पानी सहेजने के लिए जिस दर से जमीनों के क्रय-विक्रय में सरकार मुद्रांक शुल्क देती है उसी दर पर भूमि के मुआवजे का भुगतान कर जमीनें अधिग्रहित कर पुराने बनाये व रखे हुए डीपीआर को संशोधित कार्य करवाने चाहिए।

मु.मं. कुर्सी बचाने कर रहे जन-धन के अरबों रुपए बर्बाद

मप्र की शिवराज की भ्रष्ट सरकार के व्यापम, खाद्यान्न घोटाला, महिला बाल विकास कृषि आदिम जाति, खनन, उद्यानिकी स्वास्थ्य जैसे हजारों भ्रष्टाचार के कांडों से भरी है। इसलिए एक तरफ मु.मं. शिवराज विक्रय कर राजस्व से प्राप्त आय का 80 प्रश पैसा मीडिया पर खर्च कर सबका मुंह बंद करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बार-बार बहाने ढूंढकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में लाकर जन-धन का हजारों करोड़ बर्बादकर अपनी कुर्सी बचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। बदले में सरकारी कर्मचारियों को वेतन बांटने के लिए पिछले 7 माह में बाजार से 6वीं बार जनता के सीने पर ऋण पर ऋण लिये जा रहे हैं। अपनी जांचों को रूकवाने सीबीआई अधिकारियों को मोटा महीना बांटकर जांचों के कार्यों को कछुए की चाल से आगे बढ़वा रहे हैं ताकि कुर्सी सलामत रहे।

लोक परिवहन में भी इस धूर्त को केन्द्र और सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार कहने और लिखने पर भी इसने पुनः मप्र राज्य परिवहन निगम को पुनः जीवित नहीं किया, क्योंकि सभी राजनीतिज्ञों की बसें और फिर लाखों रुपए में बिकने वाले परमिटों से मोटी कमाई के साथ हजारों करोड़ जेएनआरयूएस में पूरे प्रदेश में खरीदी बसों, इंदौर भोपाल में बनाये गये बीआरटीएस और उस पर चलने वाली सैकड़ों करोड़ हजम करने में बनाई गई हर महानगर की अपनी शासकीय कं. में लूटमार कर खाने की व्यवस्था के चलते इस महाधूर्त ने राज्य परिवहन निगम को कभी पुर्नजीवित करने के लिए कोई सार्थक प्रयास की तो दूर उल्टे ही उस निगम के डिपो की जमीनों को बिकवाकर उन जमीनों में से भी धन हड़पने की जुगाड़ में संबंधित कलेक्टर कमिश्नर, प्र.सं., मु.स. लगे हुये हैं।

बदले में हर माह एक दो बसें दुर्घटना का शिकार हो सैकड़ों की जानें ले चुकी है। बस ये शूकर तो केवल मुआवजे की घोषणा कर अपने अधिकारों को इतिश्री कर लेता है। जांच आयोग केवल मामले को ठंडा करने के लिए बनाये जाते हैं। चल रहे हैं। पचासों जांच आयोग चल रहे हैं, समय माया 17 वर्ष से चीन और उसके उत्पादों के विरूद्ध लिख रहा है, परंतु मुख्यमंत्री का चीन प्रेम जगजाहिर है। कैसे शत्रु को ये राष्ट्रद्रोही अपने प्रदेश में कालोनी की जमीन देकर पूरी बस्ती पीथमपुर में बसा देने के लिए पिछले 5-7 वर्षों से बेताब है। पीथमपुर में चीनी बस्ती बसाने का सीधा अर्थ है पश्चिम में सरदार सरोवर और पीथमपुर के पास औंकारेश्वर, महेश्वर व इंदिरा सागर बांधों के बीच शत्रु को स्थापित कर प्रदेश के जन-धन की बर्बादी की आधारशिला रखना, समय माया के 17 वर्षों से लिखने के बाद भी ये मक्कार ठग मानने को तैयार नहीं।

लो.नि.वि. में मंडल और उपखंड कार्यालय बंद करने को तैयार

म.प्र.क्षे.ग्रा. सड़क वि.प्रा. करो बंद-निर्माण कार्य पूरा

40 हजार किमी से ज्यादा सड़कें सौंपी जाए लो.नि.वि.को., सारे कर्मचारी अधिकारी व इंजिनियरों को हस्तांतरित करो, उनके मूल विभाग में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास का कार्य पूरा, केन्द्र से पैसा लेने अस्तित्व बचाया जा रहा

राष्ट्र के विकास में सड़कों का विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस बात को ध्यान में रखकर ही पं. अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल में भारत के ग्रामीणों के विकास के लिंए जो उत्कृष्ट योजना ग्रामीण भारत की सड़कों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की शुरू की थी, निःसंदेह उसके बेहतर परिणाम न केवल सामने आये वरन भारत के गांवों की भाग्य रेखा को बदलकर ग्रामीणों के विकास, उनके बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य, उनकी उत्पादित फसलों को भी उत्कृष्ट बाजार उपलब्ध करवाया, मप्र में उस समय की तत्कालीन दिग्गी सरकार ने इस कार्य की रूपरेखा को समझकर उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए मप्र क्षेत्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सरंचना कर उसमें विभिन्न विभागों के सिविल इंजिनियरों जिसमें मप्र लो.न.वि., मप्रलो.स्वा.यां, मप्र जल संसाधन विभाग, म.प्र.वि.म., मप्र ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के इंजिनियरों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाकर इस महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए गठन किया था, जिसके बेहतरे परिणामों के साथ यथार्थ में भाजपा को ग्रामीण भारत में पैर जमाने और वोट हथियाने में सफलता मिली, जबकि प्र.म.ग्रा.स.यो. का यही कार्य असम, आंध्रा व अनेकों राज्यों में लोक निर्माण विभाग को ही दिया गया था।

इस प्राधिकरण का मूल उद्देश्य था, पहले चरण में 2000 से ज्यादा की आबादी को, दूसरे चरण में 1000 से ज्यादा की आबादी की, तीसरे चरण में 750 की और चौथे चरण में 500 से ज्यादा की आबादी के गांवों से भी मौसम में आवागमन की सुविधा देने जिला मुख्यालय, संभागीय, राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों से जोड़कर वर्षभर सुचारू यातायात हेतु सड़कों का निर्माण करना था, इस प्रकार पहले 15000 किमी फिर 25000 किमी और अंत में इस प्राधिकरण 40000 किमी से ज्यादा सड़कों के निर्माण के साथ इन 15 वर्षों में निर्मित सड़कों के रखरखाव भी किया, अब जबकि इसके गठन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो इसके भंगकर दिया जाना चाहिए। ताकि इस पर आ रही अतिरिक्त लागत, खर्चों और वेतन भत्तों के भार के साथ ही प्रतिनियुक्ति पर आए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, इंजिनियरों को उनके विभागों में भेजकर सभी विभागों में कर्मचारियों के घोर अभाव को कम किया जा सके, हालात ये है कि स्टॉफ की कमी के चलते मप्र लो.नि.वि.वित्र के मंडल और उपसंभागीय कार्यालयों को बंद करने की तैयारी चल रही है। जबकि दोनों ही प्रकार के कार्यालयों की आवश्यकता है, फिर 40000 किमी से ज्यादा सड़कों लो.नि.वि. को स्थानांतरित करने से तहसील, जिला मुख्यालयों में चल रहे 60 से ज्यादा प्रकार के शासकीय कार्यालयों, स्कूलों चिकित्सालयों, न्यायालयों के भवनों के साथ स्टॉफ के आवासीय भवनों की देखरेख के साथ सड़क के रखरखाव के कार्यालयों को भी संपन्न करवाया जा सकेगा, जहां तक म.प्र.क्षे.ग्रा. सड़क प्राधिकरण का सवाल है, तो उसे अभी नहीं तो आने वाले वर्षों में भंग करना ही पड़ेगा, वास्तविकता में लो.नि.वि. को उपयंत्रियों और सहायक यंत्रियों की तत्काल भर्ती करना चाहिए, औश्र मंडल कार्यालय व उपखंडों के कार्यालयों को बंद करने की अपेक्षा विकास खंड स्तर पर भी एक उपयंत्री का कार्यालय खोलना चाहिए, ताकि उस विकासखंड के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों के भवनों के साथ 20-30 स्कूल छात्रावास भवनों 5-7 प्रा. चिकित्सा केन्द्रों, 25-50 किमी सड़कों की मरम्मत, रखरखाव आदि के कार्यों को देखने के लिए आवश्यक है। वर्तमान में क्षे.ग्रा.सड़क विकास प्राधिकरण की समाप्ति पर जो कि अभी केवल सड़कों का कार्य कर रहा है। कार्यों को देखने के लिए आवश्यक है। इसके उपयंत्री और सहा. यंत्री, का.यं. 20 प्रश रिक्त स्टॉफ को भी पूरा नहीं कर पायेंगे, बेशक इस प्राधिकरण में अनुमति का कुनबा जोड़कर ही कार्य चलाया जा रहा है। प्र.मं. ग्रा. सड़क योजना से धन झटका जा रहा है, ताकि ग्रामीण सड़कों का बोझ सरकार को न उठाना पड़े।

बकवास मंत्री, लुटेरा प्र.सं6, हत्याओं का आरोपी प्र.अ., बाकी का अंदाज लगा सकते हैं

जनधन पानी की तरह बहा-गंदे पेयजल की आपूर्ति- लो.स्वा. यांत्रिकीय विभाग

इंदौर में नर्मदा के सं.क्रं. 1 व 2 हर वर्ष रुपए 8-10 करोड़ हजम करते हैं। केन्द्र व राज्य का पेयजल के नाम रुपए 5 से 8 हजार करोड़ रु. में से रु. 3000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने का, यं. हरामखोरों ने जवाब तक देना बंद कर दिया, अधीक्षण यंत्री रत्नावत उज्जैन, मिश्रा इंदौर वृत्त, पी.सी.जैन तीनों अपने का.यं. से मोटा धन हजमकर जालसाज सारी अपीले रद्द कर देते है

म.प्र.लो.स्वा. यांत्रिकीय विभाग में मंत्री कुसुम महदेले की बत्तमीजियों और गुरूर के किस्से देश के और प्रदेश के प्रसार माध्यमों में खूब सुर्खियां बटोरने के बाद भी वह मंत्री है, जिसका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार से धन बटोरता है, महीनो फाइलें सड़ती रहती है। फिर जैसा धूर्त और भ्रष्ट मक्कारों, जिसमें प्र.स. पंकज अग्रवाल उस पर 6 हत्याओं का आरोपी जिस पर अनेकों लोकायुक्त जांचें लंबित होने के बाद भी जिसके पास धार, झाबुआ, बड़वानी, इंदौर, भोपाल में अरबों की संपत्ति जिसमें पेट्रोल पंप, शॉपिंग कॉम्पलेक्स होने के बाद भी आय से अधिक संपत्तियों के मामले में न तो लोकायुक्त छापे डालता है और न ही आयकर विभाग। वर्तमान में ऐसा अपराधी डामोर प्रमुख अभियंता के प्रभार मे है। तो स्वाभाविक है, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, का.यं., सहा.यंत्री, उपयंत्री,भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगायेंगे, अभी हाल ही में संपन्न हुए सिंहस्थ में भी अरबों रुपए की खरीदी और कार्यों में लूटपाट की गई थी, 23 मई को सिंहस्थ की समाप्ति के बाद सामान समेटने की कार्रवाई चल रही थी, इस बीच प्र.स. पंकज अग्रवाल ने भ्रष्टाचार से धन लूटने के लिए उज्जैन के संभागों को संपन्न किए जा चुके कार्यों का और खरीदी का रिवाइज इस्टीमेट बनाकर देने को कहा गया ताकि 1-2 अरब की चपत लगाकर धन हड़पा जा सके, यहां पर जानकारी प्राप्त करने सूचना अधिकार का आवेदन दिया गया, तीनों संभागों को उज्जैन सिंहस्थ व उज्जैन नगर निगम संभाग को, हरामखोर धूर्तो की फौज ने या तो जवाब ही नहीं दिये और उज्जैन के का.यं. ने रुपए 4500 की राशि के साथ ही बिना दस्तावेजों की गिनती किए रुपए 7000 से ज्यादा मांगे, जब अपील की गई तो वहां बैठे धूर्त अ.यं. रत्नावत जो कि पूर्व में परियोजना तृतीय चरण इंदौर में पनामा लीक में लपेटे में आये प्रभात सांखला के साथ था, स्वाभाविक था सिंहस्थ में भी बंदे ने 5 प्रतिशत कमीशन जो कि करोड़ों में था हड़पा, तो कैसे ये जालसाज अपने मातहतों की जानकारी दे, इसलिए हरामखोर एक मुस्त सारी अपीले रद्द कर दी। जबकि का.यं. उदिया पूर्व से ही अपनी तानाशाही और मनमर्जी से धन हड़पने के लिए कुख्यात है, इसलिये सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर 10 से 25 गुना तक ज्यादा की राशि मांगकर जानबूझकर अपील में जाना पसंद कर, अधीक्षण यंत्रियों पैसे देकर रद्द करवा देता है। दूसरी ओर सिंहस्थ संभाग का का.यं. धर्मेन्द्र वर्मा तो धन देकर ही सिंहस्थ से में आया था, भ्रष्टाचार का धन लुटाकर, लूटने, इसलिए निविदाये जारी किये जाने से लेकर बिल भुगतान तक फिर अरबों की खरीदी पाइप, टंकियां, पंप से लेकर टोटिंया तक जिसमें आधा इंच से लेकर 5 इंच के प्लास्टिक के हजारों मीटर पाइप खरीदी में, फिर लोहे के पाइपों में व अन्य खरीदी 10 से 25 प्रतिशत तक तो 20 प्रश खरीदी के झूठे बिल भी आराम से भुगतान कर ठेकेदारों के साथ हड़पे गए, बड़े ठेकों में प्रभारी मंत्री भूपेन्द्र सिंग ने सीधे 20 प्रश रखवाने के बाद ही ठेके के कार्यादेश जारी करवाये, जबकि 4 क्षेत्रों में बनाए 73000 शौचालयों, स्नानागरों में से मात्र 30000 ही बनाए गए बाकि सब के माल की खरीदी निर्माण, जलापूर्ति की टोंटियों, पाइपों, विद्युत मोटर पंपों का पैसा हजम कर लिया गया। चूंकि पैसा मु.मं. और भारत के गृहमंत्री व अमित शाह तक भी पहुंचा इसलिए कोई जांच नहीं, कोई निलंबन नहीं, यही कारण था कि गिद्धों की फौज जानकारी देने में भी, कानून को बाप की जागीर मान साफ मनाकर देती है। क्योंकि सबने धन दोनों हाथों में बटोरा। बदले में जनता से धन लूटने के लिए भारीकर, पेट्रोल डीजल की तिगुनी कीमत पर भी 72 प्रतिशत कर लादकर जनता को नोंचा जा रहा है।

यही हाल इंदौर के ही नगर निगम के दो संभागों में जलापूर्ति के नाम पर होता है, फर्जी देयकों से जो कि पंपों की मरम्मत, लाइनों की मरम्मत, टनों से फिटकरी, क्लोरीने की खरीदी पर करोड़ों रुपए बर्बाद करने बाद भी जनता को पानी गंदा पिलाया जाता है। क्योंकि पानी साफ करने में काम आने वाले रसायनों यथा ब्लीचिंग, क्लोरीन, फिटकरी की खरीद के तो पूरे बिल लगाये जाते हैं, परंतु 25 से 40 प्रश माल कम आता है।

बेशक 1970-71 की डाली गई लाइनें पुरानी, प्रथम चरण की है। परंतु लाइनों का फूटना, विभागीय वर्षों से बैठे इंजिनियरों का स्वयं की ठेकेदारी करना और विभागीय मस्टर के दैनिक वेतन भोगीयों से कार्य करवाकर 50 प्रश से 200 प्रश तक के बिल बनाकर दूसरे ठेकेदारों के नाम से बिलों के भुगतान लेकर भारी भ्रष्टाचार से करोड़ों की कमाई का खेल पिछले 25-30 वर्षों से पुरानी लाइनों के दम पर ही तो चल रहा है, फिर इस कमाई में न केवल निगम के दो संभागों के इंजीनियरों के साथ निगमायुक्त व संभागीय आयुक्त भी तो हिस्सेदारी करते हैं। जो स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसलिए दोनों संभागों के भ्रष्ट शूकर न तो स्वयं जानकारी देता है, हरामखोर न ही अपीलों पर ढंग से कार्यवाही करता है। हाल ही में 2 सितम्बर 16 को दोनों संभागों के कार्यपालन यंत्रियों कुरील और श्रीवास्तव के विरूद्ध सुनवाई होना थी,1 सितम्बर को फोन करके कहा गया कि यह सुनवाई 17.09.16 को रखी गई है, क्योंकि साहब बाहर जा रहे हैं। यह सुनाकर आवेदन गया नहीं, तो बिना अपीलों को पढ़े ही दोनों अपीलें रद्द कर दी, जबकि कानून स्पष्ट रूप से कहता है, कि अपीलार्थी हो न हो,आपको दस्तावेजों पर निर्णय देना है, लाखों रुपए महीना डकारने वाला ये अ.यं. पीसी जैन जो धन देकर के यहां आया है, कैसे अपने जालसाज अधीनस्थों की जानकारी दूसरे के हाथ में जाने दे, फिर कानून इनके बाप की जागीर है। जैसे नचायेंगे वैसा नाचेंगे।

यही हाल अ.यं. मिश्रा का भी है। वह भी अपने अधीनस्थ 8 संभागों से मोटा धन वसूलता है, तो श्वान टुकड़े डालने वालों की वफादारी निभाते हुये, सारी अपीलें किसी न किसी तरीकें से रद्द कर देता है, अपने अधीनस्थों की जानकारी से इसके कार्यालय से संबंधित होती है उसे न तो खुद देता है न ही महीना खाने वाला ये टुकड़खोर और वर्षों से वहां कुंडली मारे बैठा गोयल उसे धारा 6 (3) में अंतरित करता है। इन सबका स्थानांतरण किया जाना चाहिए, जो वर्षों से कुंडली मारे चारों तरफ नोंच-खसोंट में लगे हैं। पर चारों तरफ टुकड़खोर, रिश्वतखोर श्वानों की बाबु उपयंत्री से लेकर मंत्री, प्र.सचिव तक तो कौन निवाला छोड़ना चाहेगा।, जबकि मु.अ. सोनगारिया को का.यं. श्रीवास्तव ग्रामीण, अंयं. मिश्रा, धार का राजीव खुराना, देवास का रोतला राजु, पूरे मप्र में 20 से ज्यादा का.यं., सहा. यंत्रीयों जो 50 से ज्यादा है का शीघ्र स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार और लूट के तांडव की जड़ें ज्यादा गहराई तक न जा सके, बेशक स्थानांतरण करने और रोकने सबमें मोटा पैसे का खेल होता है।

रिजर्व बैंक नहीं रिलायंस बैंक ऑफ इंडिया

हमारे राष्ट्र का धूर्त प्रधानमंत्री यथार्थ में अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, विदेशी कं. यथा युनिलीवर, आईटीसी आदि का रखैल प्रधानमंत्री है, देश की रेल भले ही वह तत्काल में अंबानी, अडानी, टाटा व अन्य को नहीं सौंप पाया हो, पर ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बीएसएनएल को कहीं आंशिक तो कहीं पूर्णतः रिलायंस, टाटा के हवाले कर दिया है, या कर रहा है। पर भारतीय रिजर्व बैंक में जरूर मोदी धूर्त ने अंबानी बंधुओं के, कीन्याई नागरिक उर्जित पटेल जो रिश्तें में सगे जीजा है। को गर्वनर के पद पर बैठाकर रिजर्व बैंक जो बैंकरों का बैंक होने के साथ है केन्द्र सरकार के केन्द्रीय बैंक की भूमिका निभाता है। अंबानी बंधुओं का रिलायंस बैंक बना दिया है, अब अंबानी, अडानी टाटा आदि के विभिन्न उद्योगों पर लिये गये विभिन्न बैंकों के लाखों करोड़ जो जनधन हैं धीरे हजम कर लिया जाया जायेगा या जालसाजियों से कर्ज को माफ करवा लिया जायेगा, दूसरी तरफ अपने चार्टड बनाम करप्ट अकाउंटेंट की टीम से संपत्तियों का चौगुना मूल्यांकन कर दोगुना तक और देश की बैंकों से कमीशन बांट लाखों करोड़ का कर्ज ले लिया जावेगा, जब जीजा भये गर्वनर तो रिजर्व बनाम रिलायंस बैंक अपना बैंकर, तो फिर बैंकों को लूट के खाने में कैसा डर। जब चीटंबर वित्त मंत्री था, तो सारे बैंकों के और रिजर्व बैंक के निर्देशक दक्षिण भारतीय थे, तो अब गुजराती मोदी प्रधानमंत्री है, तो सारे उच्च शासकीय पदों पर सारे देशी-विदेशी गुजराती होना ही चाहिए, क़ोई कैसा भी कानून हम बदल देंगे। जैसे उर्जित पटेल को केन्याई नागरिक होने के बाद भी रिजर्व बैंक का गर्वनर बना दिया। रिजर्व बैंक के गर्वनर के लिए नागरिकता की नहीं पावर का दम है।कल को मोदी अपने मित्र ओबामा को अमेरिका के बाद भारत का राष्ट्रपति बना सकते हैं।

आयुर्वेदिक औषधियों में भारी लूट, जांच के लिए प्रयोगशाला भी नहीं

अधिकांश विक्रेता, निर्माता करते हैं आयुर्वेद के नाम पर ठगी

आयुर्वेद औषधियों की शास. प्रयोगशाला जांच हेतु आवश्यक, आयुर्वेद भेषज पाठ्यक्रम की शुरूआत की जाये शीघ्र ही, देशी निर्माताओं और विक्रेताओं पर कसी लगी जाये लगाम, संजीवनी के अधिकारी बना रहे समानांतर आयुर्वेदिक औषधियां

भारत के अनादिकाल में ही देवों ने मनुष्यों के जीवन यापन, सुरक्षित स्वास्थ्य निरोधी जीवन के लिए जिन चार शास्त्रों की रचना की उसमें आयुर्वेद को स्वयं विष्णु अवतार धन्वतीर ने लिखा था, जिसमें मनुष्यों को दीर्घ अवधि की आयु प्राप्त करने और स्वास्थ्य रहने के लिए जो वेद लिखा गया वही आयुर्वेद है।

आयुर्वेद ने वनस्पतियों को औषधि के रूप में ग्रहण करने के लिए विशेष समय, नक्षत्रों की कालावधि, वार, समय आदि में उस पौधे या वृक्ष को उसके एक दिन पूर्व संध्या काल में घर से सामग्री लेकर सूर्यास्त से पहले निमंत्रण देने और विशेष नक्षत्र और वार और सूर्योदय के पूर्व घर से वस्त्रहीन होकर औषधि ग्रहण करने का प्रावधान है। स्वाभाविक है यह प्रक्रिया वानस्पतिक औषधि ग्रहण करने के लिए अब कोई नहीं अपनाता, जिससे वानस्पतिक औषधियों में वह अदृष्य दैविक स्वास्थ्य करने वाली शक्ति उत्पन्न ही नहीं हो पाती, जो दैहिक निरोगिता के लिए परम आवश्यक थी, अब केवल भौतिक शरीर को स्वास्थ्य बनाने के लिए केवल भौतिक औषधियां ही आयुर्वेद विक्रेता चाहे वे पतंजलि के उत्पाद हो या हिमालयन, डाबर, वैद्यनाथ व अन्य लाखों आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं के भारतीय आयुर्वेद औषधि उत्पाद।

भारत ये सहस्त्रों वर्ष पुरानी औषधि पद्धति के उत्पादों की भारत की आजादी के 69 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक इन पदार्थरूपी औषधियों की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई प्रयोगशाला देशभर में कही नहीं हैं साथ ही एलौपैथिक औषधियों की तरह उत्पादन बिक्री, भंडारण के नियमन के लिए औषधि और सौंदर्य प्रशासन अधि. 1940 जैसा आयुर्वेद औषधि अधिनियम भी नहीं है, इसलिए एक छोटी अनुज्ञति के सहारे, उत्पादक प्रसंस्करण, संग्रहण व भंडारण और बिक्री की जा सकती है, जबकि आयुर्वेद औषधियों के लिए जो शास्त्र, वेद, संहितायें, प्राचीन काल से विद्यमान है। वैसी उपचार, निरोगिता और स्वास्थ्य पद्धति विश्व में कहीं भी नहीं है। जिसमें औषधियों के मंत्रो से जागृत कर मनुष्यों की निरोगी बनाने हेतु शक्ति पैदा की जा सकती है। अब इस शक्ति को विश्व की कौन सी प्रयोगशाला नाप सकती है, प्रयोगशाला में भौतिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उन भौतिक तत्वों की मात्रा, मिलावट आदि का यथार्थ जाना जा सकता है।

आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर देशभर के हजारों निर्माता, पैकर्स, विक्रेता चाहे वो पतंजलि के हो या अन्य किसी के उत्पाद, पैकिंग कोई भी विक्रेता शास्त्रोंत पद्धति से ईमानदारी से औषधियों का निर्माण, पैकिंग और बिक्री नहीं करता। यही कारण है कि ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति अपना विश्वास खो रही है।

अकेले इंदौर में कुछ नामीग्रामी दुकानें यथा अखंड औषधि भंडार कपड़ा बाजार, सियागंज वाला मालवा मिल चौराहे के पास इंदौर खुली और पैक दोनों तरह की निम्न से लेकर उच्च स्तरीय औषधि बैचते अवश्य है। परंतु 90 प्रश औषधियों में जो पैकिंग में हो खुली हो। उन औषधियों का ये हरामखोर जालसाज नाम तक ढंग से नहीं लिखते। 90 प्रश औषधियों में नाम के साथ बैच नंबर पैकिंग दिनांक, उपयोग की विधि, किस में उपयोगी है। तक नहीं कुछ भी नहीं होता, स्वाभाविक है गुणवत्ता किन-किन औषधियों तत्वों का मिश्रण है कि कल्पना भी बैकार है, अखंड औषधि भंडार पर तो आलम ये है, कि वहां बैठी स्त्रियां ग्राहकों के साथ भारी बत्तमीजी से पेश आती है, इन सब की पैकिंग के नाम, बैच नंबर आदि के बारे में पूछने पर, महिलाओं ने डांट दिया। कलौंजी का तेल लिया गया, जो बेहद घटिया होने के साथ 3000 रुपए प्रति लीटर था, रुपए 150 का 50 मिली जिसकी शीशी पर कुछ भी नहीं लिखा था। ये हाल आयुर्वेदिक औषधि बैचने वालों का पूरे भारत में है। ये सारे हरामखोर जालसाज आयुर्वेद को भारी बदनाम करते हैं, जो पैकिंग में इन सब दायित्वों का पालन करते हैं।

वे इनके दुगुनी कीमत से 100 गुनी कीमत तक वसूलकर जनता को भारी लूटकर जनता को इस पद्धति से विमुख करने का ही प्रयास कर विश्वास तोड़ते है जनता का, आयुर्वेद विभाग के हरामखोर जालसाज निरीक्षक जो इंदौर में वर्षों से पदस्थ है। अपनी मोटी लाखों रुपए का महीना वसूली से मतलब रहता है, न तो कभी हरामखोर धूर्त इन औषधियों के नमूने लेता है न ही कानूनी कार्रवाई करता है, तो स्वाभाविक ह कि जनता का ये आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता हर तरह से घोर शोषण करते है।

वन विभाग की संजीवनी औषधिशाला में तो वैसे भी कोई पंजीकृत आयुर्वेद औषधि भेषज का कोई न तो पाठ्यक्रम शिक्षित भेषज पदस्थ है, न आयुर्वेद की डिग्रीधारी डॉक्टर फिर पूरे मप्र के वनविभाग के अंतर्गत कार्यरत पूरे मप्र की औषध शालाओं में गिद्धों का जमावड़ा हैं। सारा कार्य मनमर्जी से लूट-खसौट सहारे चलता है। भोपाल में तो वहां पदस्थ कुछ अधिकारियों ने अपना सामानांतर फैक्ट्रियों खोलकर, जंगल से चोरी से इकट्ठी की औषधियों से माल निर्माण कर इन संजीवनी के ठेकेदारों को सौंपकर मोटी कमाई कर रहा हैं ये खेल पूरे मप्र में वन विभाग के कई अधिकारियों की देखरेख में खुले रूप से चल रहा है। कीमती औषधियां बाहर वाले-वाले ही दी जाती है। पैसा हजम कर लिया जाता है।

साप्ताहिक समय माया

धर्म के नाम होता है घोर अधर्मी, आयोजक ही करवाते है रासलीला

गरबों के बाद आती है गर्भपातों की बाढ़

नव., दिस. में हर नर्सिंग होम, चिकित्सालय करते हैं औसत से चौगुने गर्भपात, बड़े समाचार पत्र प्रकाशकों को शामिल कर मुफ्त में प्रचार और अपने स्वच्छंद यौनाचार पर प्रशासन को व नागरिकों को दहशत, ताकि कोई भी महिला छेड़छाड़ या अन्य दुष्कर्मों की शिकायत न करे

पूरे उत्तरी पश्चिमी व पूर्वी भारत जिसमें महाराष्ट्र से लेकर मप्र, छग, उड़ीसा, बंगाल से लेकर उप्र राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड आदि में नवदुर्गा जी के नवरात्रों में आराधना के लिए जो सामूहिक गरबा नृत्य होता है, वह यथार्थ में भक्ति की शक्ति प्रदर्शन की अपेक्षा वृहद स्तर पर माफियाओं के चंगुल में फंसकर धर्म के नाम पर घोर अधर्म, स्वच्छंद यौनाचार का केन्द्र बन चुका है।

यहां तक कि जिस नवरात्रों में दुर्गाजी व अन्य नवदेवियों की आराधना के लिए गरबा किया जाता है। उनमें विशुद्ध भजन व बीच में प्रतिमा या चित्र के चारों तरफ गरबा होना चाहिए, उसका पूर्णतः अभाव होता है। बड़े केन्द्रों पर आयोजक न केवल जिसमें अधिकांश में पिछले कुछ वर्षों से दैनिक समाचार पत्र प्रकाशक जो घोर धन और रस लोलुप्त होते है। न केवल स्वयं सह प्रायोजक वरन उस कार्यक्रम में मोटा पैसा हजम करने के लिए अपने बड़े विज्ञापनदाताओं को भी उनसे मोटी धनराशि, नवयौवनाओं के साथ नृत्य करने, मौज मस्ती करने के नाम पर ऐंठी जाकर न केवल प्रायोजक वरन दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशक भी उनके कुकर्मों में सहभागी होते हैं। पिछले 15-20 साल से ये चलन इस लिये परवान चढ़ा ताकि इन जालसाज माफियाओं के कुकर्मों की जो हर दिन छपाई होकर आपराधिक प्रकरण दर्ज होते थे उनसे भी मुक्ति मिल गई तो दूसरी तरफ महिला प्रतिभागियों को डरा धमकाकर यौनाचार करने के बाद यदि किसी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश भी की तो पुलिस समाचार पत्र की सहभागिता के कारण रिपोर्ट ही नहीं लिखती, साथ ही सबकुछ होता देखकर भी पुलिस स्वयं मूकदर्शक बनी रहती है।

यह सब स्वयं प्रशासनिक अधिकारी तहसीलों, जिलों से लेकर प्रदेश व देश की राजधानी तक सब जानते हैं। समय माया ने जब गरबों के पूर्व इस बात को छापकर आगाह किया था तो शासन ने इस यौनाचार को रोकने की अपेक्षा हर गरबा स्थल पर कंडोम वेडिंग मशीनें लगा दी थी। इस बार भी सीसीटीवी कैमरे लगाने और रिकार्ड रखने की व्यर्थ नौटंकी पूर्ण घोषणा की गई, जिसका कौन मूर्ख होगा जो पालन करेगा, फिर गरबा माफियाओं का तो पावन उद्देश्य की नवयौवनाओं को इस बहाने बुलाकर यौनाचार करते हुये वीडियो बनाना और ऐसी नवयौवनाओं का तन, मन, धन से शोषण करना ही होता है। धर्म की आड़ में चलने वाले इस स्वच्छंदता का हिन्दू संगठनों यथा हिन्दु महासभा,स्वदेशी जागरण मंच, रा.स्व. से संघ द्वारा न केवल पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। एक दो बार 10 बार भी यदि इन कार्यक्रमों के विरोध को लेकर यदि हिन्दू संगठनों को नकारात्मक संदेश इन हिन्दू संघों के हित में जायेगा वो दीर्घकाल में इन माफियाओं के विरूद्ध आंदोलन की नीवं तो रख ही देगा, क्योंकि महाराष्ट्र, मप्र, गुजरात व बंगाल आदि में निजी चिकित्सालयों में नव, दिस, जन, तक इन गरबों के कारण गर्भपातों की जो बाढ़ आती है। उससे न केवल हिन्दू धर्म, नवरात्रि, आराधना की जो निम्न छवि बन रही है। कम से कम न केवल उस छवि और दुष्कर्मों के प्रति आने वाली 25-30 वर्ष की स्त्रियों और पुरूषों में उसके प्रति भय बैठेगा जो इसे रोकेगा। यह तथ्य पिछले 30-40 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन की नजरों में है, परंतु वे ही माफिया जो ये कर्म करवाते हैं। वे ही प्रशासनिकों को हर अधिकारी के राजों के आधार पर उससे भविष्य में सो कार्यो को करवाते रहते है। फिर कौन सा पुलिसिया प्रशासनिक सचिव, जिलाधीश, एडीएम, एसडीएम व तहसीलदार पटवारी सरपंच, सचिव पुलिस कांस्टेबल से लेकर आईजीडीजी, मुफ्त वंदन का तिलक लगाने से कोई नहीं चूकता। फिर नेता, पार्षद, सभी जो महाधर्मी बनते है, सभी मौके की तलाश में शिकार करते हैं, फिर टीवी चैनलों से लेकर मोबाइलों पर नग्र चित्रावली सभी रसास्वरन के लिए बाध्य करती है। स्वाभाविक है तत्काल में सभी मौज के दरिया में डूबकी लगाने के लिए बेताब रहते है। समय माया ने जब इन तथ्यों को प्रकाशित किया तो प्रशासन ने रोकने की अपेक्षा हर बड़े गरबा स्थलों पर कंडोम वेडिंग मशीने लगा दी। अभी भी प्रशासन ने खोखले दावे किए थे कि रात में 10 बजे गरबा कार्यक्रम बंद कर दिए जायेंगे और सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे सब खोखले और अपनी चमड़ी बचाने के लिए ही किये थे। जबकि सच यह है कि यदि कैमरे लगा दिए गये और रात 10बजे ये सब गरबा नृत्य बंद कर दिये गये तो माफियाओं के साथ नेताओं, गुंडो, होटलों की मुफ्त में नवयौवनाओं का भोगन की दुकानदारी कैसे चलेगी, आती रहे गर्भपातों की बाढ़ बेशक हर पुरूष की कहीं बहन बेटी, या अन्य के साथ भी यही सब हुआ होगा।

बंद करो विद्युत कं., जनता को नोंचने का अड्डा

विद्युत के लिए नेता और अधिकारी की लूट और परेशान कर रहे उपभोक्ता को

लो. वक्ता पुत्र महाजनद्वय प्र.सं. व इंजीनियर्स एक तरफ अंट-शंट बिल वसूल ने दूसरी तरफ रखरखाव, नये निर्माण के नाम हजारों करोड़ हजम करते है। क्यों नहीं करवाते एजीका अंकेक्षण, क्यों नहीं मारते छापे लोकायुक्त इन हरामखोरों पर

देशभर में विद्युत मंडलों द्वारा चलाई जा रही अनधीलाभप्रद व्यवस्था को हरामखोर, जालसाज नेताओं और महागिद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों बनाम भारतीय प्रताड़ना सेवा ने जनता को नोंचने, हजारों करोड़ हजम करने के लिए मंडलों को कंपनियों में बदलकर चारों तरफ लूट, डकैती का तांडव मचाकर पूरे देश में हजारों लोगों को अंट-शंट बिल देकर भरने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, लूट और डकैती के इस तांडव में बाहरी सेवायें लेने के नाम पर अजब-गजब तांडव किये, इन तांडवों में हमारे देश की लोकसभा वक्ता के पुत्रों ने अपनी मोटी कमाई के लिए बिलों को बनाने का ठेका प्रति बिल के स्थान पर बिलों को राशि का 1 प्रश भुगतान किया जाता है। मिलिन्द और मंदार महाजन को ये ठेका बिना किसी टेंडर, मंडल से कंपनियां बनाने के बाद ही दे दिया गया, स्वाभाविक है श्रीमती सुमित्रा महाजन के सांसद होने के कारण ही आंख भींचकर दे दिया गया और वह भी प्रति बिल कीमत जो 50 पैसा से ज्यादा नहीं होता था, तो मोटी कमाई और जनता को लूटने के लिए बिलों की राशि को एक प्रतिशत देने के चलते वो हरामखोर जालसाज अधिकतम का बिल बनायेंगे ताकि उन्हें भी अधिकतम राशि में मोटी कमाई मिले, अब यदि पूरे मप्र रुपए 2 लाख करोड़ के बिल बने तो रुपए 2000 करोड़ की कमाई मिलती है। मां के सांसद होने के कारण इन धूर्तों पुत्रों ने यही हाल भारत संचार निगम लि. में भी किया इसी के चलते अकेले मप्र में 25 लाख लैंडलाइन फोन, करवा लिये जनता ने, इनकी बला से बंद करवा लिये जनता ने, इनकी बला से बंद हो जाये। पश्चिम पूर्व और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में इनकी जालसाजियों के चलते अंट-शंट बिलिंग के कारण किसी को दिल का दौरे में मौत हो रही है, तो हजारों आत्महत्या कर रहे है। पर इन राक्षसों को इससे क्या फर्क पड़ता है, उसी धन से इन सपूतों ने सुप्रीम एवियेशन के नाम से हवाई जहाज यात्रा कं. खोलती है। बेशक इन कं. में हर कदम पर लूट का तांडव चल रहा है, जिसमें देश का प्रधानमंत्री, ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, कं. के प्रबंध संचालकों, मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण, संभागीय सहायक उपयंत्रियों, बाबुओं, लाइनमेन, (शेष पृष्ठ 7 पर)

भ्रष्ट धूर्त मु.मं. शिब्बू मामा विदेशों में मनाते रहें मौज, जनता के लूटे धन से

पिछले 10 वर्षों में 380 उद्योग बंद 14 खुले- निवेश आयोजनों में अरबों फूंके

कृषकों की 71000 एकड़ भूमि छीनी, शासन की श्रम और लघु उद्योग विरोधी नीतियां, उद्योग विकास निगमों में बैठे धूर्त, भ्रष्ट, मक्कारों की फौज, आयोजनों के नाम पर रुपए 20 से 30 करोड़ डकार जाती है, फिर भू-अधिग्रहण के बाद आंवटन शर्तों, सेवाओं, सड़कों, बिजली, पानी, करों की छूट के नाम पर यहां के श्वानों की फौज, उद्योगपतियों को उद्योग बंद करने पर मजबूर कर देती है। चीनी माल के आयात को रोके बिना देश में औद्योगिक विकास संभव ही नहीं, इसी कारण हजारों छोटे व सैकड़ों, बड़े उद्योग बंद हो रहे और लाखों को बेरोजगार कर रहे है। बकवास और लूट का साधन है, निवेश आयोजन, यदि उद्योग शुरू होते तो आसानी से काला धन सफेद कर लेते राजनेता व अधिकारी।

मप्र का मु.मं. शिवराज अपनी मौज, मस्ती और भ्रष्टाचार से जनता से लूट गये करों की कैसे चारों तरफ बर्बादी कर स्वयं भी लूट रहा है और अपने भ्रष्ट मंत्रियों सचिवों अधिकारियों, इंजिनियरों, डॉक्टरों से लेकर नीचे बाबुओं तक सचिवों के माध्यम से लुटवा रहा है। जनता ने 10-12 वर्षों के प्रशासन में अच्छी तरह देख लिया है इसलिए भ्रष्टों को पालना, फंस जाने पर कानूनी कार्रवाई से बचाना, भ्रष्टाचार में मोटा हिस्सा मिलने पर उन्हें पुरस्कृत करना, पिछले 10 वर्षों से ज्यादा समय में हुई हर निवेश को मिलाप आयोजनों में यही हुआ, जिसमें केवल मप्र के सभी औद्योगिक केन्द्रीय विकास निगमों में बैठे प्र.सं, महा प्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, सहा. महाप्रबंधको से लेकर नीचे बाबू-चपरासी का.यं., सहा. यंत्रियों उपयंत्रियों से लेकर इंदौर में लंबे समय से कुंडली मार बैठा महाजालसाज गेठेवाला जिसके पास रुपए 1 अरब से ज्यादा की संपत्ति है। जालसाजी और भ्रष्टाचार से लेखाधिकारी बना बैठा है, एक बार ग्वालियर स्थानांतरित किया गया था, पर दोनों हाथ से लूटा एक हाथ से लुटाकर लौट आया, यही हाल न केवल इंदौर में बैठे धूर्त प्रबंध संचालक महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों, सहा. महाप्रबंधकों, प्रबंधकों, सहा. प्रबंधकों तक पूरे प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर आदि से लेकर राज्य औद्योगिक विकास निगम तक है। ये हरामखोर धूर्त, मक्कारों की फौज उद्योगपतियों को न केवल वसूली के लिए भारी प्रताड़ित करती है, वरन् अपने भ्रष्टाचार के लिए नल, बिजली, सड़कों, सुरक्षा आदि के नाम पर आधारभूत सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराती और कराती है तो पहले व्यक्तिगत वसूली के लिए सोदेबाजी करती है आवश्यक यह है कि वर्षों से जमे इन धूर्तों की फौज को तत्काल इनके मूल विभागों में भेजे और नए कर्मचारी, अधिकारी बैठायें और जो पुराने जमे है वर्षों से उनकी संपत्तियों की जांच करवाये, ताकि नए उद्योगपतियों को हत्सोहित करने की अपेक्षा उन्हें तत्काल सुविधायें प्रदान कर उद्योग लगाने के लिए मित्रवत वातावरण महसूस करें और राष्ट्रोन्नति में सहायक बन उत्पादन पर ध्यान दे सकें।

इसके विपरीत मु.मं. शिवराज चौहान और प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि इन निवेशक मिलाप कार्यक्रमों और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले देशी उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले चीनी माल की अविश्वसनीयता के आधार पर जनता में नफरत पैदा करें, ताकि चीन माल के आयात को रोका जा सके और देश में भारत में बने माल को विश्वसमीयता को स्थापित कर माल की मांग उत्पन्न करें, मांग होती तो आपूर्ति की व्यवस्था में स्वयं ही सैकड़ों उत्पादनकर्ता बिना निवेशक मिलन आयोजनों के भी खड़े होकर उद्योग लगाने की पहल करेंगे, फिर बिना शासकीय सुविधाओं के भी उत्पादन बढ़ने लगेगा।

भारत के बाजारों में चीनी माल के स्तरहीन और अविश्वसनीयता के बाद भी चीनी माल ने सस्ते होने की आड़ में कब्जा जमा रखा है, पिछले 16 वर्षों में पूरे देश में लगभग छोटे-बड़े 1 लाख से अधिक उद्योग धंधों जिसमें पटाखों, राखी, गणेशजी की, लक्ष्मी की प्रतिमाओं को बनाने से लेकर विद्युत, औषधियां, कपड़े, तैयार वस्त्र इलेक्ट्रानिक्स के हजारों छोटे-बड़े सामानों, घरेलु उपयोग की वस्तुओं यथा टीवी, कम्प्युटर, बल्बों, प्रशीतक, वस्त्र धुलाई मशीनों, मोबाइल आदि तक के अन्य सैकड़ों सामान के भारतीय औद्योगिक घरेलु, लघु, मध्यम वृत्त आकारों के उद्योगों के बंद होने से करोड़ों के बेरोजगार कर दिया, हजारों करोड़ के आयकर, बिक्रीकर की हानि हुई, सरकार ये तथ्य जानने के बाद भी चीनी आयात को हतोत्साहित नहीं करवा रही, वह तो उल्टे ही औद्योगिकी निवेश मिलाप आयोजनों का व्यर्थ हथकंडा अपनाकर, मु.मं. शिवराज अपनी कुर्सी बचा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा जनता से करों में वसूली गई रकम से होली खेलकर बार-बार मोदी को इंदौर बुलाकर आर्शीवार्द लेकर अपने कुकर्मों यथा व्यापम कांड, राघवजी कांड, डंपर कांड, सिंहस्थ में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार को दबाकर अपनी काली कमाई कर बच रहा है। इसकी आड़ में पूरे मप्र के औद्योगिक, केन्द्रीय विकास निगमों के माध्यम से जो किसानों की 71000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में ही हजारों करोड़ के भुगतान में सैकड़ों करोड़ ये शूकरों की फौज हजम कर गई, फिर अकेले इंदौर में ही ब्रिलियंट कंवेशन सेंटर के किराये में इन हरामखोर शूकरों ने रुपए 15 लाख प्रतिदिन ज्यादा देकर हजम किया, (शेष पृष्ठ 9 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569